सौर ऊर्जा में वृद्धि

वर्तमान वर्ष के पहले तीन महीनों में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 9.7 गीगावाट की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जो 2023 में जनवरी से मार्च तक की अवधि में हुई वृद्धि से 414 प्रतिशत अधिक है. इस साल जनवरी से मार्च के बीच देश में 15.2 गीगावाट नयी ऊर्जा क्षमता जोड़ी गयी है, जिसमें सौर ऊर्जा का हिस्सा 66 प्रतिशत है. अब देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 82 गीगावाट हो गयी है. स्वच्छ ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 43 प्रतिशत हो चुकी है. कुल ऊर्जा क्षमता में इसका हिस्सा बढ़कर 18.5 प्रतिशत हो गया है. उल्लेखनीय है कि ये आंकड़े बड़े पैमाने पर लगाये गये संयंत्रों की क्षमता के है. इनमें व्यक्तिगत स्तर पर लोगों द्वारा अपने घरों पर लगाये जा रहे सौर पैनलों की उत्पादन क्षमता शामिल नहीं है. ये आंकड़े इंगित करते हैं कि स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन और उपभोग को बढ़ाने का भारत का संकल्प उल्लेखनीय गति से साकार होने की ओर अग्रसर है. भारत सरकार ने 2030 तक बिजली उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों, यानी स्वच्छ ऊर्जा के योगदान को 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया था. वर्ष 2021 के जलवायु सम्मेलन में भारत ने कहा था कि देश में 2030 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन होने लगेगा, जिससे एक अरब टन तक उत्सर्जन में कमी आ सकती है. स्पष्ट है कि ऐसे लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में हमारी प्रगति बहुत उत्साहजनक है. उल्लेखनीय है कि लगभग छह दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिजली उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से नीचे आयी है. धरती के तापमान को नियंत्रित रखने तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उत्सर्जन घटाना और इस सदी के अंत तक उसे शून्य के स्तर पर लाना बहुत आवश्यक है. ऐसा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में निरंतर तीव्र वृद्धि के लिए प्रयास किये जाने चाहिए. भारत इसमें गिने-चुने अग्रणी देशों में शामिल हो चुका है. स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर चौथे, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में चौथे तथा सौर ऊर्जा के मामले में पांचवें स्थान पर है. स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए जहां आम लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा घरों में सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए सहयोग मुहैया कराया जा रहा है, वहीं व्यापक उत्पादन के लिए बड़े-बड़े संयंत्र भी लगाये जा रहे हैं. स्वच्छ ऊर्जा में वृद्धि के साथ इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं. साल 2020-21 की तुलना में 2021-22 में इस क्षेत्र में आठ गुना अधिक रोजगार सृजन हुआ था. इस क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग और प्रशिक्षण को अधिक गति देने की आवश्यकता है.

स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर चौथे, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में चौथे तथा सौर ऊर्जा के मामले में पांचवें स्थान पर है.

गंगा से कावेरी तक दक्षिण की चुनावी यात्रा

मधुरेंद्र सिन्हा
वरिष्ठ टिप्पणीकार
madhurendra.sinha6@gmail.com

ओडिशा भगवान जगन्नाथ की धरती है और वहां बीजू जनता दल (बीजेडी) के नवीन बाबू 2000 से ही सत्ता पर काबिज हैं. उल्लेखनीय है कि इसकी शुरुआत उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर की थी, लेकिन बाद में दोनों एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हो गये. साल 2009 में नवीन बाबू की पार्टी भाजपा से दूर हो गयी और दोनों परस्पर विरोधी हो गये. ओडिशा एक ऐसा राज्य है, जहां विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव साथ-साथ होते हैं. इस बार भाजपा की नजरें विधानसभा पर भी हैं.

भारतीय जनता पार्टी के आलोचक उसे 'काऊ बेल्ट' की पार्टी कहकर उपहास करते रहे हैं. साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी एक लहर के साथ केंद्रीय राजनीति में आये, तो भी देश के दक्षिणी हिस्से (कर्नाटक छोड़कर) में भाजपा लगभग अनुपस्थित थी. साल 2019 में पार्टी दुबारा सत्ता में आयी, लेकिन उसने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की अपनी थोड़ी सी सीटें भी गंवा दी. केरल में पार्टी का खाता पहले की ही तरह नहीं खुला. इन अनुभवों से सबक लेते हुए भाजपा ने जोरदार तैयारी शुरू कर दी. अध्यक्ष पद से हटने के बाद भी गृह मंत्री अमित शाह ने, जिन्हें संगठन का गहरा अनुभव है, दक्षिण में अपने पैर मजबूत करने शुरू कर दिये. इस दिशा में उन्होंने तमिलनाडु में पूर्व पुलिस अधिकारी कुपुसामी अन्नामलाई को राज्य इकाई का अध्यक्ष बनाया. हालांकि सहयोगी पार्टी अन्ना द्रमुक ने उनका विरोध किया फिर भी गृह मंत्री झुके नहीं और उसके बाद जो हुआ, उसे सबने देखा. भाजपा ने तमिलनाडु में एक तूफान ला दिया और द्रमुक को जवाब देने पर मजबूर कर दिया. तमिलनाडु, जहां लोकसभा की 39 सीटें हैं, में इस बार पार्टी की शक्ति साफ दिखी. रणनीति बनाने में सिद्धहस्त अमित शाह ने अन्नामलाई को पूरी आजादी दी, जिसका नतीजा था कि वहां प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी दौरा अब तक का सबसे प्रभावशाली था. पूरे राज्य में भाजपा की उपस्थिति साफ दिखने लगी और चुनाव में इसका असर पड़ा. इसके पहले राम मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा के दौरान जिस तरह से तमिलनाडु को महत्व दिया गया, वह वहां के लोगों को खूब भाया.

आंध्र प्रदेश में भी पार्टी ने नये सिरे से पार्टी को संगठित किया और राजनीति के पुराने खिलाड़ी चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ ले लिया. साथ ही, जनसेना पार्टी के पवन कल्याण को भी अपना सहयोगी बनाया. यह एक रणनीतिक फैसला था, जिसके दूरगामी प्रभाव होंगे. इस गठबंधन ने मुख्यमंत्री जगन रेड्डी को हिलाकर रख दिया और उन्होंने जनता के लिए सरकारी खजाना खोल दिया. अब वहां कांटे की लड़ाई है, जिसका परिणाम न केवल इस चुनाव परिणाम में दिखाई देगा, बल्कि आने वाले समय में भी दिखाई देगा. तेलंगाना में भी पार्टी ने बहुत जोर लगाया है, जिसे देखते हुए चुनाव विश्लेषक प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर पार्टी तेलंगाना में पहले या दूसरे स्थान पर रहेगी, तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा. भाजपा उम्मीदवार माधवी लता ने हैदराबाद में सनसनी फैला दी है और ओवैसी बंधुओं की नींद उड़ा दी है. पार्टी ने दक्षिण भारत के लिए इस बार ठोस रणनीति बनायी और उसे कार्यान्वित भी किया. हर राज्य में स्थानीय नेताओं को पूरा महत्व देकर उन्हें संसाधनों के साथ आगे बढ़ाया गया, जो कारगर रहा. केरल में भी एनडीए को बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है. इस कारण कहा जा रहा था कि इस बार न केवल हिंदू वोटर, बल्कि ईसाई भी उसे वोट देंगे. पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी के पुत्र अनिल एंटनी के भाजपा में शामिल होने से स्थिति में बदलाव हुआ है. कांग्रेस के कमजोर पड़ने का फायदा भी उसे साफ तौर पर मिलता दिख रहा है. भाजपा के केरल इकाई के अध्यक्ष के सुरेंद्रन अमित शाह की बनायी हुई रणनीति को लागू करने में सफल रहे हैं. सभी विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भाजपा केरल में तीसरी शक्ति बन गयी है और उसका वोट प्रतिशत दहाई अंकों में होगा. अगर यह बात सच साबित हो जाती है कि पार्टी इस राज्य में पांच सीटें तक ला सकती है, तो यह उसके हिंदी भाषी राज्यों की पार्टी होने का ठप्पा सदा के लिए मिटा देगी.

भाजपा ने बंगाल में पिछले लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीती थी, जिसकी काफी चर्चा हुई थी, लेकिन इस बार पार्टी ने जबरदस्त तैयारी की है. गृह मंत्री अमित शाह ने पिछली बार भी चुनाव की कमान संभाली थी और इस बार भी वे काफी सक्रिय रहे हैं. बंगाल के हर मुद्दे पर उन्होंने ध्यान रखा और केंद्रीय एजेंसियों की सहायता से वहां के अपराधी मिजाज के तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारियों को धूल चटा दी. संदेशखाली कांड में जिस शाहजहां शेख नाम के डॉन का नाम आ रहा था, वह अब सीबीआई और ईडी की गिरफ्त में है. इस घटना पर भाजपा ने जिस तरह की सक्रियता दिखायी, उससे वहां के वोटरों को हिम्मत मिली. अब ऐसा दिखता है कि वहां पासा पलट गया है. भ्रष्टाचार के आरोप में तृणमूल के कई नेता जेल जा चुके हैं. इससे पार्टी के प्रति जनता में पहले जैसा जुड़ाव नहीं दिख रहा है. ऐसे में प्रशांत किशोर की बात में दम लगता है कि बंगाल में भाजपा दूसरे नंबर पर तो रहेगी ही, पहले स्थान पर भी आ सकती है. कभी देश का सबसे औद्योगिक राज्य रहा बंगाल, जो व्यापार-कारोबार में अव्वल था, कम्युनिस्टों के 30 साल के शासनकाल में बर्बाद हो गया. ममता बनर्जी के आने के बाद उम्मीद बंधी थी, पर उन्होंने अपनी हिंदू विरोधी नीतियों और बांग्लादेशियों को बढ़ावा देने के रवैये से उसे फिर बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया. इस बार अमित शाह ने पूरी तैयारी की है और पार्टी कार्यकर्ता उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं. पार्टी ने वहां सोनार बांग्ला का नारा दिया है, जिसके तहत विकास, रोजगार तथा विनिर्माण को बढ़ावा देने का वादा किया है. इसका असर मतदान के दिन दिख रहा है.

ओडिशा भगवान जगन्नाथ की धरती है और वहां बीजू जनता दल (बीजेडी) के नवीन बाबू 2000 से ही सत्ता पर काबिज हैं. उल्लेखनीय है कि इसकी शुरुआत उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर की थी, लेकिन बाद में दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हो गये. साल 2009 में नवीन बाबू की पार्टी भाजपा से दूर हो गयी और दोनों परस्पर विरोधी हो गये. ओडिशा एक ऐसा राज्य है, जहां विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव साथ-साथ होते हैं. इस बार भाजपा की नजरें विधानसभा पर भी हैं. पार्टी के शीर्ष रणनीतिकार अमित शाह ने पूरा जोर लगाया हुआ है कि दक्षिण का द्वार समझा जाने वाला यह राज्य पार्टी के हाथ में आ जाए. इसके लिए उन्होंने पूरी रणनीति बनायी है. यह देखते हुए कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अब 77 साल के हो गये हैं और पहले की तरह गतिशील नहीं रहे हैं, भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. इस कारण कुछ विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के परिणामों में भाजपा पहले स्थान पर रहेगी. लेकिन जब तक परिणाम न आ जाएं, हमें इंतजार करना होगा.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

विदेशों में भारतीय छात्रों की बढ़ती मुश्किलें

सतीश सिंह
टिप्पणीकार
singhsatish@sbi.co.in

पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कभी विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को देश का ब्रांड एंबेसडर कहा था. इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने वहां पढाई कर रहे भारतीय छात्रों को दोनों देशों के बीच का जीवंत सेतु माना था. परंतु आज इन भारतीय छात्रों की जान वैश्विक स्तर पर सांसत में फंसी हुई है.

भले ही भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, परंतु अभी भी भारत में गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पर्याप्त विकल्प एवं अवसर उपलब्ध नहीं हैं. न ही शिक्षा और योग्यता के अनुसार देश में रोजगार उपलब्ध हैं. हालांकि, आजादी के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार हुए हैं, जिससे रोजगार व अनुसंधान परिदृश्य, साक्षरता दर आदि में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. आज देशभर में 1000 से अधिक विश्वविद्यालय और 42,000 से अधिक कॉलेज उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं. परंतु इनके पास अभी भी पर्याप्त पूंजी, कुशल शिक्षक और आधारभूत संरचना की कमी है. हालांकि शोध कार्यों में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय तेजी आयी है. भारत में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों का प्रतिशत महज 13 है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह प्रतिशत 28 से 90 के बीच है.

वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर फ्यूचर इंडेक्स के अनुसार गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के मामले में भारत 2020 में दुनिया में 33वें, 2019 में 35वें और 2018 में 40वें स्थान पर था. भारत का कोई कॉलेज या विश्वविद्यालय आज भी दुनिया में शीर्ष 10 स्थानों में नहीं है. उच्च शिक्षा के स्तर का विश्लेषण करने वाली संस्था क्वाक्वेरेली साइमंड्स (क्यूएस), लंदन द्वारा घोषित विश्वविद्यालय रैंकिंग, 2024 के अनुसार, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद व्यवसाय एवं प्रबंधन श्रेणी में दुनिया के शीर्ष 25 प्रबंधन संस्थानों में से एक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु और कोलकाता दुनिया के शीर्ष 50 व्यवसाय प्रबंधन संस्थानों में से एक हैं. विश्वविद्यालय श्रेणी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दुनिया के शीर्ष 20 विश्वविद्यालयों में से एक है. विदेश में बड़ी संख्या में छात्रों द्वारा शिक्षा ग्रहण के कारण भारत से पूंजी का बहाव विदेशों में होने के साथ ही प्रतिभा का पलायन भी हो रहा है. विदेश मंत्रालय के अनुसार, जनवरी 2023 तक 15 लाख भारतीय छात्र विदेशों में पढ़ाई कर रहे थे, जबकि 2022 में यह संख्या 13 लाख थी और 2024 में इसके 24 लाख पहुंचने की संभावना है. वर्ष 2020 से 2021 के दौरान विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई. विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों में से 20 प्रतिशत ही अपनी पढ़ाई पूरी कर विदेश से भारत वापस लौटना चाहते हैं. ऐसी स्थिति में बदलाव के लिए, विदेश के नामचीन कॉलेज और विश्वविद्यालय की शाखाएं भारत में खोली गयी हैं, परंतु भारतीय छात्र इनमें दाखिला लेने में ज्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं.

विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों में 35 प्रतिशत अमेरिका में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. कोरोना महामारी के शुरू होने से पहले विदेशों में अध्ययनरत छात्रों ने विदेश की अर्थव्यवस्थाओं में 24 अरब डॉलर व्यय किया था, जो भारत के जीडीपी का एक प्रतिशत था. वर्ष 2024 में इस राशि के बढ़कर 80 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान है. आंकड़ों के अनुसार, चीन के बाद भारत से सबसे अधिक छात्र विदेश पढ़ने जाते हैं. मेडिकल की डिग्री के लिए भारतीय छात्र लगभग तीन दशकों से रूस, चीन, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाखस्तान, फिलीपींस जा रहे हैं, क्योंकि भारत में मेडिकल सीट कम है और पढ़ाई बहुत महंगी. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 में देशभर में महज 596 मेडिकल कॉलेज थे, जहां कुल मेडिकल सीटों की संख्या महज 88,120 थी. बीते कई वर्षों से विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की हत्या और उनके साथ भेदभाव हो रहा है, परंतु कोरोना महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद विदेश में अध्ययनरत छात्रों की सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंता महसूस की गयी. महामारी के दौरान ऑस्ट्रेलिया के शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों के लिए वहां की सरकार ने देश की सीमाएं भी बंद कर दी थीं. वहीं, रूस-यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दौर में यूक्रेन में 20,000 से अधिक छात्र फंस गये थे. कुछ महीने पहले भी कनाडा में कुछ कॉलेजों के बंद होने के कारण सैकड़ों भारतीय छात्र प्रभावित हुए थे. कुछ दिनों पूर्व किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में कुछ भारतीय छात्रों पर जानलेवा हमला हुआ. फरवरी 2024 में अमेरिका के सेंट लुईस स्थित वाशिंगटन विश्वविद्यालय के छात्र अमरनाथ घोष की हत्या कर दी गयी. विदेश मंत्रालय के अनुसार, 2018 से अब तक विदेशों में पढ़ रहे 400 से अधिक छात्रों की मौत हो चुकी है, जिनमें कुछ प्राकृतिक मौत थी तो कुछ हत्या.

भारतीय छात्रों की विदेश में की जा रही हत्या, उन पर किये जा रहे जानलेवा हमले, नस्ली टिप्पणी या भेदभाव की स्थिति में सुधार के लिए सरकार को अंतरराष्ट्रीय संधि की संख्या बढ़ाने के साथ सरकारी मेडिकल व इंजीनियरिंग कालेजों में सीटों की संख्या बढ़ानी चाहिए. शिक्षा के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर सुधार एवं अधिकाधिक निवेश, नवोन्मेष और अनुसंधान को बढ़ावा देने की जरूरत है. पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कभी विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को देश का ब्रांड एंबेसडर कहा था. इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने वहां पढाई कर रहे भारतीय छात्रों को दोनों देशों के बीच का जीवंत सेतु माना था. परंतु आज इन भारतीय छात्रों की जान वैश्विक स्तर पर सांसत में फंसी हुई है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश दुनिया

सूडान में जारी युद्ध और यूएइ की भूमिका

सूडान का युद्ध दुनिया में चल रहे सबसे खराब मानवीय संकटों में से एक बन गया है. सूडानी सशस्त्र बलों (एसएएफ) और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) के बीच चल रहे युद्ध में एक वर्ष से कुछ अधिक समय में, 68 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं, 20 लाख देश छोड़कर चले गये हैं, और 2.48 करोड़, लगभग आधी जनसंख्या को, मानवीय सहायता की सख्त जरूरत है. यूएई युद्ध में सबसे अधिक निवेश करने वाला विदेशी खिलाड़ी है. वास्तव में, इसके प्रत्यक्ष और चौतरफा समर्थन के बिना, आरएसएफ इस हद तक युद्ध करने में सक्षम नहीं हो पाता. सूडान, अफ्रीका और मध्य-पूर्व में यूएइ की रणनीति की कुंजी है, जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक आकांक्षाओं पर अंकुश लगाते हुए राजनीतिक और आर्थिक आधिपत्य प्राप्त करना है. वर्ष 2015 से इसने यमन में अपने संघर्ष में शामिल होने के लिए दोनों गुटों से लड़ाकों को बुलाया है. यह सूडान के सोने का प्राथमिक आयातक है, और इसकी योजना सूडान के लाल सागर तट पर बंदरगाह विकसित करने की है. सूडान में आरएसएफ का समर्थन करके इसने 30 वर्षों तक सूडान के तानाशाह रहे उमर अल-बशीर को 2019 में सत्ता से बेदखल किया और उसके बाद यहां हुए लोकतांत्रिक परिवर्तन को कमजोर कर दिया. युद्ध शुरू होने पर इसने कथित तौर पर लीबिया, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण सूडान, युगांडा, हफ्तार और वैगनर मिलिशिया में मौजूद अपने नेटवर्क के माध्यम से आरएसएफ को हथियार भेजने के लिए लॉजिस्टिक ऑपरेशन स्थापित किये. हालांकि यूएइ ने आरएसएफ को सहायता से इनकार किया है. इन सबके बीच, अकाल, बीमारी और युद्ध नागरिकों पर भारी पड़ रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय समुदाय को संघर्ष में यूएई की घातक भूमिका के लिए उसका विरोध करना चाहिए. नहीं तो सूडान के अंतहीन युद्ध में फंस जाने का खतरा है.

The Guardian

-हुसम महजौब

बोधि वृक्ष

मनुष्य का लक्षण

मनुष्य को काम करते समय याद रखना चाहिए कि वह जो कुछ कर रहा है, वह आत्म-साक्षात्कार के लिए है. यदि कोई केवल आत्म-साक्षात्कार के लिए साधना कर रहा है और दुनिया की परवाह नहीं है, तो क्या हम ऐसे व्यक्ति को पूर्ण स्वार्थी नहीं कहेंगे? यदि कोई मानवता की सेवा नहीं कर रहा, उसकी कोई चिंता नहीं है, केवल आत्म-साक्षात्कार के लिए साधना में लगा हुआ है, तो वह निरुद्देश्य हो जाता है. आप जीविका और भरण-पोषण के रूप में संसार से बहुत अधिक सेवा लेते हैं. बदले में आपको वापस करना ही होगा, अन्यथा आप अपने ऊपर ऋण लाद रहे हैं. मृत्यु के समय यदि आप पर किसी बड़े ऋण का बोझ है तो क्या होगा? ब्याज के साथ अपना ऋण चुकाने के लिए आपको पुनर्जन्म लेना होगा. आप दुनिया से सेवा लेते हैं, इसलिए आप दुनिया को कुछ नहीं दे सकते हैं. परंतु यदि आप जितना लेते हैं, उससे अधिक देते हैं, तो आपको ब्याज प्राप्त होगा. बेशक ब्याज को स्वीकार करना या न करना आपका विशेषाधिकार है. परंतु ऋण चुकाने के संबंध में आपके पास ऐसा कोई विशेषाधिकार नहीं है. आपको इसे चुकाना ही होगा. आप दुनिया में आये हैं दुनिया की सेवा करने के लिए और आत्म-साक्षात्कार की साधना का अभ्यास करने के लिए. पर केवल आत्म-साक्षात्कार की साधना करेंगे और समाज सेवा से दूर रहेंगे, तो आप अपनी साधना में कोई प्रगति नहीं कर सकते. सेवा और साधना दोनों एक-दूसरे पर निर्भर हैं. हमारे दर्शन में मनुष्य को पशु नहीं, तर्कशील प्राणी माना गया है. मानव जीवन एक वैचारिक प्रवाह है. जीवन में एक आदर्श होना चाहिए और जब उस आदर्श की ओर गतिशीलता हो तो हम उसे मानव कहते हैं. जहां कोई आदर्श नहीं है, न ही किसी आदर्श की ओर कोई गति है, हम किसी मानवीय रूप के होते हुए भी उसे मानव नहीं कह सकते. मनुष्य जब व्यावहारिक जीवन में रचता-बसता है, तो उसकी संवेदनशीलता बताती है कि वह कितना मानव है. इसलिए हर व्यक्ति को आंतरिक जगत और बाहरी जगत में संतुलन रखना चाहिए.

-श्री श्री आनंदमूर्ति

अंतरराष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस

माउंट एवरेस्ट की सुंदरता बनाये रखनी होगी

सुधीर कुमार
टिप्पणीकार
sudhirphd@bhu.ac.in

उनत्तीस मई, 1953 की सुबह 11.30 बजे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेनजिंग नोर्गे ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था. मानव सभ्यता के इतिहास में यह पहला अवसर था जब 8848.86 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट को सफलतापूर्वक फतह किया गया था. इस ऐतिहासिक अभियान ने पर्वतारोहण की दुनिया में नयी प्रेरणा का संचार किया. हिलेरी और तेनजिंग की इस महान उपलब्धि ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई और पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनके योगदान को अमर कर दिया. ये दोनों 15 सदस्यीय ब्रिटिश अभियान दल का हिस्सा थे, जिसका नेतृत्व कर्नल जॉन हंट, बैरन हंट कर रहे थे.

तेनजिंग और हिलेरी की इस सफलता ने पर्वतारोहियों के लिए असंभव प्रतीत होने वाले लक्ष्य को संभव कर दिखाया. इस अद्वितीय उपलब्धि ने माउंट एवरेस्ट को इतिहास के पन्नों में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया. इससे न केवल दोनों की प्रसिद्धि दुनियाभर में फैली, बल्कि उन्हें कई उपलब्धियों से भी नवाजा गया. ब्रिटिश सरकार ने एडमंड हिलेरी को नाइटहुड (सर) की उपाधि दी. एवरेस्ट फतह ने उनकी राजनयिक भूमिका स्थापित करने का कार्य भी किया. हिलेरी भारत व बांग्लादेश में न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त और नेपाल में राजदूत भी रहे. वर्ष 2008 में हिलेरी का निधन हुआ और उसी वर्ष से नेपाल ने 29 मई को अंतरराष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस मनाने की शुरुआत की. यह तिथि एवरेस्ट फतह की तिथि होने के साथ-साथ तेनजिंग नोर्गे की जन्मतिथि भी थी. एवरेस्ट फतह के बाद तेनजिंग कई नेपाली और भारतीयों के लिए नायक बन गये. उन्हें ब्रिटेन का 'जॉर्ज मेडल' और 'ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ नेपाल' प्रदान किया गया. उनके सम्मान में भारत सरकार तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान करती है.

माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का जो सिलसिला आज से सात दशक पहले शुरू हुआ था, वह आज भी जारी है. विभिन्न देशों के लोग दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को छूने की तमन्ना लिए नेपाल आते हैं. पर्वतारोहण आज नेपाल में पर्यटन उद्योग का एक सशक्त माध्यम बन चुका है. परंतु इससे एवरेस्ट पर भीड़भाड़ बढ़ रही है. इस कारण एवरेस्ट पर कार्बन पदचिह्न भी व्यापक हो रहे हैं, साथ ही यह कचरे के पहाड़ में तब्दील होता जा रहा है. वर्ष 1953 से अब तक एवरेस्ट फतह के क्रम में 300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं. इस कारण पर्वतारोहियों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए सख्त नियमों की आवश्यकता बढ़ गयी है. नेपाल सरकार को इस दिशा में कदम उठाने होंगे, ताकि माउंट एवरेस्ट की अद्वितीयता और सुंदरता बनी रहे.

आपके पत्र

बिहार में जल्द बने फिल्म सिटी

बिहार ने फिल्म इंडस्ट्री को कई महान कलाकार दिये हैं. बिहारी कलाकार बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्मों में धमाल मचा रहे हैं. चंदन रॉय, पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकार ओटीटी पर भी अपना लोहा मनवा रहे हैं. लेकिन, यहां फिल्म सिटी नहीं होने से निराशा होती है. सूबे में ऐतिहासिक धरोहर होने के बाद भी शूटिंग का इंतजाम नहीं है. सरकार को बिहार में फिल्म सिटी के निर्माण पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. फिल्म निर्माताओं को सब्सिडी देनी चाहिए. इससे स्थानीय कलाकारों को भी मौका मिलेगा.

दीपक कुमार, चकौर (बेगूसराय)

समार्टफोन ने बदल दी जीवनशैली

स्मार्टफोन ने लोगों की जीवनशैली बदल दी है. ऐसा हो गया है कि लोग बिना मोबाइल के रह ही नहीं सकते. हालांकि, मोबाइल से कई प्रकार की सुविधा मिली है. पैसा भेजने से लेकर संवाद करने तक में आसानी हो गयी है. लेकिन, इसने बच्चों का बचपन, युवाओं से खेल और समाज से समसरता छीन ली है. अब गांवों में भी एक साथ लोग बैठे नहीं मिलते. चाय की दुकान पर पड़ोसियों से बातचीत नहीं होती है. इसलिए, स्मार्टफोन का उपयोग करें, लेकिन इसकी सीमाओं को तय करना जरूरी है.

नीतीश कुमार, अमरौरी (अररिया)

संपादकीय

नौकरशाह नेताओं की हां में हां मिलाने से बचें

तेलंगाना की वर्तमान सरकार ने पिछले दिनों कुछ आईपीएस अधिकारियों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि पिछली केसीआर सरकार में राजनेताओं के इशारे पर एसआईटी ने विरोधियों, खिलाफ बोलने वालों, कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों, उद्योगपतियों आदि के फोन सर्विलांस पर रखे या बातचीत टेप की। अब एक पूर्व डीसीपी ने इन आरोपों को स्वीकारा है। तेलंगाना एसआईटी को देश भर के आतंकवादियों पर नजर रखने, राज्यों को टिप्स देने और आतंकियों को पकड़वाने में महारत हासिल है, जिसका लोहा एनआईए जैसी संस्था भी मानती है। लेकिन उसका पतन इस स्तर तक होना यह बताता है कि आजादी के बाद सत्ताधारी वर्ग ने किस तरह किसी जमाने में स्टील-फ्रेम (फौलादी ढांचा) कहलाने वाली अफसरशाही को ट्रांसफर का भय और पद का लालच दिखा कर बीमार कर दिया। सिर्फ तेलंगाना नहीं, अनेक राज्यों और केंद्र में नौकरशाही की गतिविधियां साफ बताती हैं कि इसने अपनी रीढ़ सीधी रखते हुए, नेताओं के मुंह पर केवल संविधान-सम्मत काम करने की बात कहना लगभग छोड़ दिया है। कर्नाटक में एक ऐसे राजनीतिक परिवार- जिसका मुखिया प्रधानमंत्री और बेटा मुख्यमंत्री और अन्य परिजन मंत्री व विधायक रहे हों, उस परिवार के सदस्य पर लंबे समय तक दर्जनों महिलाओं से दुष्कर्म का खुलासा तब हुआ जब राज्य में नई सरकार आई। यह क्या बताता है? यही अफसर तो पहले भी थे। राजनीतिक वर्ग ने सत्ता में रहते हुए इन्हें इस कदर रीढ़विहीन बनाया कि इनमें से कुछ ने समय से पहले वीआरएस लेकर किसी राजनीतिक पार्टी का दामन थामा। सन् 1922 में ब्रिटिश पीएम लायेड जॉर्ज ने आईसीएस को स्टील फ्रेम कहा था, भारत के नेताओं ने दिखाया कि भारत का प्रजातंत्र इसे कितना लचीला बना सकता है।

प्रेरणा

किसी का आकलन करना है, तो उसके सवालों से करो, जवाबों से नहीं। **-वोल्तेयर,** फ्रांसीसी दार्शनिक

सुर्खियों से आगे • पुणे की घटना पिताओं और उनके जवान होते बच्चों के लिए सबक है

पोर्श, पिता और पुत्र! आखिर दोषी कौन?

नवनीत गुर्जर
navneet@dbcorp.in

19 मई।

पुणे का कल्याणी नगर इलाका।

यहां रहने वाले रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल का नाबालिग (18 से कम उम्र) बेटा अपनी पोर्श कार से बाइक सवार दो इंजीनियरों को कुचल देता है।

परिणाम बेटा खुद बाल सुधार गृह में। पिता जेल में। दादा भी गिरफ्तार।

आखिर यह क्यों हुआ? ऐसा होता ही क्यों है?

कसूर उस तेज रफ्तार, महंगी कार का है? नशे में धुत होकर कार दौड़ा रहे उस बेटे का है? या उस पिता का जिसने नाबालिग बेटे की जिद के आगे हार मानकर उसको पोर्श की चाबी थमा दी?

आसानी से कहा जा सकता है कि रईस बाप की औलादें ऐसी ही होती हैं।

पैसों के नशे में चूर।

बेमुरव्वत। बेखौफ...

और बहुत हद तक निर्दयी भी।

कहा जा सकता है कि रईस बाप को फर्क नहीं पड़ता। बेटे को बचाने के लिए वो कभी ड्राइवर को खरीदता है। कभी डॉक्टर्स को ब्लड सैंपल डस्टबिन में फेंकने को मजबूर करता है। पुलिस, न्याय व्यवस्था आदि को खरीदने की कोशिश भी करता है।

सही है, ऐसा अक्सर होता है। कोई अपनी इस मंशा में सफल होता है। कोई विफल।

सवाल यह है कि इस पूरी समस्या की जड़ क्या है? क्या उस पिता ने अपने नाबालिग बेटे को कार ले जाने से मना नहीं किया होगा?

जरूर किया होगा। लेकिन आजकल के जवान होते बेटे मानते कहां हैं? पिता भी बेटे और उसके दोस्तों के सामने कंजूस नहीं कहलाना चाहते। नहीं चाहते कि आज की पीढ़ी उन्हें पुरातन कहकर चिढ़ाए।

सकुचाते हैं कि उनके बच्चे ये न कहने लगें कि हमारे पिता तो कतरे-ब्योंते, सड़े-गले, नियम-सिद्धांतों की अंधी गली में खोए रहते हैं।

यही सब सोचकर पिता कार की चाबी नाबालिग को देने पर मजबूर हो जाता है।

बच्चों की नजर में 'प्रोग्रेसिव' कहलाने की चाह उससे यह सब करवाती है।

लेकिन फिर पिता की सीरियसनेस सामने आती है। ड्राइवर साथ ले जाने की शर्त पर चाबी देता है लेकिन नशे में धुत बेटा ड्राइवर को पीछे बैठाकर गाड़ी उड़ाता है

पिता सकुचाते हैं कि बच्चे उन्हें पुरातन न समझ बैठें...

क्या पिता ने बेटे को कार ले जाने से मना नहीं किया होगा? जरूर किया होगा। पर आजकल के जवान होते बेटे मानते कहां हैं? पिता भी नहीं चाहते कि आज की पीढ़ी उन्हें पुरातन कहकर चिढ़ाए।

और उड़ जाते हैं निर्दोष लोगों के प्राण!

तो आखिर इसका निदान क्या?

सच है, सोलह-सत्रह की उम्र में जाना-पहचाना सबकुछ शरीर के वस्त्रों की तरह तंग हो जाता है।

होंठ जिंदगी की प्यास से खुश्क हो जाते हैं।

आकाश के तारे, जिन्हें बचपन में सप्त ऋषियों के आकार में देखकर दूर से प्रणाम करना होता है, पास जाकर छूने, बल्कि खीसे में डालने को मन करता है।

इर्द-गिर्द और दूर-पास की हवा में इतनी मनाहियां, इतने इनकार और इतने विरोध होते हैं कि सांसों में आग सुलग उठती है।

युवा मन की यही आग पिता-दादा को मजबूर बनाती है और कभी-कभी सड़क चलते निरपराध की जान लेने पर भी बन आती है।

होना यह चाहिए कि पिता अपनी सख्ती पर कायम रहे। बच्चे इस पितृात्मक अनुशासन की हंसी उड़ाने या उसे अपना अपमान समझने की बजाय हालात की गंभीरता को समझें।

निश्चित ही ऐसे हादसों से बचाव का उपाय बच्चों और पिता की गंभीर समझ से ही निकल सकता है।

पुलिस, प्रशासन, थाने, ये सब तो सबूत बनाने और उन्हें मिटाने के उपक्रम में लगे रहते हैं।

वहां से किसी तरह के निदान की कल्पना करना बेमानी ही लगता है।

कुल-मिलाकर पुणे की यह घटना देशभर के पिताओं और उनके जवान होते बच्चों के लिए एक सबक है।

एक हिदायत है...

और बहुत हद तक एक लक्ष्मण रेखा भी।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
ptvijayshankarmehta.com

संस्कार और चरित्र के प्रति जन जागृति बहुत जरूरी है

हमारे देश में कई किस्म की चिंताएं चल रही हैं। एक फिक्र ये भी है कि हम 144 करोड़ हो चुके हैं। और इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए भोजन, स्वास्थ्य और रोजगार ये अब अलग समस्या के रूप में सामने आएंगे। 25 साल बाद, 70 प्रतिशत भोजन की और अधिक आवश्यकता होगी। अभी भी हमारे देश में कई लोग भूखे उठते हैं और भूखे ही सोते हैं, तो आने वाले 25 सालों में क्या होगा? इस जनशक्ति का हमें सदुपयोग करना पड़ेगा। आने वाले समय में पीने के पानी के ठिकाने नहीं होंगे। जीवनशैली में लगातार विलास उतरेगा और विलास के कारण अपराध आएगा। कदम-कदम पर युद्ध है और इसी का नाम जिंदगी है। पग-पग पर हार-जीत, इसी का नाम उम्र है। इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण अपने ढंग से सरकारें करेंगी, पर जनशक्ति का उपयोग धार्मिक जगत में ही हो पाएगा। हमारे देश में साधु-संतों की अद्भुत परंपरा है और वे ही जनशक्ति को मनुष्य जीवन का सदुपयोग सिखा रहे हैं। अगर समाज की दृष्टि से देखें तो विलास ने अपराध इतने बढ़ा दिए कि अब उम्र का कोई लेना देना नहीं है। नाबालिग ऐसे-ऐसे अपराध कर रहे हैं कि वो वयस्क की श्रेणी को भी लांघ दें। ऐसे में बढ़ती जनसंख्या में जन जागृति भी बहुत जरूरी है और खास तौर पर संस्कार और चरित्र के प्रति तो बहुत ज्यादा।

• Facebook: Pt. Vijayshankar Mehta

अर्थात् • कार्बन उगलने वाली कंपनियों को जंगलों में करना पड़ रहा है निवेश, और यही है 'कार्बन क्रेडिट'

जंगलों की कटाई अब कारोबार पर भी भारी पड़ेगी

अंशुमान तिवारी
मनी-9 के एडिटर
anshuman.tiwari@tv9.com

बीते बरस दुबई में पर्यावरण बचाने की जुटान यानी कोप-28 की बैठक में जब दुनिया के महान नेता भाषणों की जलेबी बना रहे थे, उस वक्त कुछ अखबारों में एक खबर कौंधी। पता चला कि दुबई की एक कंपनी ब्लू कार्बन ने अफ्रीका में जंगल खरीद लिए हैं। इस कंपनी के मालिक शेख अल मकतूम दुबई के सुल्तान के कुनबे से आते हैं। जंगल खरीदना बड़ी बात नहीं मगर इन्होंने तो कुछ और ही किया। ब्लू कार्बन ने जिम्बाब्वे का 20%, लाइबेरिया का 10%, जाम्बिया का 10%, तंजानिया का 8% हिस्सा खरीद लिया। इस भूमि पर जंगल हैं। इन चार अफ्रीकी देशों में जितना जंगल अमीरात की कंपनी ने खरीदा है, वह यूके के क्षेत्रफल के बराबर है! इससे पहले अक्टूबर में अल मकतूम की कंपनी ने केन्या में जंगल खरीदने का एक बड़ा सौदा किया था। खरीदे गए जंगलों के क्षेत्रफल का ब्योरा नहीं बताया गया, मगर इस सौदे की जानकारी केन्या की सरकार की तरफ से दी गई। दुबई की इस कंपनी ने पाकिस्तान में भी जंगल खरीदे हैं। ब्लू कार्बन की पैरेंट कंपनी ग्लोबल कार्बन इन्वेस्टमेंट ने अकेले जाम्बिया के सौदे से 1.5 अरब डॉलर के कार्बन क्रेडिट हासिल किए हैं।

बर्बादी का लेनदेन : 1997 में क्योटो में तय हुआ था कि उद्योगों और देशों को पर्यावरण की तबाही और ग्लोबल वार्मिंग घटाने के लिए कार्बन का उत्सर्जन रोकना होगा। यह काम चुटकियों में तो होना नहीं था, इसलिए खुला कार्बन क्रेडिट और कार्बन ऑफसेट का बाजार। कंपनियों को अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना होता है। इसके दो रास्ते हैं। एक वे उत्पादन में कार्बन वाली ऊर्जा के इस्तेमाल को कम करें और दूसरा वो जितना धुआं छोड़ रहे हैं उसके बदले उतनी ही ऑक्सीजन पैदा करने वाले किसी प्राकृतिक संसाधन में निवेश करें।

सनद रहे कि ऑक्सीजन तो केवल जंगल ही पैदा कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट एक तरह का लाइसेंस है, जिन्हें दिखाकर उद्योग कार्बन उगलते रह सकते हैं। क्योंकि इनके बदले कहीं कोई जंगल उतनी ही टन ऑक्सीजन बना रहा है। कार्बन क्रेडिट सरकारें या अंतरराष्ट्रीय संगठन जारी करते हैं। मसलन अमेरिका में कैलिफोर्निया की सरकार कार्बन उत्सर्जन करने वाले बिजली घरों और गैस कंपनियों को कार्बन क्रेडिट देती है। जबकि कार्बन ऑफसेट का बाजार फर्क है। यह कार्बन बेचने-खरीदने वालों के बीच चलता है। जैसे किसी कंपनी ने जंगल बढ़ाकर उत्सर्जन कम किया तो वह इस क्रेडिट को किसी दूसरी कंपनी को बेच सकती है, जिसे कार्बन फुटप्रिंट कम करना है।

अफ्रीका की होड़ : इस बाजार पर कब्जे के लिए दुबई के शेखों ने गरीब अफ्रीका को धर लिया। अफ्रीका के जंगल हर साल करीब 600 टन सीओ2 सोख सकते हैं, जो दुनिया के लिए भी इको-सिस्टम से ज्यादा है। अफ्रीका का अपना उत्सर्जन नगण्य है। अफ्रीका के लिए कार्बन क्रेडिट सबसे बड़ा निर्यात होने वाले हैं। अगले छह साल में यह महाद्वीप करीब 300 मिलियन कार्बन क्रेडिट बेच सकता है। दुबई के शेख को जंगलों की खरीद के साथ अगले 30 साल के लिए कार्बन क्रेडिट बेचने का अधिकार मिल गया है। ब्लू कार्बन अगले एक दशक में कार्बन क्रेडिट की सबसे बड़ी कारोबारी हो सकती है। अफ्रीका में कार्बन क्रेडिट पर टैक्स और कारोबार के नियम भी नहीं बने हैं। सरकारें भ्रष्टाचार का उत्पादन करती हैं। अरब के शेखों के लिए यह बाजार लपकना आसान है।

जंगल गंवाने में नंबर वन...

बीते 30 सालों में भारत ने 6-7 लाख हेक्टेयर जंगल गंवा दिए। 1990 से 2020 के बीच जंगल गंवाने में तो भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। इस दौरान 3 लाख हेक्टेयर जंगल खा-पचा लिए गए। वहीं भूटान कार्बन न्यूट्रल देश है और अपना कार्बन क्रेडिट बाजार बना रहा है।

बाजार का खेल : कोप-दुबई में यह बात साफ हो गई थी कि दुनिया अपना कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली नहीं है। सभी देशों ने कार्बन उत्सर्जन बढ़ाने के लक्ष्य रखे हैं। इसलिए अब बाजारों में कार्बन क्रेडिट की होड़ मचेगी। उद्योगों को कार्बन उत्सर्जन कम करना होगा और कंपनियां तलाशेंगी अफ्रीका जैसे बाजार जहां कार्बन सोखा जा सके। मार्केटसैंड मार्केट की रिपोर्ट का अनुमान है कि कार्बन क्रेडिट का बाजार 2022 में 332 अरब डॉलर था, जो सालाना 31% की बढ़त के साथ 2028 में 1.6 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कंप्लायंस के बाजार का है यानी वे क्रेडिट जो कंपनियों को खरीदने ही होंगे। मसलन, भारतीय निर्यातकों को यूरोप में निर्यात पर कार्बन टैक्स चुकाना होगा। कार्बन तो कम होने से रहा तो फिर उन्हें कंप्लायंस क्रेडिट (कहीं दूसरी जगह ऑक्सीजन उत्सर्जन की गारंटी) खरीदने पड़ सकते हैं। मार्च 2022 में अबू धाबी में दुनिया का पहला कार्बन क्रेडिट मार्केट भी शुरू हो गया है। कार्बन क्रेडिट के मौजूदा बाजार में पारदर्शिता नहीं है। कार्बन वैल्यूएशन के नियम स्पष्ट नहीं हैं। कोप की बैठक के बाद हाय-तौबा मची है कि अफ्रीका का कार्बन मार्केट सस्ते में लुट रहा है।

और भारत : भारत ने भी कार्बन उत्सर्जन घटाने का वादा नहीं किया। बल्कि कोयला जलाने के नए लक्ष्य तय किए हैं। कल्पना करें कि भारत में कार्बन क्रेडिट का घरेलू बाजार हो तो वह कैसा होगा। क्या उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, मध्य प्रदेश और मध्य-पूर्व के राज्य बाकी देश का कार्बन सोखने की कीमत वसूलेंगे? क्योंकि इसी तरीके से बाजार चलने वाला है। मगर भारत के पास जंगल हैं कितने? वास्तव में, यूके की प्रतिष्ठित एजेंसी यूटिलिटी बिल्डर के मुताबिक जंगल गंवाने में भारत दुनिया का दूसरा सबसे कुख्यात मुल्क है! अगर आप देश के किसी हिस्से में जंगलों के कटने की खबर सुन रहे हैं तो समझिए कि भारत अपना सबसे कीमती बाजार गंवा रहा है। जल्द ही इनकी जरूरत समझ आएगी जब यूरोप के बाजार में भारत के निर्यातकों से कार्बन की खपत और उत्सर्जन का हिसाब मांगा जाएगा! **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

वेब भास्कर

पुरस्कृत तस्वीर : ग्रे-व्हेल से दोस्ती करने के लिए पर्यटक यहां आते हैं

यह तस्वीर मैक्सिको में बाहा कैलिफोर्निया सूर की है। यहां के समुद्री इलाके में ग्रे-व्हेल अच्छी-खासी संख्या में देखने को मिल जाती हैं। इस इलाके में स्तनपायी जीवों का सबसे लंबे माइग्रेशन भी देखने को मिलता है। पर पर्यटक अक्सर इन ग्रे व्हेल से दोस्ती करने के लिए आते हैं। ग्रे व्हेल वास्तव में मिलनसार होती हैं। इंसानों को देखकर, वे बोट के आसपास चक्कर लगाने लगती हैं। बहुत आराम से तस्वीरें खिंचवाती हैं। ये व्हेल अपने व्यवहार से जाहिर करती हैं इंसान उनकी पीठ खुजलाएं, उन्हें दुलार करें। इस तस्वीर को 2024 का ड्रोन-फोटो अवॉर्ड्स मिल चुका है।

तस्वीर साभार : Joseph Cheires

टेक्नोलॉजी • जेनरेटिव एआई मॉडल बनाने वाली कंपनियां दुनियाभर में मुकदमे झेल रही हैं

एआई निर्मित कंटेंट का असली मालिक कौन होगा?

साधना शंकर
लेखिका और पूर्व भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी
sadhna99@hotmail.com

जेनरेटिव एआई से बनाई छवियों, कलाकृतियों और लेखों से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। इन एआई मॉडल्स की मालिक कंपनियां अब अरबों डॉलर की हो चुकी हैं। चैटजीपीटी बनाने वाली ओपनएआई की मार्केट वैल्यू 90 अरब डॉलर (7.4 लाख करोड़ रु) है, जबकि प्रतिस्पर्धी माइक्रोसॉफ्ट की वैल्यू 3.1 ट्रिलियन डॉलर (250 लाख करोड़ रु) के आसपास है।

इन कंपनियों के एआई मॉडल्स को भारी-भरकम डेटा के साथ प्रशिक्षित किया गया है, फिर चाहे टेक्स्ट हों, तस्वीरें, वीडियो या फिर संगीत। इसलिए सवाल उभरकर आ रहा है कि इन मॉडल्स को प्रशिक्षित करने से पहले इस डेटा के मालिक या लेखकों से अनुमति नहीं ली गई थी? उस डेटा के रचना-कर्ता इंसान हैं और अधिकांश कॉपीराइट कानूनों से संरक्षित है।

अतीत में ओपनएआई के खुलासे से पता चलता है कि चैटजीपीटी-3 को इंटरनेट सहित विभिन्न स्रोतों पर प्रशिक्षित किया गया था, जिसमें बड़ी मात्रा में कॉपीराइट डेटा शामिल था। आरोप हैं कि जेनरेटिव एआई मॉडल चोरी के सामग्री से बने हैं। इससे एआई मॉडल की मालिक कंपनियों पर मुकदमे शुरू हो गए हैं। बड़े अखबार ओपनएआई व माइक्रोसॉफ्ट पर केस कर रहे हैं, एक बड़ी म्यूजिक लेबल कंपनी एंथ्रोपिक को अपने गीतों के बोल, बिना अनुमति इस्तेमाल करने के लिए अदालत में खींच रही है, वहीं वेब इमेज की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक अपनी तस्वीरों का इस्तेमाल करने के लिए स्टेबिलिटी एआई कंपनी पर केस कर रही है। हालांकि ये कंपनियां आरोपों को नकारती हैं। तर्क दिया जा रहा है कि जैसे मनुष्य कुछ नया निर्मित करने के लिए पहले से मौजूद सामग्री को ग्रहण करता है, उसी तरह एआई भी कुछ अलग बनाने के लिए उपलब्ध सामग्री से प्रशिक्षण लेती है।

कानूनी लड़ाई जारी है, लेकिन बदलती दुनिया टेक्नोलॉजी से उत्पन्न चुनौतियां अपनाने की कोशिश कर रही है। जेनरेटिव एआई कंपनियों के मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए कई कंपनियां अपने डेटा का इस्तेमाल करने का लाइसेंस दे रही हैं। कॉपीराइट से सुरक्षित सामग्री के मालिक अब अपने एआई टूल्स बना रहे हैं, जिन्हें अंदरुनी डेटा पर प्रशिक्षित किया जा सके।

कंटेंट के मालिकों और जेनरेटिव एआई मॉडल के मालिकों के बीच चल रही यह रस्साकशी कॉपीराइट कानूनों की मौजूदा स्थिति के अनुसार उनकी पर्याप्तता पर भी सवाल उठा रही है। क्या कॉपीराइट कानून एआई से बनाए कंटेंट पर भी लागू होंगे? भारत में 2020 में कॉपीराइट कार्यालय ने एक आवेदन को अस्वीकार कर दिया जिसमें एआई (राघव) को एक कलाकृति के एकमात्र रचना-कर्ता के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि दूसरा आवेदन भी दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति और एआई (राघव) को संयुक्त रूप में प्रस्तुत किया गया और कॉपीराइट का पंजीयन स्वीकार कर लिया गया। बाद में इस रजिस्ट्रेशन को वापस लेने का नोटिस भी जारी किया गया।

सवाल उभरता है कि फिर एआई से बने कंटेंट का मालिक कौन होगा। चैटजीपीटी के नियम व शर्तें कहते हैं कि शुरुआती तौर पर तो वह उस कंटेंट का मालिक है, लेकिन बाद में स्वामित्व उपयोगकर्ता को स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसके कारण वो कंटेंट बना। सवाल है कि अगर चैटजीपीटी कई सारे उपयोगकर्ताओं के लिए एक-जैसी सामग्री उत्पन्न कर देता है, तो कोई भी इस पर अपना दावा नहीं कर सकता। मौजूदा कानूनी ढांचा ऐसे सवालों का स्पष्ट रूप से जवाब नहीं देते हैं।

जेनरेटिव एआई के कारण जीवन का हर क्षेत्र बदल रहा है और जो मुद्दे सामने आ रहे हैं वे जटिल हैं। बस एक बार स्वामित्व और रचनात्मकता के परिवर्तित कानून और इसकी धारणाएं मानव जीवन में ढल जाएं तो तमाम बहसें, मुकदमे और चर्चाएं अंततः सुलझ जाएंगी। **(ये लेखिका के अपने विचार हैं)**

मुद्दा • कानून के प्रावधानों का निजी हित में उपयोग

दलबदल विरोधी कानून ने उलटे दलबदल को बढ़ाया है

मयूरी गुप्ता
विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी में रिसर्च फेलो
mayuri.gupta@vidhilegalpolicy.in

पिछले कुछ वर्षों में राजनेताओं ने दलबदल विरोधी कानून का फायदा उठाने के लिए नित नए तरीके ईजाद किए हैं। दलबदल विरोधी कानून- या संविधान की दसवीं अनुसूची- 1985 में लागू किया गया था। कानून जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, उसमें बहुत कम सफलता हासिल कर पाया है। उलटे दसवीं अनुसूची ने उन समस्याओं को और विकट बना दिया, जिनका उसे समाधान करना था। उसने बड़े पैमाने पर दलबदल का मार्ग प्रशस्त किया। इसका मुख्य कारण राजनीतिक दलों में विभाजन और विलय को दी गई छूट थी। इन छूटों ने वास्तव में कई तरीकों से दलबदल को और सुविधाजनक बना दिया है। 2003 में, परिच्छेद 3 के तहत विभाजन वाली छूट को हटा दिया गया था। हालांकि, विभाजन और विलय, इन दोनों ही अपवादों के संयुक्त उपयोग से दलबदल विरोधी कानून के क्रियान्वयन पर जो असर पड़ा, वह समझने जैसा है।

लोकसभा और यूपी-हरियाणा विधानसभा के स्पीकर्स द्वारा दिए गए निर्णयों के विश्लेषण से एक पैटर्न का पता चलता है, जहां दलबदल के कारण अपात्रता से बचने के लिए विधायकों द्वारा विभाजन और विलय की छूट का उपयोग बार-बार किया गया था। इसे मोटे तौर पर 'विभाजन के बाद विलय' कहा जा सकता है। इन उदाहरणों में, एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि (या जनप्रतिनिधियों का एक समूह) उस राजनीतिक दल से अलग हो गया, जिसमें वे शामिल थे, और विधायक-दल के एक-तिहाई सदस्यों का समूह बनाकर विभाजन की छूट का लाभ उठाया। फिर अलग हुए विधायकों के पूरे समूह का दूसरी पार्टी में विलय हो गया। यह मानते हुए कि वे पूर्ण रूप से विलय करेंगे, उन्होंने किसी अन्य पार्टी के साथ वैध-विलय को लागू करने के लिए दो-तिहाई सदस्यों की आवश्यकता को आसानी से पूरा कर लिया। उदाहरण के लिए, 1997 में यूपी के जनता दल विधायक राजाराम पांडे ने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर जेडी (राजाराम) गुट बनाने के लिए पार्टी में विभाजन कराया। 2000 में जेडी (राजाराम) का लोजपा में विलय हो गया। 2002 में राजाराम पांडे ने लोजपा से अलग होकर लोजपा (राजाराम) गुट बना लिया। अंत में पांडे 2003 में सपा में शामिल हो गए।

ऐसा ही पैटर्न लोकसभा और हरियाणा विधानसभा में भी देखने को मिला। मार्च 1992 में लोकसभा सांसद भूपतिराजू विजयकुमार राजू ने तेलुगु देशम पार्टी से अलग होकर टीडीपी(वी) का गठन किया। कुछ ही महीनों के भीतर अगस्त 1992 में उन्होंने पूरे गुट का कांग्रेस(आई) संसदीय दल में विलय कर दिया। इसी तरह हरियाणा में करतार सिंह भड़ाना और 16 अन्य विधायकों ने 13 अगस्त 1999 को हरियाणा विकास पार्टी से अलग होकर एचवीपी (डेमोक्रेटिक) का गठन किया और 3 दिनों में हरियाणा लोकदल में विलय कर लिया। यह बताता है कि कैसे विभाजन और विलय अक्सर तेजी से होते हैं, कभी-कभी तो एक ही दिन में भी! जैसे यूपी विधानसभा से मित्रसेन यादव ने 4 मार्च 1994 को सीपीआई से अलग होने का फैसला किया और उसी दिन सपा में विलय कर लिया। इन मामलों में विधायकों द्वारा कई बार पार्टी बदलने के बावजूद वे अपात्र घोषित नहीं हुए।

दलबदल के कारण अपात्रता से बचने के लिए विधायकों द्वारा दसवीं अनुसूची में दी गई विभाजन और विलय की छूट का उपयोग बार-बार किया गया है। इसे मोटे तौर पर 'विभाजन के बाद विलय' कहा जा सकता है।

महाराष्ट्र में दो अवसरों पर अपात्रता से बचने के लिए एक नया पैटर्न तैयार किया गया, जिसे 'विभाजन के बाद विलय नहीं' कहा जा सकता है। दोनों उदाहरणों में, एक समूह ने विधायक दल में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत जुटाया, अलग गुट बनाया, और बाद में अन्य दलों के साथ सरकार बना ली या सरकार में शामिल हो गए। 2003 के बाद से, बड़े पैमाने पर दलबदलुओं के लिए उपलब्ध एकमात्र छूट परिच्छेद 4 के तहत विलय है। इसके अनुसार विभाजित होने वाले किसी भी गुट का किसी भी दल के साथ विलय या एक अलग समूह नहीं बनने के बावजूद, विभाजन और विलय की राजनीतिक जुगलबंदी ने अलग होने वाले विधायकों को महाराष्ट्र में अपात्रता से बचा लिया। इन हथकंडों ने दलबदल विरोधी कानून को निष्प्रभावी बना दिया है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

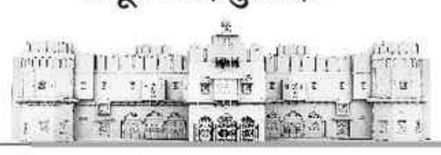

मजबूत तंत्र बने इंटरनेट के सुरक्षित इस्तेमाल का

बच्चों के साथ ऑनलाइन यौन दुराचरण की सामने आई तस्वीर चिंताजनक है। एक ताजा अध्ययन के अनुसार पिछले 12 माह में ही दुनिया भर में तीस करोड़ से ज्यादा बच्चे (अठारह वर्ष से कम उम्र के) ऑनलाइन यौन शोषण और दुर्व्यवहार के शिकार हुए हैं। इन चौंकाने वाले आंकड़ों की बड़ी वजह यह भी है कि सोशल नेटवर्किंग भी बच्चों के जीवन का अहम हिस्सा बनती जा रही है। भारत में भी बड़ी संख्या में बच्चे साइबर बुलिंग के शिकार होते हैं लेकिन इनसे कैसे निपटा जाए इसके बारे में उनको जानकारी नहीं के बराबर है। इसीलिए बच्चे साइबर अपराधियों के सबसे आसान निशाने पर रहते आए हैं।

यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के चाइल्ड सेफ्टी इंस्टीट्यूट के अध्ययन में यह चिंता पैदा करने वाली जानकारी सामने आई है कि दुनिया में हर एक सेकण्ड में बच्चे की कोई सेक्सुअल तस्वीर डिजिटल दुनिया में प्रकट होती है। इंटरनेट पर अधिक समय बिताना भी बच्चों के लिए बड़ा खतरा बनकर सामने आ रहा है जिसमें वे यौन शोषण, अश्लील तस्वीरों के आदान-प्रदान व साइबर धमकी का सामना करने जैसे मामलों का शिकार हो रहे हैं। इसकी बड़ी वजह भी है। बच्चों के लिए इंटरनेट की आवश्यकता अपनी जगह है। इस आवश्यकता को सिरे से खारिज किया भी नहीं जा सकता। लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय किस तरह की सावधानी बरती जानी चाहिए, इस दिशा पर जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। इसीलिए बच्चे साइबर अपराधियों का आसान निशान बन रहे हैं। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल (सीएसएएम) होस्टिंग के मामले सर्वाधिक एशिया में दर्ज किए जा रहे हैं। जाहिर है, भारत भी ऐसे मामलों से अछूता नहीं है। चिंता इस बात की भी है कि इस तरह के अपराधों का शिकार बालक-बालिकाएं दोनों हो रहे हैं। बच्चों के हाथों में इंटरनेट इस्तेमाल वाले उपकरण कितने जरूरी हैं, यह अभिभावक ही तय कर सकते हैं। पढ़ाई-लिखाई में इंटरनेट का इस्तेमाल जरूरी हो गया है। लेकिन हाथों में मोबाइल व लेपटॉप थामे हमारे बच्चे इस सुविधा का इस्तेमाल करते वक्त ऐसी अवांछित गतिविधियों की चपेट में नहीं आ जाएं, इसका भी ध्यान रखना होगा।

दरअसल , इंटरनेट पर बच्चों के खिलाफ अपराधों के जिस तरह से नित नए तरीके सामने आ रहे हैं उसमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफार्म से दूर रखना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन, बच्चों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ साइबर अपराधियों पर नजर रखने के लिए अधिक मजबूत तंत्र होना ही चाहिए।

ओडिशा : हार-जीत किसी की भी हो, राज्य के विधानसभा चुनाव में बनेगा रेकॉर्ड

भाजपा सत्ता को छीनने और बीजेडी बचाने के लिए लगा रही है पूरा जोर

भुवनेश्वर से
अनंत मिश्रा

ओडिशा में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। सत्तारूढ़ बीजू जनता दल और विपक्षी दल भाजपा दोनों पूर्ण बहुमत हासिल करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन मतदाताओं के मन में क्या है, इसका नतीजा मतगणना के दिन ही आएगा। यह बात जरूर है कि ओडिशा में इस बार का चुनाव परिणाम कोई न कोई रेकॉर्ड जरूर बनाएगा। अगर बीजू जनता दल गढ़ बचाने में कामयाब रहा तो पटनायक देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम बनेंगे। वहीं, अगर भाजपा पूर्ण बहुमत हासिल करती है तो ओडिशा में पहली बार भाजपा की सरकार बनेगी।

जिस तरह देश की जनता यह जानने को उत्सुक है कि क्या नरेन्द्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? ठीक उसी तरह ओडिशा के लोगों में दिलचस्पी इस बात में है कि नवीन पटनायक लगातार छठी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं? जी हां, सवाल दिल्ली में नरेन्द्र मोदी की फिर से ताजपोशी के साथ ओडिशा में नवीन के राजनीतिक भविष्य का जो ठहरा। लोकसभा चुनाव के साथ ओडिशा में हो रहे विधानसभा चुनाव के नतीजे तो चार जून को आएंगे, लेकिन यहां लोगों से शुरू हुई चर्चा के आधार पर यह अवश्य कहा जा सकता है कि 24 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद पटनायक के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती। बातचीत का निचोड़ यह भी निकलता है कि जहां दिल्ली की सत्ता के लिए मोदी पहली पसंद है, वहीं राज्य की सत्ता के लिए नवीन पटनायक के मुकाबले दूसरा कोई नाम नजर नहीं आता।

लगातार ढाई दशक से सत्ता में रहने के बावजूद पटनायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं है? ये सवाल तमाम लोगों से पूछा लेकिन सटीक जवाब दिया राज्य सरकार की सेवा से रिटायर हो चुके भुवनेश्वर के सुकांत महापात्रा ने। बोले, जैसे दिल्ली में फिलहाल मोदी का कोई विकल्प नहीं है, वैसे ही ओडिशा में पटनायक जरूरी हैं। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए सुकांत ने समझाने के अंदाज में कहा, मुफ्त चावल, निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य नवीन बाबू की ऐसी राजनीतिक पूंजी है, जिसका विरोध विपक्ष भी नहीं कर पाता। पुरी के समीप रामचंद्र मंदिर में एक श्रद्धालु विभा पटनायक को विधानसभा चुनाव के बारे में टटोला तो जवाब मिला, पटनायक बाबू न सिर्फ योजनाएं बनाते हैं, बल्कि उनके क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देते हैं। यही कारण है उनके पांच बार जीतने का। उत्तर भारत के राज्यों की तरह सप्ताह भर पहले तक ओडिशा भी तप रहा था, लेकिन चक्रवाती तूफान रेमल के चलते वहां मौसम सुहावना जरूर हुआ है। अलबत्ता चुनाव के आखिरी चरण आते-आते राज्य का राजनीतिक पारा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। दशकों तक राज्य में सत्तारूढ़ रही कांग्रेस स्थानीय राजनीति में अपनी पकड़ गंवा चुकी है। कभी साथ-साथ रहे बीजू जनता दल और भाजपा अब यहां एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी बनकर उभरे हैं। नवीन बाबू की सरकार से लोग संतुष्ट हैं, लेकिन उनकी बढ़ती उम्र और पार्टी में खींचतान के चलते इस बार मुकाबला कड़ा जरूर है। पहले तीन चरणों में मतदान का प्रतिशत ठीक- ठाक रहा। चुनाव जीतने के लिए भाजपा के देशभर से आए नेताओं ने यहां डेरा डाल रखा है। वहीं बीजू जनता दल की कमान पटनायक ने थाम रखी है।

ओडिशा विधानसभा

पटनायक, पंडियन और पार्टी

पिछले 24 साल से सत्ता दल रहा बीजू जनता दल इन दिनों अंदरुनी उठापटक के दौर में है। पटनायक की बढ़ती उम्र के बीच आइएएस सेवा छोड़कर राजनीति में आए वीके पंडियन को ही फिलहाल पटनायक के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन पंडियन अगर पटनायक की ताकत हैं तो पार्टी के लिए वे कमजोरी साबित हो रहे हैं। बीजेडी के तमाम नेता पंडियन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। पार्टी के कई नेता पंडियन की कार्यशैली से नाखुश हैं, मगर पटनायक के सामने बोलने से डरते हैं।

टकराव की राजनीति से दूर

रेलवे से सेवानिवृत्त सुधीर मजूमदार ने पटनायक की सफलता का राज कुछ यूं बताया। कहने लगे -नवीन बाबू का टकराव की राजनीति से दूर रहना ही उनकी कामयाबी का राज है। उनके प्रशसंक भले कम हों, लेकिन उनकी बुराई करने वाला कोई नहीं। पटनायक सामंजस्य की राजनीति में भरोसा करते हैं। राज्य की राजनीति में भाजपा और बीजेडी भले ही विरोधी की भूमिका में खड़े हैं, लेकिन सब जानते हैं कि नवीन पटनायक ने जरूरत के समय मोदी सरकार की राज्यसभा में भरपूर मदद की है। यही कारण है कि दोनों दल शब्दों की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघते। भाजपा की प्राथमिकता जहां लोकसभा चुनाव है, वहीं बीजेडी का सारा जोर राज्य की सत्ता बचाने पर है।

कांग्रेस न तीन में, न तेरह में

दो दशक से सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस राज्य में धीरे-धीरे अपना जनाधार गंवा चुकी है। 2009 के विधानसभा चुनाव में 27 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 2014 के चुनाव में 16 सीटों पर सिमट गई। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी 9 सीटें ही जीत पाई। इस बार भी पार्टी मुकाबले में नजर नहीं आ रही है। ओडिशा में जहां कहीं भी प्रचार सामग्री पर नजर गई तो केवल नवीन पटनायक और पार्टी के चुनाव चिह्न शंख की फोटो ही नजर आई। पटनायक के अलावा किसी नेता का फोटो चुनावी पोस्टरों में नजर नहीं आया।

कानून : आरोप पत्र के लिए गिरफ्तारी जरूरी नहीं

आरोपी को मिलनी चाहिए गिरफ्तारी के आधार की लिखित जानकारी

उच्चतम न्यायालय के दो महत्त्वपूर्ण निर्णय व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता और आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से संबंधित हैं। पहला निर्णय (सिद्धार्थ विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) अगस्त 2021 का है जिसका पालन करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने पुनः निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने निर्देशित किया है कि जब पुलिस किसी मामले में आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल करती है तो यह जरूरी नहीं है कि उसी समय आरोपी को गिरफ्तार कर या अन्यथा आवश्यक रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। दूसरा निर्णय (पंकज बंसल विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य) अक्टूबर 2023 का है जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के आरोपी को गिरफ्तार करने के आधार पर उसे लिखित में सूचित करने से जुड़ा है।

उच्चतम न्यायालय ने सिद्धार्थ प्रकरण में यह स्पष्ट किया कि यदि आरोपी पुलिस को विवेचना में पूरा सहयोग करता है, उसके फरार हो जाने की कोई संभावना नहीं होती और पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती तो कोर्ट बिना आरोपी के आरोप-पत्र लेने से मना नहीं कर सकता। दरअसल, कई मामलों में पुलिस को जमानत देने के अधिकार हैं। कई अजमानतीय मामलों में भी आरोपी की गिरफ्तारी करना कानूनन अनिवार्य नहीं होता। उच्चतम न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 की व्याख्या करते हुए कहा कि कुछ मामलों में यदि विवेचक आरोपी की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं समझता तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय आरोप-पत्र लेने से मना नहीं कर सकते। उच्चतम न्यायालय ने सत्येंद्र कुमार अंटील विरुद्ध सीबीआइ प्रकरण की सुनवाई करते हुए उपरोक्तानुसार पुनः निर्देशों का पालन करने के लिए राज्यों एवं न्यायालयों से पालन प्रतिवेदन चाहे हैं। यदि इन निर्देशों का पालन दृढ़तापूर्वक किया जाता है तो थाना स्तर पर पुलिस अधिकारियों को काफी राहत मिलने की संभावना है। इसी प्रकार मनी-लॉन्ड्रिंग के एक प्रकरण (पंकज बंसल) में निर्णय देते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि आरोपी को गिरफ्तारी के आधारों की लिखित में सूचना देना जरूरी है। गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के एक प्रकरण में निर्णय देते हुए हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने पुनः इस बात को दोहराया कि यूएपीए एवं पीएमएलए में गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देने का प्रावधान एक होने से पंकज बंसल मामले में दिए गए निर्देश यूएपीए के प्रकरणों पर भी लागू होंगे।

आर. के. विज
भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी
@patrika.com

आरोपी को गिरफ्तारी के आधारों की सूचना दी जाए। न्यायालय यह निर्धारित कर चुके है कि यह एक अनिवार्य प्रावधान है एवं इसके पालन के बिना गिरफ्तारी या हिरासत अवैध है।

उपरोक्त विशेष अधिनियमो के अतिरिक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50(1) में भी यह प्रावधान है कि आरोपी को गिरफ्तारी के आधारों की सूचना दी जाए। न्यायालय यह निर्धारित कर चुका है कि यह एक अनिवार्य प्रावधान है एवं इसके पालन के बिना गिरफ्तारी या हिरासत अवैध है। पुलिस द्वारा प्रत्येक गिरफ्तार आरोपी के लिए एक पृथक गिरफ्तारी मेमो तैयार किया जाता है। गिरफ्तारी मेमो में यह अंकित होता है कि 'आरोपी को गिरफ्तारी के आधार बताने के बाद उसे हिरासत में लिया गया'। इसमें अपराध की धाराएं एवं तारीख, गिरफ्तारी का समय व स्थान आदि का भी उल्लेख होता है। गिरफ्तारी मेमो में आरोपी के हस्ताक्षर अवश्य लिए जाते हैं परंतु इसकी एक प्रति आरोपी को तत्काल देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता में गिरफ्तारी का आधार बताने का प्रावधान विशेष अधिनियमों में एक समान है और जमानत लेने के लिए या रिमांड का विरोध करने के लिए गिरफ्तारी के आधार सही तरीके से आरोपी को ज्ञात होना आवश्यक है। इसलिए यदि गिरफ्तारी के आधार लिखित में आरोपी को दिए जाएं तो बेहतर होगा। इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 में आंशिक संशोधन करना होगा जो संवैधानिक प्रावधानों को देखते हुए आवश्यक है।

समाज : वेब सीरीज ने बढ़ाई समस्या

बिंज वॉचिंग भी बन रही है डिप्रेशन का कारण

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
समसामयिक विषयों पर टिप्पणीकार
@patrika.com

बिंज वॉचिंग घर-घर में अपनी जगह बना चुका है। यह नए जमाने का नए तरह का नशा है। ड्रग्स की भाषा में बात करें तो यह डिजिटल ड्रग्स है और किसी अन्य नशे से इसका नशा किसी भी तरह से कमतर नहीं है। मेडिकल की भाषा में कहा जाए तो यह एक तरह की वह बीमारी है जिसे मनोचिकित्सक साइकोसोमैटिक डिसआर्डर कह कर पुकारने लगे हैं।

आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो बिंज वॉचिंग का सीधा-सीधा अर्थ है किसी सीरीज या इसी तरह के कार्यक्रम, गेम आदि को एक ही सीटिंग में पूरा करने की जिद या सीरियल या वेब सीरीज के उपलब्ध सारे एपिसोड देखने का जुनून। यह एक प्रकार की लत है और ओटीटी प्लेटफार्म के आने के बाद इसका प्रभाव अधिक ही हो गया है। वेब सीरीज ने इसे और अधिक लोकप्रिय बना दिया है तो वीडियो गेम खासतौर से मोबाइल के गेम और इसी तरह के कार्यक्रम, सोशल मीडिया जिसमें सेल्फी लेने की लत तो रील्स बनाने, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपलोड करने और उन पर आने वाली प्रतिक्रियाओं को लेकर तनाव में रहना एक तरह से इसी श्रेणी में रखा जा सकता है।

बिंज वॉचिंग शब्द पहली बार 2003 में चलन में आया पर 2013 में यह अधिक लोकप्रिय हुआ। कोरोना काल में खासतौर से लॉकडाउन के कालखण्ड में बिंज वॉचिंग और भी अधिक पांव पसारने में सफल रही। देखा जाए तो दूसरे नशों की तरह ही इस तरह की लत व्यक्ति के दिमाग पर सीधा असर करती है। इसके चलते व्यक्ति में एकाकीपन, चिडचिड़ापन अनिद्रा, दैनिक व्यवहार में बदलाव यहां तक कि डिप्रेशन के हालात तक होने लगे हैं। बिंज वॉचिंग या यों कहें कि डिजिटल ड्रग्स की समस्या को खारिज नहीं किया जा सकता। यह जिस तरह से व्यक्ति के दिलो-दिमाग को प्रभावित कर रही है, वह अपने आप में गंभीर है। ऐसे में समय रहते कोई समाधान खोजना होगा। हर वर्ग इसकी चपेट में है, लेकिन बच्चे जिस तेजी से इसके शिकार हो रहे हैं, उससे समस्या ज्यादा गंभीर होती जा रही है।

पर्यावरण : पिछले कुछ सालों में कृषि भूमि पर अंधाधुंध निर्माण हुआ, इसके लिए छायादार पेड़ों को भी काटा गया

छायादार पेड़ों की कटाई, सब पर अब पड़ रही है भारी

अतुल कनक
लेखक और साहित्यकार
@patrika.com

यदि छायादार पेड़ों को नहीं बचाया गया तो हम जैव विविधता को संरक्षित रखने में भी विफल रहेंगे। मुश्किल यह है कि हमारा समाज अब भी इस विषय पर उदासीन बना हुआ है।

इस साल मई के अंतिम सप्ताह में उत्तर और मध्य भारत के अधिकांश शहरों में तापमान ने पिछले कई सालों का रेकॉर्ड तोड़ दिया। मई के अंतिम दिनों में सूर्य ने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया। आम बोलचाल की भाषा में ये नौतपा के दिन कहे जाते हैं और मान्यता है कि नौतपा के दौरान तापमान सामान्य से अधिक होना अच्छे मानसून का संकेत होता है। लेकिन इन दिनों धरती जिस तरह तप रही है, वह असामान्य है। एक बड़ा कारण यह भी है कि हमारे शहरों से छायादार वृक्ष तेजी से गायब होते जा रहे हैं।

छायादार पेड़ हमारे जीवन में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल हमें फल और औषधि देते हैं , अपितु अनेक जीवों को अपने आश्रय में स्थान देकर पर्यावरण के संरक्षण में भी योगदान करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि हमारे घरों के आसपास हमेशा फुदकने वाली गौरैया की चहचहाट अचानक कहां गुमने लगी है या गुम हो गई है? छायादार पेड़ों का कटना जैव विविधता की दृष्टि से बड़ी चुनौती बन गया है। पिछले दिनों डेनमार्क के कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के कुछ शोधार्थियों ने भारत के साठ करोड़ पेड़ों का एक मानचित्र बनाया और उनके बारे में अध्ययन किया। इस अध्ययन की रिपोर्ट नेचर सस्टेनेबिलिटी नामक एक अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका में छपी है। इस अध्ययन में सामने आया है कि सन् 2018 से 2022 के बीच भारत के खेतों से 53 लाख छायादार पेड गायब हो गए हैं। आम, नीम, पीपल, बरगद, महुआ, जामुन, कटहल, खेजड़ी, शीशम, नारियल जैसे पेड़ हैं जिनमें से कई पेड़ों का मुकुट 67 वर्ग मीटर या उससे भी अधिक था।

इस वर्ष मई के तीसरे सप्ताह में ही जिस तरह से पश्चिम और मध्य भारत के शहरी इलाके तपने लगे , उसने आम आदमी में यह चिंता जगा दी है कि आने वाले समय में गर्मी कितनी कठिन होगी। हमारे पूर्वज पेड़ों के महत्त्व को समझते थे। इसीलिए भारतीय वांग्मय में छायादार पेड़ों को बहुत पवित्र माना गया है। गीता में तो कृष्ण स्वयं को पेड़ों में अश्वत्थ यानी पीपल बताते हैं। पुराने ग्रंथों में पीपल, बड़ जैसे पेड़ों की महत्ता विस्तार से लिखी गई है। वनस्पति के प्रति भारतीय मानस के मन में सम्मान की परंपरा का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब किसी काम से पेड़ की लकड़ी के एक हिस्से या थोड़ी सी जड़ भी लेनी होती थी तो शास्त्रों का निर्देश था कि पहले पेड़ की पूजा करो और फिर क्षमा मांग कर उस चीज को प्राप्त करो। पेड़ों की पूजा किसी दकियानूसी मानसिकता का परिणाम नहीं था बल्कि प्रकृति की उस रचना के प्रति मनुष्य का आभार व्यक्त करना था जो फल, छाया, लकड़ी, गोंद जैसी कितनी ही चीजों के साथ हमारे कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहती है।

कोपनहेगन विश्वविद्यालय के जिन शोधार्थियों ने यह पाया है कि 1918 से सन् 1922 के बीच भारतीय खेतों से 53 लाख से भी अधिक छायादार पेड़ कट गए, उन्होंने अपने अध्ययन में उन वृक्षों का तो जिक्र ही नहीं किया जो खेतों से इतर जगहों पर थे और विकास के नाम पर नेस्तनाबूद कर दिये गए। रिपोर्ट के अनुसार कुछ इलाकों में तो एक किलोमीटर में पचास से अधिक पेड़ की दर से घने छायादार पेड़ काटे गए हैं। यह स्थिति किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को डरा सकती है। शहरीकरण के कारण पिछले कुछ सालों में कृषि भूमि पर अंधाधुंध निर्माण हुआ है और इसी क्रम में घने छायादार पेड़ों को भी निर्ममता से काटा गया है। खेतों में खड़े पुराने छायादार पेड़ों के गायब होने का यह एक बड़ा कारण है।

एक शायर ने कहा है कि 'फल नहीं देगा, न दे- छाया तो देगा मुझे/ पेड़ बूढ़ा ही सही घर में लगा रहने दो', तो मुनव्वर राणा ने लिखा- 'हम छायादार पेड़ जमाने के काम आए/ जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए।' पेड़ किसी बुजुर्ग की तरह समाज के हित का संरक्षण करते हैं। वृक्षारोपण को हमारे समय की बड़ी आवश्यकता माना जाता है। बड़ी संख्या में छायादार पुराने पेड़ों का इतनी तेज गति से काटा जाना किसी भी समाज के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। मुश्किल यह है कि हमारा समाज अभी इस विषय में उदासीन बना हुआ है। यदि छायादार पेड़ों को नहीं बचाया गया तो हम न केवल जैव विविधता को संरक्षित रखने में विफल रहेंगे बल्कि अपने पर्यावरण से खिलवाड़ करने के भी अपराधी साबित होंगे। इसके के लिए हमारी पीढ़ियां शायद हमें माफ नहीं कर सकें।

यूरोप में रूसी दुष्प्रचार, दूसरे देश भी रहें सावधान

ली हॉकस्टेडर
यूरोपीय मामलों के स्तंभकार
द वाशिंगटन पोस्ट
से विशेष अनुबंध के तहत

दुष्प्रचार, हेराफेरी और द्वेष की समस्या सर्वव्यापी है।एआइ ने इस समस्या को गंभीर बना दिया है।

रूसी दुष्प्रचार पर नजर रखने वाले यूरोपीय मॉनिटरों ने वर्ष 2022 में, एक महत्त्वाकांक्षी ऑनलाइन इन्फ्लुएंस ऑपरेशन देखा, जिसे उन्होंने डोपेलगैंगर कहा। मास्को द्वारा संचालित इस अभियाान ने ब्रिटेन के गार्जियन और जर्मनी के बिल्ड सहित वैध समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और समाचार सेवाओं की वेबसाइटों की क्लोनिंग की, समान डोमेन नामों के तहत प्रतिकृतियां पोस्ट कीं ।

पश्चिमी जनमत में हेरफेर करने के रूस के प्रयासों को देखते हुए यह अभियान चौंकाने वाला नहीं था। अधिक आश्चर्य की बात यह है कि, उनका पता चलने के कम से कम दो साल बाद, उन्हें बंद करने के चल रहे प्रयासों के बावजूद डोपेलगैंगर की खूब सारी नकली साइटें इंटरनेट पर दिखाई दे रही हैं। यूरोपीय संसद के लिए अगले महीने होने वाले चुनावों से पहले इसे रोकना तो दूर, इसकी निगरानी करना भी लगभग असंभव है। यह इस बात का भी पूर्वाभास है कि अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में मास्को अमरीकी राजनीति के जहरीले शोर को बढ़ाने की कोशिश करेगा। सोशल मीडिया ने दुष्प्रचार और प्रचार का वितरण लगभग निःशुल्क कर दिया है। एआइ ने इसके उत्पादन की लागत कम कर दी है। यूरोपीय संसद के लिए मतदान 6 से 9 जून के बीच होगा। मतदान से इस बात का पुख्ता सबूत नहीं मिलेगा कि रूसी साजिश ने मास्को के प्रति सहानुभूति रखने वाली पार्टियों को मजबूत किया है और यूक्रेन के लिए पश्चिमी समर्थन का विरोध किया है।

दुष्प्रचार, हेराफेरी और द्वेष की बाढ़ सर्वव्यापी है। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से मिलती जुलती वेबसाइट पर यह घोषणा की गई कि यूक्रेन में सेवा के लिए 200,000 फ्रांसीसी रंगरूटों की मांग की जाएगी। डोपेलगैंगर ऑपरेशन के अस्तित्व का खुलासा करने वाले नागरिक समाज समूह, ईयू डिसइंफोलैब के कार्यकारी निदेशक एलेक्जेंडर अलाफिलिप्पे ने बताया कि मामला उजागर होने के बाद भी इसका लचीलापन और दृढ़ता एक चिंताजनक संकेत है। अलाफिलिप्पे ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि क्या रूस यूरोप में प्रचार युद्ध जीत रहा है। सवाल यह है कि क्या हमारे पास लोकतांत्रिक सुरक्षा उपाय हैं? यदि यूरोप में उत्तर नहीं नजर नहीं आ रहा तो अन्यत्र तस्वीर और भी गंभीर दिखाई देगी।

आज का सवाल

गर्मी से हो रही मौतों को कैसे रोका जा सकता है?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

स्वास्थ्य पर भी असर

एसी का उपयोग करने से उसमें से जहरीली गैसें निकलती हैं, जो पर्यावरण के लिए घातक होती हैं। लंबे समय तक एसी का इस्तेमाल करने से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
-**रितिका गुप्ता,** दमोह, म.प्र.

ज्यादा पेड़ लगाएं

पर्यावरण पर असर की बात करें तो एसी से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है। बेहतर तो यह है कि गर्मी से बचने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए।
-**चांदनी श्रीवास्तव,** रायपुर, छत्तीसगढ़

पर्यावरण को नुकसान

एसी के इस्तेमाल से पर्यावरण पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। वातावरण में गर्मी बढ़ रही है। हीटवेव की तीव्रता बढ़ रही है। श्वास संबंधी बीमारियां हो रही हैं।
-**याकूब मोहम्मद,** उदयपुर

बिजली की बढ़ रही खपत

एसी का इस्तेमाल बढ़ने से बिजली की खपत बढ़ रही है। ट्रांसफार्मर बार-बार जल रहे हैं, जिसके कारण से बिजली बंद हो रही है। शरीर को भी नुकसान हो रहा है।
-**सुरेंद्र बिंदल,** जयपुर

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'एसी का इस्तेमाल बढ़ने का क्या असर हो रहा है?' ऑनलाइन भी देखें।

इसे स्कैन करें

rb.gy/m2zage

दिल्ली में अग्निकांड

प्रशासन जिम्मेदार

दिल्ली के अग्निकांडों में 10 लोगों की मौत चुनाव प्रचार में व्यस्त मुख्यमंत्री केजरीवाल के प्रशासन पर सवाल खड़े करती है। यह अत्यधिक भयानक त्रासदी तथा सिविल अधिकारियों का अक्षम्य अपराध है कि दिल्ली में हुए अग्निकांडों में 10 लोगों को अपने जीवन से हाथ धोने पड़े हैं। शनिवार की रात पूर्वी दिल्ली में बच्चों के अस्पताल में आग लगी जिसमें सात बच्चों की मृत्यु हुई। रविवार तड़के इसी जिले में हुई दूसरी दुर्घटना में एक आवासीय इमारत में लगी आग में तीन लोगों को जान से हाथ धोने पड़े। सात मासूम बच्चों की जान लेने वाली अस्पताल की आग हृदयविदारक है। इन त्रासदियों की शिकार राजधानी दु:ख में डूबी है। उसे अपना आत्मावलोकन करना चाहिए। दिल्ली की घटनायें गुजरात में हुए भयानक अग्निकांड के फौरन बाद हुए हैं जिनमें एक 'गेमिंग आर्केड' में 27 बच्चे जिन्दा जल गए थे। यह बात समझ में आती है कि गर्मी में दिल्ली में अग्निकांडों की आशंका बढ़ जाती है। लेकिन आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू होने और जवाबदेही तय होने से पहले दिल्ली सरकार को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और मानव जीवन से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रथमदृष्टया भूतल में आक्सीजन सिलिंडर भंडारण में घोर लापरवाही के कारण शार्ट सर्किट से भयंकर आग फैल गई। लगता है कि 'सुरक्षा प्रोटोकाल' केवल कागजों पर रहते हैं और अधिकारी इनको क्रियान्वित करने की चिन्ता नहीं करते हैं। अक्सर अनिवार्य सुरक्षा उपायों वाले 'अग्नि-प्रोटोकालों' का धड़ल्ले से उल्लंघन होता है तथा 'फायर ड्रिल' कभी नहीं होती हैं। एक अत्यधिक भयानक मामले में पूरा परिवार बिजली शार्ट सर्किट के कारण लगी आग में मौत का शिकार हो गया। अग्निशामक दस्तों तथा वाहनों को संकरी सड़कों और कुछ क्षेत्रों में पानी की भारी कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वे जनहानि व संपत्ति का नुकसान नहीं रोक पाते हैं।

इन त्रासद दुर्घटनाओं के बाद जनता बेहतर सुरक्षा मानकों तथा वर्तमान कानूनों के बेहतर क्रियान्वयन की मांग कर रही है। जनता के गम और गुस्से के बीच केजरीवाल की अनुपस्थिति पर भी ध्यान गया है। वर्तमान समय में अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद वे पंजाब में चुनाव अभियान में लगे हैं। ऐसे में जेल से दिल्ली सरकार चलाने का उनका दावा हास्यास्पद लगता है। वर्तमान तकनीक को देखते हुए भले ही यह तकनीकी रूप से संभव हो, पर वे जमीनी यथार्थ से कटे हैं जो तत्काल प्रत्यक्ष प्रशासन की मांग करता है। एक अन्य राज्य में मुख्यमंत्री के चुनाव प्रचार में व्यस्तता से चिन्ता पैदा होती है कि उनकी प्राथमिकता क्या है? क्या वे भौतिक रूप से अपने घर व कार्यालय से दूर रह कर दिल्ली की तात्कालिक आवश्यकतायें पूरी कर सकते हैं? इन दु:खद घटनाओं की जिम्मेदारी बहुआयामी है। एक ओर तात्कालिक कारण व्यवस्था संबंधी मुद्दे हैं, वहीं दूसरी ओर शहर के प्रशासन और नेतृत्व की व्यापक जवाबदेही है। विडंबना है कि चाहे घाटकोपर त्रासदी हो, गेमिंग आर्केड की आग हो या दिल्ली के अग्निकांड, हम ऐसी दुर्घटनाओं से कोई सबक नहीं लेते हैं। शुरुआती शोर-शराबे के बाद चीजें फिर पहले जैसी हो जाती हैं। समय आ गया है कि हम कम से कम अस्पतालों और स्कूलों में समुचित फायर आडिट सुनिश्चित करें ताकि बच्चों का जीवन संकट में न पड़े। उम्मीद करनी चाहिए कि 'एक्टिविस्ट मुख्यमंत्री' समुचित कार्रवाई करेंगे और बहुत देर होने से पहले राजधानी में स्थितियां सुधरेंगी।

टैगोर पर भगवान बुद्ध का प्रभाव

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर अहिंसा तथा सभी जीवों के सम्मान की भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। ये शांति व सद्भावना की इच्छा रखने वाली दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण हैं।

राजदीप पाठक
(लेखक, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति से संबद्ध हैं)

नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर अहिंसा तथा सभी जीवों के सम्मान की भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। यह प्रभाव उनकी अनेक रचनाओं में अभिव्यक्त होता है जिसमें कई नाटक भी शामिल हैं। भगवान बुद्ध की ये शिक्षायें शांति व सद्भावना की इच्छा रखने वाली दुनिया में आज भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। हजारों सालों में हुए अनेक परिवर्तनों तथा विज्ञान एवं तकनीक की प्रगति व खासकर पश्चिमी दुनिया में भौतिकवाद के बढ़ते वर्चस्व के बीच भी समकालीन दुनिया में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की प्रासंगिकता बनी हुई है।

भगवान बुद्ध के अहिंसा व सहानुभूति के सिद्धान्त वर्तमान समय की ऐसी दुनिया में ज्यादा सामंजस्य का मार्ग दिखाते हैं जो अक्सर टकरावों का शिकार बनती है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में सभी प्रकार के जीवों के प्रति प्रेम व सहानुभूति तथा संपूर्ण जीवजगत की परस्पर निर्भरता पर जोर दिया गया है। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित ये सिद्धान्त वर्तमान पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण हैं। उल्लेखनीय है कि सारी दुनिया के समक्ष मौजूद पर्यावरणीय संकट न केवल मानवजाति, बल्कि संपूर्ण जीवजगत और इस पृथ्वी ग्रह के अस्तित्व को ही खतरे में डाल रहे हैं। इन मूल्यों को स्वीकार करने से टिकाऊ व्यवहारों तथा प्रकृति के साथ गहरे संबंधों को बढ़ावा मिलता है। भगवान बुद्ध के 'अष्टांग मार्ग' में रेखांकित नैतिक जीवनशैली का महत्व वैयक्तिक, पेशेवर व सामाजिक संदर्भ में प्रासंगिक है जो सहयोग तथा निष्ठा को बढ़ावा देता है।

इस दर्शन का अनुसरण करने वालों में वियतनामी जेन मास्टर थिच न्हाट हान एलियास शामिल हैं। उन्होंने अहिंसा, सहानुभूति तथा विचार का महत्व विश्व शांति के लिए रेखांकित किया है। उनके 'समाहित बौद्धवाद' में दिन प्रतिदिन के जीवन तथा सोशल एक्टिविज्म में सम्यक विचार को समाहित करने की शिक्षा है। इसमें टकरावों के समाधान तथा पर्यावरण की देखभाल को समुचित महत्व दिया गया है। उनकी शिक्षाओं में गहन रूप से सुनने तथा प्रिय भाषण शामिल हैं जो विभाजनों को पाटने तथा समुदायों को शांति प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार तिब्बती धर्मगुरु दलाईलामा ने अंतरधार्मिक संवाद, सहानुभूति एवं नैतिक दायित्व पर जोर दिया है जिससे मानवाधिकारों तथा टिकाऊ विकास के लिए वैश्विक आंदोलनों को प्रेरणा मिली है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने बौद्ध धर्म से प्रेरणा प्राप्त की थी जो उनकी रचनाओं में स्पष्ट दिखती है। विश्व मानववाद का उनका दृष्टिकोण बुद्ध की सहानुभूति तथा प्रेम व दया की शिक्षाओं से जुड़ा है। टैगोर की रचनाओं का संबंध आमतौर से आंतरिक शांति व आत्म-स्वीकृति से है जो बौद्ध धर्म की अवधारणाओं पर आधारित है। शिक्षा के प्रति उनके समग्र दृष्टिकोण में भी व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास पर जोर दिया गया है जो बौद्ध धर्म में 'विवेक के विकास' पर केन्द्रित है। बुद्ध की शिक्षाओं में समावेशन, सहानुभूति तथा प्रत्येक को जागरूक करने की अंतर्निहित क्षमताओं पर जोर दिया गया है, भले ही किसी का सामाजिक स्तर चाहे जो हो। उन्होंने जाति व्यवस्था को अस्वीकार करते हुए जन्मजात अधिकार पर नैतिक व्यवहार को वरीयता दी थी। ब्रिटिश इतिहासकार और लेखक करेन आर्मस्ट्रांग के अनुसार, बुद्ध ने जाति व्यवस्था को स्वीकृति न देकर अपने समय के धार्मिक व सामाजिक मानकों को चुनौती दी। बौद्ध भिक्षुओं के समुदाय में भी 'संघ' में सभी पृष्ठभूमियों के लोगों का स्वागत कर आध्यात्मिक समानता तथा समावेशन को महत्व दिया गया है। अपने एक नाटक 'चंडालिका' में टैगोर ने प्रकृति के चरित्र से खुलेपन की अवधारणा व्याख्यायित की है। इसमें प्रकृति अश्पृश्य जाति की एक महिला तथा आनन्द प्रख्यात बौद्ध भिक्षु हैं। बौद्ध अभिलेखों से प्रेरणा प्राप्त कर टैगोर ने उस विमर्श की कल्पना की है जिसमें सामाजिक विभाजनों के खिलाफ निरंतर संघर्ष को बढ़ावा दिया गया है। इसका संबंध खासकर प्राचीन भारत में अश्पृश्यों के ऐतिहासिक उत्पीड़न से है। आनन्द द्वारा विनम्रता से प्रकृति से जल स्वीकार कर जातीय पूर्वाग्रहों को अस्वीकार करते हुए उसकी आंतरिक गरिमा को स्वीकार किया गया है।

प्रकृति द्वारा आनन्द में प्रेम की भावना को अस्वीकार करने के बावजूद बुद्ध की शिक्षाओं में दृढ़ विश्वास आनन्द की पवित्रता को रेखांकित करता है। अंतत: ईश्वरीय हस्तक्षेप आनन्द को इस आकर्षण से मुक्ति दिलाता है। इस प्रकार यह भौतिक इच्छाओं पर आध्यात्मिक निष्ठा की विजय का प्रतीक है। यह बौद्ध धर्म में 'ध्यान' का एक चरित्र है। टैगोर के काव्यात्मक गद्य से यह कहानी विमर्श की सीमाओं को तोड़ते हुए प्रेम की स्थाई शक्ति को गहन ध्यान में बदलती है। इस प्रकार यह जागरण व आत्माभिव्यक्ति के माध्यम से सभी आत्माओं से जुड़ती है। भगवान बुद्ध की यह विरासत उनके अनुयाइयों को सामाजिक बाधाओं से मुक्त होने, एक 'संघ' बनाने तथा शांति के संदेशवाहक बनने की प्रेरणा देती है।

रवीन्द्रनाथ टैगोर ने 'प्रकृति' के चरित्र का विकास कर उसे सामाजिक मानकों पर सवाल उठाने को प्रेरित करते हैं। इन सामाजिक मानकों से महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित होती है तथा इस प्रकार वह अपनी पहचान पुन: बहाल करती है। इस प्रयास में आनन्द का सहानुभूति वाला दृष्टिकोण वैसे तो बौद्ध दर्शन का विशिष्ट चरित्र है, पर यह प्रकृति में आत्माभिव्यक्ति की भावना प्रज्वलित कर इस तथ्य पर जोर देता है कि सभी मनुष्य मूलभूत रूप से समान हैं। प्रकृति द्वारा आनन्द की अंजलि में पीने के लिए डाला गया पानी उसकी पवित्रता और प्रेम का प्रतीक है। इसके साथ ही वह असीम उदारता और मानवता का भी प्रतीक है। इस प्रकार रवीन्द्रनाथ टैगोर प्रतीकात्मक एकता या उत्थान के माध्यम से आध्यात्मिकता एवं अश्पृश्यता की भावना प्रकृति व आनन्द के माध्यम से व्यक्त करते हैं।

यह एकता पुरुष एवं महिला के बीच, पवित्रता एवं अशुद्धता के बीच तथा आध्यात्मिकता एवं सहानुभूति के बीच समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है। रवीन्द्रनाथ टैगोर इस समन्वय या सम्मिलन का प्रयोग एक संतुलित एवं सभ्य समाज को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने सहानुभूति या करुणा तथा सभी जीवधारियों के प्रति प्रेम एवं दया या 'मित्त' का प्रयोग समुदाय में संवेदना व सहायता की पैरवी के लिए किया है। उनकी यह भावना खासकर उन समुदायों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो किसी प्रकार के टकरावों का शिकार हैं अथवा किसी कारण से हाशियाकृत हो गए हैं।

भगवान बुद्ध के पहले 'परम सत्य' में 'दु:ख' को संबोधित किया गया है। इसमें पीड़ा के वैश्विक मानवीय अनुभव को रेखांकित करते हुए प्रत्येक को इससे मुक्ति दिलाने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। इस पर वियतनामी विचारक थिच न्हाट हान ने अपनी रचना 'द हार्ट आफ बुद्धाज़ टीचिंग्स' में कहा है कि 'पीड़ा को समझने से सहानुभूति में वृद्धि होती है, सद्भावना पैदा होती है तथा समझदारी बढ़ती है।' सम्यक आजीविका व नैतिक व्यवहार पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं ने सामाजिक न्याय तथा न्यायोचित व्यवहार को प्रोत्साहन दिया। इससे सारी दुनिया के स्तर पर ज्यादा समावेशी तथा सद्भावनापूर्ण समाज बनाने में सहायता मिली। बौद्ध दर्शन में 'मध्यम मार्ग' अतिवाद से बचने तथा संतुलन खोजने की सलाह देता है।

यह सिद्धान्त रवीन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं में दिखाई देता है। उदाहरणार्थ अपने नाटक 'द किंग इन डार्क चैंबर' या बांग्ला भाषा में 'राजा' में टैगोर ने जीवन में प्रकाश एवं अंधकार तथा अज्ञान एवं ज्ञान के बीच निरंतर जारी टकराव की भावना को अभिव्यक्त किया है। इस प्रकार यह नाटक भगवान बुद्ध द्वारा सामंजस्य या 'सम्यक जीवन' की खोज की प्रस्तुति करता है। इस नाटकीय यात्रा का मुख्य चरित्र जीवन के अंधकारमय एवं प्रकाशित आयामों को अच्छी तरह समझते हुए संतुलन बनाए रखने के लिए मध्य मार्ग पर जोर देता है।

ई-कचरा संकट पर अंकुश आवश्यक

शाइनी शर्मा
(लेखिका, शिक्षाविद हैं)

"उपभोक्ता अक्सर अपने गैजेट को अपग्रेड करते रहते हैं जिससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का टर्नओवर बहुत बढ़ जाता है।"

आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति के साथ, कंप्यूटर और अन्य मोबाइल डिवाइस हर किसी के काम और व्यक्तिगत जीवन का इतना अभिन्न अंग बन गए हैं कि उनके बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही ई-कचरे की समस्या हर साल बढ़ती जा रही है क्योंकि उपभोक्ता अक्सर अपने गैजेट को अपग्रेड करते रहते हैं जिससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का टर्नओवर बहुत बढ़ जाता है।

ई-कचरा या इलेक्ट्रॉनिक कचरा उन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उपकरणों को संदर्भित करता है जो अपने उपयोगी जीवन के अंत तक पहुँच चुके हैं या अब उनके मालिकों को नहीं चाहिए। यह अपनी जटिल संरचना, तेजी से उत्पादन और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए चुनौतियों के कारण महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है। बैटरी और सेमीकंडक्टर में मौजूद सीसा, पारा और कैडमियम जैसे विभिन्न विषाक्त पदार्थों की उपस्थिति के कारण तंत्रिका संबंधी क्षति हो सकती है और गुर्दे और हड्डियों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इतना ही नहीं ऐसे कचरे से निकलने वाले जहरीले रसायन मिट्टी में मिल सकते हैं, जिससे यह बंजर और कृषि के लिए असुरक्षित हो जाती है।

न केवल मिट्टी दूषित होगी बल्कि पर्यावरण के अन्य स्रोत जैसे पानी और हवा भी बुरी तरह प्रभावित होंगे क्योंकि ई-कचरे का अनुचित निपटान जल निकायों को दूषित कर सकता है जिससे जल आपूर्ति और जलीय जीवन प्रभावित हो सकता है और मूल्यवान धातुओं को निकालने के लिए छोड़े जाने वाले जहरीले धुएं से श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि हवा में मौजूद विषाक्त पदार्थ लंबी दूरी तक जा सकते हैं,

जिससे वायु की गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है। कई विकासशील देशों में अक्सर अनौपचारिक ई-कचरा रीसाइक्लिंग गतिविधि आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती है। ऐसी गतिविधियां अक्सर अनियमित होती हैं और श्रमिक पर्याप्त सुरक्षा के बिना उच्च स्तर के विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आते हैं। इस संपर्क से श्वसन संबंधी समस्याएं, त्वचा संबंधी विकार और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ई-कचरे का अनुचित निपटान और रीसाइक्लिंग ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान देता है जिससे पर्यावरण क्षरण और कार्बन फुटप्रिंट में वृद्धि होती है। ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2020 के अनुसार, दुनिया ने 2019 में 53.6 मिलियन मीट्रिक टन ई-कचरा उत्पन्न किया और यह आँकड़ा 2030 तक 74.7 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ने की उम्मीद है। इस कचरे का केवल एक अंश ही ठीक से रिसाइकिल किया जाता है, और बहुत सारा कचरा लैंडफिल में चला जाता है, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होता है। ऐसे कचरे का उचित रिसाइकिल ही एकमात्र उपाय है जो मूल्यवान सामग्रियों को पुन: प्राप्त करने और नए संसाधन निष्कर्षण की आवश्यकता को कम करने में मदद कर सकता है और यह तभी संभव है जब सरकार ई-कचरा प्रबंधन के लिए कड़े नियम बनाए और लागू करे, जिसमें उचित संग्रह, रिसाइकिलिंग और निपटान अभ्यास जैसे कि ई-कचरा संग्रह अभियान और रिसाइकिलिंग केंद्र शामिल हैं, ताकि उचित निपटान की सुविधा मिल सके। निर्माताओं को अपने उत्पादों के पूरे जीवनचक्र के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जिसमें टेक-बैक प्रोग्राम और रिसाइकिलिंग पहल शामिल हैं।

उन्नत रिसाइकिलिंग तकनीकों में निवेश करने से ई-कचरे से मूल्यवान सामग्री निकालने की दक्षता और सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिल सकती है। निर्माताओं को ऐसे उत्पाद डिजाइन करने के लिए प्रोत्साहित करना जिन्हें रिसाइकिल करना, मरम्मत करना और अपग्रेड करना आसान हो, ई-कचरा उत्पादन को कम कर सकता है। साथ ही उपभोक्ताओं को उचित ई-कचरे के निपटान और उपलब्ध रीसाइक्लिंग विकल्पों के महत्व के बारे में शिक्षित करने से अनुचित निपटान प्रथाओं को कम किया जा सकता है।

ई-कचरे के प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित करने से दुनिया भर में सुरक्षित और कुशल रीसाइक्लिंग प्रथाओं को सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। विकासशील देशों में ई-कचरे के अवैध निर्यात को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय नियमों को मजबूत करना, जहां इसे अक्सर असुरक्षित तरीके से संसाधित किया जाता है। याद रखें, गैजेट से लेकर हरित पहल तक, इस ग्रह पर रहने वाले हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से अपने ई-कचरे को रीसाइकिल करना चाहिए और एक स्वच्छ और हरित कल का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।

आप की बात

अखिलेश के बयान

चुनाव के अंतिम चरण में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि जहाँ दिखे भाजपाई वहां बिछाओ चारपाई और उन्हें उस पर बिठाकर नौ सवाल पूछो। क्यों पेपर लीक हुए? क्यों युवाओं की नौकरी छीनी जा रही है? क्यों जातिगत जनगणना का विरोध किया जा रहा है? क्यों आरक्षण खत्म किया जा रहा है? क्यों महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को बचाया जा रहा है? विडंबना है कि सपा की यह आक्रामकता युनाव के इस अंतिम चरण में क्यों दिख रही है? यदि अखिलेश यादव ने चुनाव शुरू होते ही मतदाताओं को यह निर्देश दे दिया होता और उसका जमीनी स्तर पर जारी भी क्रियान्वयन हुआ होता तो शायद आज पक्ष-विपक्ष के बीच चुनाव में एजेंडा ही कुछ और होता। सपा अध्यक्ष पूरे जोर से कहते रहे हैं कि इंडिया गठबंधन प्रदेश की 79 सीटों पर जीतने जा रहा है। अब वे कहने लगे हैं कि विपक्षी गठबंधन सभी सीटों पर जीत रहा है और भाजपा को 140 से अधिक सीटें मिलने वाली नहीं हैं। उनके ये बयान भले ही कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने या भीड़ जुटाने में कुछ काम आते हों, पर इन पर शायद ही किसी को विश्वास हो। अंतिम चरण के पहले उन्होंने बसपा को भाजपा की बी टीम बता दिया, जबकि अब तक वे बसपा के मामले पर चुप थे।

– **शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

गर्मी का प्रकोप

साल दर साल गर्मी अपनी प्रचंडता बढ़ती जा रही है। अमीर वर्ग तो एसी कूलर में अपना बचाव कर लेते हैं। मगर खुले में कामकाज करने वाले, हाथ ठेला लेकर सब्जी बेचने वाले, अटाला खरीदने वाले, मजदूरी करने वाले व अनेक ऐसे ही लोग इस भीषण गर्मी में भी सड़कों पर निकलने को मजबूर हैं। प्रशासन ने 12 से 3 बजे तक बाहर नहीं निकलने की सलाह तो दे दी है, मगर रोज कमा कर खाने वालों के लिए यह सलाह रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकती है। ऐसी सलाह देने वाले अधिकारियों ने एक स्थान पर वन दरोगा की परीक्षाओं का आयोजन कर दिया जिसमें 25 किलोमीटर दौड़ लगाना भी शामिल था। इसमें एक युवा की मृत्यु हो गई और कई बीमार हो गए। ऐसी संवेदनहीन कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को दंड दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही दिन-रात ग्राहकों की सेवा में दौड़ने वाले गिग वर्कर्स खाने-पीने का व अन्य सामान पहुंचाने में लगे रहते हैं। उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। बढ़ती गर्मी को देखते हुए अब सरकार को बहुत खराब मौसम में कार्यदिवस का समय बदलने पर भी विचार करना चाहिए। इतनी गर्मी में मतदान कराने एवं चुनाव व्यवस्था में लगे लोगों का विशेष साधुवाद।

– **सुभाष बुडावन वाला,** रतलाम

अनावश्यक सवाल

चुनाव आयोग को बार-बार ईवीएम की सुरक्षा और पारदर्शिता पर सफाई देनी पड़ रही है। चुनाव आयोग ने पहले ही सभी प्रत्याशियों को मशीन से जुड़ी पूरी जानकारी दी है। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय भी ईवीएम की सुरक्षा पर अपनी मुहर लगा चुके हैं। चुनाव आयोग ने सभी आवश्यक उपाय किए हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे। ईवीएम की विश्वसनीयता पर बार-बार संदेह से भारतीये लोकतंत्र की नींव कमजोर होगी। चुनाव आयोग देश भर में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए दिन-रात मेहनत करता है। विपक्षी दलों को चाहिए कि वे ईवीएम या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा कर अपनी ऊर्जा बरबाद न करें। विपक्षी दल चुनाव प्रक्रिया में सुधारों के लिए रचनात्मक सुझाव देने चाहिए। ईवीएम का उपयोग अनेक चुनावों में हुआ है और इसने हमारी चुनाव प्रक्रिया को तेज व निष्पक्ष बनाया है। विपक्षी दल चुनाव जीतने पर ईवीएम व चुनाव आयोग पर कुछ नहीं बोलते हैं, पर हारने पर इन्हीं पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं। आम जनता अब उनके इस विलाप की असलियत समझ चुकी है और उनके तर्कों से किसी प्रकार भ्रमित होने वाली नहीं है।

– **अवनीश गुप्ता,** आजमगढ़

पर्वतारोही महिलायें

टाइम ऑन रॉक पुस्तक के माध्यम से महिला पर्वतारोही अन्ना फ्लेमिंग मैं बताया है कि सिर्फ आसान कामों मैं ही पुरुषों से बराबरी करने के बजाय पर्वतारोहण जैसे कठोर श्रमसाध्य व रोमांच तथा जोखिम से परिपूर्ण कार्य महिलाओं के लिए भी संभव है। ऐसी दूरूह जानलेवा चढ़ाई भयानक बर्फीले माहौल में लंबे समय तक करते रहना विश्व की अन्य महिलाओं के लिए भी एक संदेश प्रदान करता है । भारत की बछेंद्री पाल ने भी माउंट एवरेस्ट फ्तह करके विश्व में अपना नाम रोशन किया है। जीवन के रोमांच का सही मजा लेना हो तो ऐसे चुनौतीपूर्ण कार्यों के माध्यम से ही उसका आनंद लिया जा सकता है। पर्यटन स्थलों पर मौज मस्ती करने और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में उतना ही फ्र्क है जितना आर्टिफिशियल ज्वेलरी और ओरिजिनल गोल्ड ज्वेलरी में होता है। इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर सफ्लता का स्वाद मिलता है। लेकिन जिसने यह स्वाद एक बार चख लिया वह जीवन में किसी भी अन्य जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं झिझकेगी। अधिकाधिक महिलाओं को पर्वतारोहण करना चाहिए।

–**विभूति बुपक्या,** खाचरोद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 88

कृषि उपज की बरबादी न हो

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने फिर यह बात कही है कि इस साल देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से ज्यादा होगी। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में भी इस साल अच्छी बारिश होने की उम्मीद है जो कृषि पैदावार बढ़ाने में मददगार साबित होगी। ऊंचे उत्पादन से स्वाभाविक रूप से खाद्य महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी। यह गौर करना अहम होगा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुख्य मुद्रास्फीति दर 4 फीसदी से नीचे बनी हुई है, लेकिन खाद्य पदार्थों की ऊंची महंगाई ने समग्र मुद्रास्फीति दर को रिजर्व बैंक के लक्ष्य से ऊपर रखा है। उदाहरण के लिए अप्रैल में खाद्य मुद्रास्फीति दर 8.7 फीसदी थी। महंगाई के प्रबंधन के लिहाज से देखें, जब खाद्य उत्पादन में सुधार से कीमतों और महंगाई पर अंकुश बने रहने की संभावना है, भारत को जल्द खराब होने वाले उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला बेहतर करने पर भी काम करना चाहिए जिनकी महंगाई के उतार-चढ़ाव में ज्यादा भूमिका होती है। उदाहरण के लिए कुछ महीने पहले सब्जियों की कीमतों ने समग्र मुद्रास्फीति दर को बढ़ा दिया था।

यह इस तथ्य के बावजूद है कि भारत दुनिया में सब्जियों और फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यहां साल 2022-23 में बागवानी उत्पादों की पैदावार करीब 35.19 करोड़ टन रही और उसी वर्ष में उन्होंने कुल अनाज उत्पादन को पीछे छोड़ दिया। लेकिन सच यह भी है कि इनमें से टनों उत्पाद बरबाद हो गए। करीब 15 फीसदी फल और सब्जियां उपज हासिल करने के बाद ही बरबाद हो जाती हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से पड़ने वाली अतिशय गर्मी से आने वाले वर्षों में हालत और बदतर हो सकती है। बुनियादी ढांचे में सुधार से इस बरबादी को कम करने में मदद मिल सकती है। देश में शीत भंडार गृह और प्रशीतन सुविधाएं अपर्याप्त हैं जो पूरे आपूर्ति श्रृंखला के लिए अड़चन है। तापमान नियंत्रित आपूर्ति श्रृंखला से खराब हो सकने वाली सामग्री को संरक्षित करने में काफी मदद मिलती है और इससे यह सुनिश्चित होता है कि उपभोक्ताओं तक खाद्य पदार्थ अधिक से अधिक सही स्थिति में पहुंच सकें। ध्यान देने की बात यह भी है कि देश में करीब 3.9 करोड़ टन की मौजूदा शीत भंडार गृह क्षमता के एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल ही नहीं हो पाता है। यही नहीं, अभी जो शीत भंडार गृह इकाइयां हैं उनका भौगोलिक इलाकों के हिसाब से वितरण भी असमान है। उदाहरण के लिए ज्यादातरण शीत भंडार गृह सुविधाएं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब और आंध्र प्रदेश में केंद्रित हैं, जबकि बिहार और मध्य प्रदेश में ऐसी सुविधाएं अपर्याप्त हैं। ज्यादातर शीत भंडार गृह केंद्रों का डिजाइन इस तरह का है कि वे एक समय में एक ही जिंस का संग्रहण कर पाते हैं। इसलिए देश में मल्टी-स्टोरेज शीत भंडार गृह क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है।

भारत के ज्यादातर किसान गरीब और छोटे, बिखरे जोत वाले हैं तथा खेती से उनकी कमाई बहुत कम होती है, इसलिए यह संभव नहीं है कि विकेंद्रित तरीके से भंडारण ढांचे में निवेश किया जा सके। देश की करीब 92 फीसदी शीत भंडार गृह इकाइयों का संचालन और स्वामित्व निजी क्षेत्र में है, इसलिए भंडारण ढांचे में कमी की समस्या के समाधान के लिए सरकार के दखल की गुंजाइश है। वैसे तो ऐसे भंडारण केंद्रों, पैक हाउस सहित, की स्थापना के लिए सरकार 35 से 50 फीसदी तक सब्सिडी देती है, फिर भी इनकी लागत काफी ज्यादा होती है। खेतों और थोक बाजारों या मंडियों के बीच काफी दूरी और खराब सड़कों जैसी अन्य समस्याएं भी आपूर्ति श्रृंखला में अवरोध को बढ़ा देती हैं जिससे ढुलाई के दौरान ही कुछ पैदावार खराब हो जाती है। भारत में सड़क संजाल का करीब 30 फीसदी हिस्सा अब भी कच्चा है जिससे कृषि पैदावार को मंडियों तक ले जाने में काफी दूरी और समय लगता है और इसका असर भी कीमतों पर पड़ता है।

प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर खाद्य पदार्थों की बरबादी को काफी कम किया जा सकता है। देश में होने वाली ऐसी बरबादी को कम से कम करने के लिए कृषि में मशीनीकरण को बढ़ाने, सटीक कृषि दस्तूर अपनाने, जलवायु अनुकूल कृषि-खाद्य प्रणाली अपनाने जैसे उपाय अहम हो सकते हैं। हालांकि भंडारण और सड़क संजाल के बुनियादी ढांचे में क्षमता सुधार तथा खेतों से मंडियों के बीच दूरी कम करना नीतिगत प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। आपूर्ति श्रृंखला में सुधार से कीमतों में उतार-चढ़ाव को रोकने में मदद मिलेगी जिससे उत्पादकों और उपभोक्ताओं, दोनों का भला होगा।

अजय मोहंती

बिजली सब्सिडी देने के तरीके में हो रहा सुधार

बिजली क्षेत्र में कर वसूलने और उसका इस्तेमाल सब्सिडी देने में करने की व्यवस्था से पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्द्धा पर नकारात्मक असर होता है। बता रहे हैं अजय शाह और अक्षय जेटली

नीति निर्धारक बिजली सब्सिडी देने में अधिक पारदर्शिता बरतने लगे हैं। सरकारी खजाने से इस मद में दी जाने वाली सब्सिडी का भुगतान अब पहले की तुलना में काफी स्पष्ट एवं पारदर्शी हो गया है। यह बदलाव बिजली क्षेत्र की परंपरागत समस्याओं के निदान के लिए महत्त्वपूर्ण विकल्पों को बढ़ावा दे रहा है। इस क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण और त्रुटिपूर्ण नियमों का बेजा फायदा लेकर कुछ खास समूहों को सब्सिडी का भुगतान होता था, जिसमें पारदर्शिता का काफी अभाव हुआ करता था। अगर यह नई नीति आगे बढ़ाई जाए तो इससे एक ऐसे सक्षम बिजली क्षेत्र की राह प्रशस्त हो सकती है जो बाजार के सिद्धांतों पर आधारित होगा और पारदर्शी तरीके से सब्सिडी लाभार्थियों तक पहुंचने से राजनीतिक उद्देश्यों की भी पूर्ति भी हो पाएगी।

सबसे श्रेष्ठ उपाय तो यही होगा कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की पूरी ताकत झोंक दी जाए और उसके बाद कर राजस्व का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाए। भारत में बिजली उन कई क्षेत्रों में एक है जिनमें सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर एक ऐसी कर और व्यय प्रणाली तैयार की जाती है जिसमें कुछ ग्राहकों से जरूरत से ज्यादा शुल्क लिया जाता है ताकि दूसरों को सब्सिडी दी जा सके। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सभी कर एवं सभी व्यय केंद्र, राज्य या निगम स्तर पर बजट में समाहित किए जाएं तो उस स्थिति में नीतियों एवं उनके क्रियान्वयन की गुणवत्ता काफी बढ़ जाएगी। कराधान के अंतर्गत वाजिब कर (व्यक्तिगत आयकर, वस्तु एवं सेवा कर और जायदाद कर) लगाए जाएंगे और नुकसानदेह कर (व्यावसायिक एवं औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं पर कराधान का बोझ) धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगे।

व्यय सटीक तरीके से होगा और इस तरह आर्थिक संसाधन का श्रेष्ठतम इस्तेमाल हो पाएगा। इससे सार्वजनिक संसाधनों एवं सब्सिडी के संबंधों में अधिक सार्थकता आएगी और समाज के उन खास समूहों की सटीक पहचान हो सकेगी जिन्हें वाकई सब्सिडी की आवश्यकता है। इसके अलावा, बिजली क्षेत्र में कर वसूलने और फिर उसका इस्तेमाल सब्सिडी देने में करने की व्यवस्था से पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्द्धा दोनों पर ही नकारात्मक असर होता है। पुनर्वितरण के नाम पर त्रुटिपूर्ण व्यवस्था एवं अक्षमता की स्थिति लंबे समय तक खिंचती जाती है। बिजली क्षेत्र निजी नियंत्रण और मूल्य प्रणाली को बढ़ावा देने से बेहतर ढंग से काम कर पाएगा। मगर जो सुधार हमें इस दिशा में ले जाते, उन्हें यह कहते हुए रोक दिया गया है कि ये बिजली क्षेत्र के अंतर्गत चलने वाली कर एवं सब्सिडी योजना में हस्तक्षेप करते हैं। यह तर्क भी दिया जा रहा है कि सरकार नियंत्रित कंपनियों के साथ मिलकर बिजली क्षेत्र अधिक सुगमता से काम कर सकता है।

इसी संदर्भ में हमें तमिलनाडु, कर्नाटक और दिल्ली में चल रही बिजली सब्सिडी योजनाओं पर विचार करना चाहिए। नई धारणा यह बनी है कि सरकारी तंत्र में कंप्यूटरीकरण एक अभीष्ट स्तर तक पहुंच गया है जिसकी मदद से नीति निर्धारक एक सब्सिडी कार्यक्रम तैयार कर पाएंगे और वितरण कंपनी को एक निश्चित एवं जरूरी अनुपात में रकम दे पाएंगे। एक ढांचा कुछ इस प्रकार काम करता है कि प्रत्येक परिवार को हर महीने 200 किलोवॉट घंटा निःशुल्क बिजली देकर लगभग 1,000 रुपये की राशि हर महीने सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। यह राजनीति के हिसाब से प्रभावी नीति है इसलिए लोकप्रिय हो रही है। लाभार्थी यह प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं कि उन्हें कहां से सब्सिडी मिलेगी। उपभोक्ताओं को एक ऐसा बिजली बिल मिलता है जिसमें इस बात का स्पष्ट जिक्र होता है कि बिल के मद में उन पर बकाया 1,000 रुपये (200 किलोवॉट घंटा के लिए) का भुगतान राज्य के वित्त मंत्रालय ने किया है। इस तरह, लाभार्थी का बिल शून्य हो जाता है। यह लाभार्थी को अधिक खुशी एवं संतुष्टि देता है। इसकी तुलना में बिजली क्षेत्र में मौजूदा पेचीदा एवं परंपरागत कर एवं सब्सिडी योजना में लाभार्थियों को यह पता ही नहीं होता है कि उसे क्या मिल रहा है। हमारा अनुमान है कि इस पद्धति का चलन पूरे भारत में बढ़ता जाएगा।

ऐसी सब्सिडी बिजली क्षेत्र में सुधार की गुणवत्ता बढ़ाने की महत्त्वपूर्ण संभावनाएं खोल देती है। मौजूदा बिजली व्यवस्था में कई तरह के हस्तक्षेप सुधार की राह में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में बिजली की 22 दरें हैं जो इस आधार पर निर्धारित होती हैं कि खरीदार कौन है और कितनी मात्रा खरीदी जा रही है। इन हस्तक्षेपों को दूर कर कई लाभ मिल सकते हैं। जब प्रत्येक लाभार्थी सामान्य बिजली बिल (स्पष्ट एवं बिजली की एकसमान दर) देखेगा, जब बिल में यह जिक्र होगा कि वित्त मंत्रालय से सब्सिडी मिली है तो उसे अधिक संतुष्टि मिलेगी। एक आदर्श व्यवस्था यह है जिसमें वित्त मंत्रालय राजनीतिक रूप से लाभकारी सब्सिडी का निर्धारण करे और बिजली प्रणाली विश्वसनीय एवं सस्ती बिजली उपलब्ध कराने की ओर उन्मुख हो। बिजली क्षेत्र से राजनीतिक मकसद अलग करने से इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों पर बोझ कम हो जाएगा।

बिजली नियमन मुख्य रूप से एक विशेष समस्या के लिए होना चाहिए। वह समस्या यह है कि बिजली वितरण कंपनियों को अपने दबदबे का फायदा उठाने और उपभोक्ताओं से अधिक शुल्क वसूलने से रोकना। मगर इसके बजाय राज्य बिजली नियामकों ने स्वयं को बिजली की राजनीतिक व्यवस्था में उलझा दिया है। बिजली की राजनीतिक व्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण और कर एवं सब्सिडी योजना से संचालित होती है। इन पेचीदा समस्याओं के कारण राज्य बिजली नियामकों की क्षमता का विकास बाधित होता है। अगर राजनीतिक समस्या-जिस समूह को रकम दी जानी है उसका चयन करना- वित्त मंत्रालय को स्थानांतरित की जाती है तो इससे तकनीकी रूप से सक्षम बिजली नियामक गठित करने के लिए जरूरी परिस्थितियां तैयार हो सकती हैं। निजी वितरण कंपनियों की सफलता के कई उदाहरणों के बाद यह आम तौर समझा जाता है कि ऐसी कंपनियां बेहतर कार्य करती हैं। भारत के कई राज्यों में निजी वितरण की तरफ कदम बढ़ाने की राह में वितरण कंपनियों में गैर-पारदर्शी तरीके से लिए गए निर्णय बाधा बनते हैं। एक बार बजट सब्सिडी का नियंत्रण वित्त मंत्रालय के पास आ जाएगा तो अधिक स्थानों पर निजी वितरण कंपनियों के जरिये अधिक बिजली उत्पादन क्षमता तैयार करना आसान हो जाएगा।

राजनीति एवं पुनर्वितरण की समस्या को जीडीपी हासिल करने की जद्दोजहद से अलग रखना बुद्धिमानी होगी। अगर राजनीतिक नफा-नुकसान के लिए राज्य अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर मूल्य प्रणाली में हस्तक्षेप करता है तो इसे जीडीपी प्रभावित होती है और उम्मीद से कम रहती है। मूल्य निर्धारण प्रणाली के आधार पर निजी क्षेत्र लागत कम करने और जीडीपी को बढ़ाने में सक्षम है। नीति निर्धारकों को एक ऐसा नीतिगत माहौल तैयार करना चाहिए जिसमें मूल्य प्रणाली प्रभावी ढंग से ऐसा कार्य कर सके। जीडीपी का लक्ष्य हासिल होने के बाद राजनीतिक निर्णय इस बारे में होना चाहिए कि कराधान का स्तर क्या हो, सार्वजनिक संसाधन और सब्सिडी पर खर्च कितना-कितना हो और किन पसंदीदा समूहों को सब्सिडी का लाभ दिया जाए।

(शाह एक्सकेडीआर फोरम में शोधकर्ता और जेटली ट्राइलीगल के पार्टनर एवं ट्रस्टब्रिज के संस्थापक हैं)

केंद्रीय बैंक क्यों खरीद रहे इतना सोना?

सोने की मांग बढ़ने से पिछले दो वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका भाव 30 प्रतिशत से भी अधिक चढ़ चुका है। भारतीय बाजारों में तो सोने के दाम में पंख लग गए हैं। दाम में मौजूदा तेजी सोने के साथ एक महत्त्वपूर्ण सैद्धांतिक तथ्य से मेल नहीं खाती है। सोना नियमित आय का स्रोत नहीं है इसलिए ब्याज दरें कम रहने की स्थिति में इसे रखने में संभावित नुकसान कम रहता है। परंतु, वैश्विक स्तर पर ब्याज दरें कई दशकों के ऊंचे स्तर पर रहने के बावजूद सोने के भाव में भारी इजाफा देखा जा रहा है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के अधिकारी संकेत दे रहे हैं कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर रह सकती हैं। सोने के भाव में तेजी इसलिए भी ध्यान खींच रही कि अमेरिका मुद्रा डॉलर तुलनात्मक रूप से मजबूत है तब भी सोने की चमक कम नहीं हो रही है। अमेरिकी मुद्रा डॉलर और सोने के मूल्य में ज्यादातर अवसरों पर उल्टा संबंध दिखा है। यानी जब डॉलर कमजोर होता है तो उस स्थिति में सोने की कीमतें बढ़ जाती हैं।

पिछले कुछ समय से दुनिया के केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं और यह इसके दाम में बढ़ोतरी के प्रमुख कारणों में एक है। 2024 की पहली तिमाही में एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों से निवेश निकलने के दौरान भी केंद्रीय बैंकों ने खरीदारी जारी रखी। विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) के अनुसार जनवरी-मार्च 2024 में केंद्रीय बैंकों ने 290 टन सोना खरीदा है। इससे पहले पहली तिमाही में इतनी भारी मात्रा में सोना नहीं खरीदा गया था। चीन, भारत और तुर्किये के केंद्रीय बैंक सोना खरीदने में सबसे आगे रहे हैं। वर्ष 2024 की शेष अवधि में भी केंद्रीय बैंक सोना खरीदने की अपनी रफ्तार कम नहीं होने देंगे। मगर केंद्रीय बैंक इतना सोना क्यों खरीद रहे हैं?

सोना परंपरागत रूप से केंद्रीय बैंक के भंडार का महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहा है। अनुमानों के अनुसार अब तक जितनी मात्रा में सोने का उत्पादन हुआ है उनका पांचवां हिस्सा केंद्रीय बैंकों के भंडारों में है। केंद्रीय बैंक प्रायः अपने भंडार में विविधता लाने के लिए सोना खरीदते हैं। पिछले आंकड़े बताते हैं कि बॉन्ड एवं शेयरों जैसी परंपरागत परिसंपत्तियों के साथ सोने का मजबूत संबंध नहीं रहा है।

अर्थतंत्र

राजेश कुमार

यह कहा जा रहा है कि कुछ केंद्रीय बैंक कई कारणों से अमेरिकी परिसंपत्तियों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए सोना खरीद रहे हैं। इन कारणों में एक है गंभीर भू-राजनीतिक स्थिति और वैश्विक स्तर पर देशों के बीच बढ़ती दूरियां। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका एवं उसके सहयोगी देशों ने उसका (रूस) विदेशी मुद्रा भंडार जब्त कर लिया। इससे दुनिया के दूसरे देशों में भय व्याप्त हो गया है। पश्चिमी देशों ने रूस के लगभग 300 अरब डॉलर भंडार पर ताला जड़ दिया है। भू-राजनीतिक समीकरण में अमेरिकी खेमे में नहीं रहने वाले किसी देश को ऐसे ही परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सोना रखने में इतना जोखिम नहीं है क्योंकि यह किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र में ही रहता है। साबुत सोने (फिजिकल गोल्ड) में चूक (डिफॉल्ट) का जोखिम शून्य रहता है। हालांकि, इस बात पर चर्चा करना भी जरूरी है कि क्या भू-राजनीतिक बिखराव और लगातार बढ़ते तनाव के बीच सोना केंद्रीय बैंकों के लिए एक मूल्यवान परिसंपत्ति साबित हो सकता है? छोटे देशों के लिए यह संभव है कि वे अपने भंडार का एक बड़ा हिस्सा सोने में निवेश कर दें मगर विदेशी मुद्रा भंडार से बड़े स्तर पर जुड़े बड़े केंद्रीय बैंकों के लिए यह संभव नहीं है। चीन बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहा है और दुनिया में यह सोना रखने वाले सबसे बड़े देशों में एक है मगर इसके कुल विदेशी मुद्रा भंडार में इसकी (सोने की) हिस्सेदारी मात्र 4.6 प्रतिशत है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सोने का भंडार रखने के मामले में दुनिया का नौवां सबसे बड़ा बैंक है। इसके कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से नीचे है। रूस के भंडार में सोने की हिस्सेदारी 28 प्रतिशत पहुंच गई है।

इस बात के मजबूत कारण मौजूद हैं कि क्यों सोना केंद्रीय बैंक के बहीखातों में वित्तीय परिसंपत्तियों की जगह बहुत अधिक नहीं ले पाएगा। यह बात भी ध्यान में रखने लायक है कि सोने के साथ जुड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी आपूर्ति सीमित है। लिहाजा, केंद्रीय बैंकों में इसके भंडार में इसकी कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और इसके साथ ही निवेश जोखिम भी बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए अगर चीन ने सोने का भंडार बढ़ाकर दोगुना कर दिया है तो इसका मतलब है कि लगभग तीन तिमाहियों में उत्पादित सोने की पूरी मात्रा खरीद ली है। आरबीआई जैसे केंद्रीय बैंक मुद्रा पर पूंजी से जुड़े प्रभाव कम करने के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा रखते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक विदेशी परिसंपत्तियां खरीदते एवं बेचते हैं। सोने की खरीद-बिक्री तेजी से होती है मगर केंद्रीय बैंकों की तरफ से भारी मात्रा में सोने की बिकवाली के समय इसके दाम पर उल्टा असर हो सकता है। चूंकि, शेयर या बॉन्ड की तरह सोने का मूल्य किसी वस्तु या वित्तीय साधन से नहीं जुड़ा होता है इसलिए केंद्रीय बैंकों द्वारा बड़े स्तर पर खरीदारी या बिकवाली से इसका (सोने के दाम) झुकाव किसी भी तरफ हो सकता है। उदाहरण के लिए चीन के केंद्रीय बैंक ने पिछले दो वर्षों के दौरान 200 अरब डॉलर मूल्य के अमेरिकी बॉन्ड बेचे हैं और इससे बाजार में कोई खास असर नहीं हुआ है। चीन ने अपनी मुद्रा युआन को मजबूती देने के लिए यह कदम उठाया है, जो 2023 में 9 प्रतिशत तक लुढ़क गया था। चीन के केंद्रीय बैंक के पास लगभग 161 अरब डॉलर सोना जमा है। मगर वहां का केंद्रीय बैंक इसे बेचता है तो निश्चित तौर पर इसकी कीमत पर बड़ा असर होगा। एक परिसंपत्ति के रूप में सोने के साथ लोगों का जुड़ाव भी काफी अधिक होता है और यह बात 1991 में भारत में विदेशी मुद्रा संकट के दौरान दिख चुकी है।

इस तरह, केंद्रीय बैंक अपने भंडार में विविधता लाने के लिए अक्सर सीमित मात्रा में सोना रखते हैं। अमेरिकी मुद्रा डॉलर के सामने इसकी कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। दुनिया में इस समय सभी विदेशी मुद्राओं का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा डॉलर में है और 80 प्रतिशत से अधिक व्यापार भी इसी में होता है। विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा से आर्थिक एवं राजनीतिक बिखराव बढ़ता ही जा रहा है। इसके दुनिया के लिए ऐसे विकट परिणाम हैं जिनका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। मगर इस रणनीतिक एवं वित्तीय संघर्ष में सोने की कोई बड़ी भूमिका नहीं दिख रही है। सोने की आपूर्ति सीमित होती है इसलिए इसकी मांग में मामूली बदलाव से इसकी कीमतों पर असर अधिक हो सकता है।

आपका पक्ष

पर्यटन क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत

संपादकीय 'सही मायने में अतुल्य हो भारत' में बहुत गंभीरता से भारत को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर पर्यटन के क्षेत्र में उच्च स्थान पर स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यह सच है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का लगभग 6 प्रतिशत का योगदान है परंतु सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन को एक अलग सेक्टर के रूप में स्थापित करने की भी आवश्यकता है। तभी पर्यटन के हित में राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर गंभीरता से नीति निर्धारण हो सकता है। इतने विशाल देश में महज 50 स्थान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और साथ ही घरेलू पर्यटकों की भी भीड़ वहीं पहुंचती है। इस कारण इन मुख्य पर्यटक स्थलों में कुव्यवस्थाएं, होटलों की कमी और आवागमन में गतिरोध होते हैं। भारत में हर साल लगभग 4 करोड़ घरेलू और 1 करोड़ विदेशी पर्यटक आते हैं। इस अनुपात से लक्जरी होटलों और स्थानीय पर्यटन सुविधाओं की कमी है। सरकार को लोकल टैक्सी सर्विस के साथ-साथ उबर, ओला और निजी टैक्सियों को अच्छी स्थिति वाली गाड़ियों की अनिवार्यता करनी चाहिए और दाम पर अंकुश लगाना चाहिए। दिल्ली जैसे महानगर और देश की राजधानी में निजी टैक्सियों की स्थिति बहुत दयनीय है और ड्राइवरों के लिए यातायात नियमों का उल्लंघन कोई मायने नहीं रखता। सभी ट्रैवल वेबसाइट और सर्विस प्रदाताओं को होटल बुकिंग और लोकल ट्रैवल सहित बुकिंग की आधिकारिक सुविधा से विदेशी पर्यटकों का शोषण नहीं होगा और उनकी संख्या में भी वृद्धि होगी। विभिन्न पर्वतीय और तटीय क्षेत्रों में नये पर्यटक स्थलों को विकसित करने और अविकसित पर्यटन स्थलों को उच्चीकृत करके घरेलू और विदेशी पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। पर्यटन सर्वाधिक रोजगार सृजन का क्षेत्र है।

विनोद जौहरी, दिल्ली

देश के पर्यटन स्थलों को देखने के लिए हर साल 4 करोड़ देसी और 1 करोड़ विदेशी पर्यटक आते हैं मगर उन्हें सुविधाओं की कमी दिखती है

ऑनलाइन मतदान हो सकता है एक बेहतर विकल्प

वर्तमान में जारी मतदान प्रक्रिया अत्यंत बोझिल, उबाऊ, समय, ऊर्जा और मानव श्रम का सरासर अपव्यय है। जीवन के विविध क्षेत्रों की भांति अब मतदान प्रक्रिया में भी डिजिटल तकनीक का प्रयोग होना समय की मांग है। आधुनिकीकरण के माध्यम से इसका आसान तरीका है ऑनलाइन मतदान। इसके साथ ही मतदाता सूची को आधार से जोड़ देने पर निष्पक्ष मतदान होने के साथ सभी प्रकार के संसाधनों की बचत भी होगी।

डॉ.हेमलता कर्नावट,इंदौर, मप्र

जागरूकता जरूरी

चुनावी प्रक्रिया में सुधार के लिए मतदान के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना जरूरी है। इससे मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। नोटा के मतों का अधिक योग होने पर संबंधित चुनाव के सभी उम्मीदवारों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगना चाहिए। आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में कठोर सजा का प्रावधान भी जरूरी है। साथ ही मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को और अधिक बढ़ावा दिया जाए जिससे मतों की खरीद-फरोख्त को रोका जा सके।

कृष्ण चन्द्र त्रिपाठी, रीवा, मप्र

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

नई दिल्ली में मंगलवार को विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन (दाएं) ने लीबिया के राजनीतिक मामलों के उप मंत्री मोहम्मद खलील इस्सा से मुलाकात की।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बुधवार • 29 मई • 2024
www.rashtriyasahara.com

सही फैसला

जम्मू-कश्मीर में किसी आतंकवादी या पत्थरबाजी करने वाले शख्स के परिजन को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को यह बात कही। यह भी कहा कि मोदी सरकार आतंकवादी ढांचा समाप्त करेगी और इससे आतंकी घटनाओं में कमी आना तय है। शाह ने फैसले के खिलाफ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के उच्चतम न्यायालय जाने की बात भी की। इस मामले में सरकार की जीत हुई। उन्होंने ऐसे मामलों में राहत देने की बात भी की, जिनमें कोई शख्स स्वयं आगे आकर अपने करीबी रिश्तेदार के आतंकवादी गुट में शामिल होने की सूचना देता है। आतंकी के मारे जाने पर निकाले जाने वाले जनाजे को लेकर भी उन्होंने बताया कि हमने

धार्मिक रिवाजों के साथ सुपुर्द-ए-खाक निर्जन स्थान पर करने की व्यवस्था की। जैसा कि याद होगा कि पूर्व में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादी मारे जाने के बाद भारी जन-सैलाब उनके जनाजे में शामिल हुआ करता था। आतंकवाद के खिलाफ होने वाले वित्त पोषण को लेकर भी मोदी सरकार द्वारा बहुत सख्ती बरती गई है। पूर्ववर्ती राज्य का विशेष दर्जा समाप्त करने के बाद से केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। राज्य लंबे समय तक आतंकवाद की चपेट में रहा है। बड़े आतंकवादी संगठन युवाओं को बरगला कर, उन्हें झूठे आश्वासन देकर या धमका कर अपने गुटों में शामिल करते रहे हैं। आत्मसमर्पण करने या हथियार डालने वाले युवाओं को सुधरने का मौका देने के लिहाज से उन्हें नौकरियां दी जा रही थीं। मगर अमानत में खयानत करने वाले गद्दारों तथा गोपनीय सूचनाएं देश-विरोधी तत्वों तक पहुंचाने वालों से आजिज आकर इस तरह के सख्त फैसले करना उचित है। बेहतर हो कि सरकार हथियार डालने वाले ऐसे भटके युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए, उन्हें रोजगार पाने में सक्षम बनने में मदद करे। बेशक, कड़ाई उचित है मगर उन्हें विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था तो की ही जा सकती है। साथ ही, उनके परिजनों पर कड़ी नजर रखने के अलावा स्थानीय पुलिस या सुरक्षा तंत्र के संपर्क में रहने जैसे आदेश भी दिए जा सकते हैं। बेशक, राज्य में आतंकवादी और पत्थरबाजी की घटनाओं को थामने में सरकार काफी हद तक सफल हो रही है। नतीजतन, राज्य में पर्यटकों की आवक में तेजी आई है, जो स्थानीय रोजगार की रीढ़ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राज्य में सकारात्मक और आशावादिता का माहौल बना है।

चुनाव और विदेशी हस्तक्षेप

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के आम चुनाव पर पड़ोसी देश पाकिस्तान सहित पश्चिमी देशों और वहां की मीडिया की नजर लगी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से इस चुनाव में पाकिस्तान के कुछ नेताओं की टिप्पणी को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब आया देश में कुछ ही लोग हैं जिनके समर्थन में वहां से आवाज उठती है। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों है। यह जांच-पड़ताल का गंभीर विषय है। यह गौर करने वाली बात है कि भारत में चुनाव अभियान शुरू होने के साथ ही विदेशी हस्तक्षेप किसी न किसी रूप में मुद्दा बना हुआ है। अभी पिछले दिनों ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 'इंटरनेशनल खान मार्केट गैंग' का जिक्र किया। उनका विश्वास है कि यह गैंग भारत में सक्रिय ऐसे ही तत्वों के साथ मिलकर सरकार की नीतियों को

प्रभावित करता है। विदेश मंत्री के अनुसार 'इंटरनेशनल खान मार्केट गैंग' में पश्चिमी देशों की मीडिया, बुद्धिजीवी वर्ग, थिंक टैंक और मध्यम दर्जे के सरकारी अधिकारी शामिल हैं। जयशंकर ने इन देशों को एक तरह से चेतावनी भी दी है कि वे भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने के बजाय अपने देश को संभालें। पड़ोसी देश पाकिस्तान हो या फिर अमेरिका और पश्चिमी देश सभी की नजरों में भारत और प्रधानमंत्री मोदी किरकिरी बने हुए हैं। वे भारत के एक मजबूत और विकसित देश के रूप में उभरते देखना नहीं चाहते। ये देश भारत की राजनीति को अस्थिर और कमजोर बनाने के लिए समय-समय पर इस तरह के दांव चला करते हैं और इनके लिए चुनाव से बेहतर कोई दूसरा मौसम नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जब अपना पोस्ट साझा कि मैंने महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही के खिलाफ विरोध किया है तो पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने प्रतिक्रिया दी कि शांति और सद्भाव से नफरती और कट्टर ताकतों को हराया जा सकता है। केजरीवाल को पाकिस्तानी मंत्री की राजनीतिक चाल समझने में देर नहीं लगी और उन्होंने जवाब दिया कि आपको आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के बजाय अपने देश की खराब स्थिति को संभालने में ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने केजरीवाल और चौधरी के संवाद को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की है। जाहिर है चुनाव में नेता एक दूसरे पर अपने तरकश का हर बाण चलाते हैं। लेकिन चुनाव बाद एक दूसरे को गले भी लगा लेते हैं। लोकतंत्र की यही खूबी है कि भारत के नेता और मतदाता दोनों परिपक्व हैं।

विमर्श/डॉ. अशोक कुमार

पलायन की पीड़ा

हर भारतीय नागरिक का यह संवैधानिक अधिकार है कि वह देश की नागरिकता का त्याग कर किसी भी दूसरे देश के नियमों के आधार पर वहां जाकर बसे और वहां की नागरिकता ग्रहण करे। जब निजी हितों, रोजी-रोटी, सुविधाओं एवं बेहतर जीवन जीने की इच्छा को लेकर कोई अपने देश की नागरिकता को छोड़कर अन्यत्र जाने को विवश हो तो यह देश के लिए गहरी चिंता का विषय भी है। विचारणीय यह भी है कि जब हम यह कहते नहीं थकते कि देश संसार की पांचवीं अर्थव्यवस्था की पंक्ति में खड़ा हो गर्वित हो रहा है तो आखिर, यह पलायन क्यों?

आंकड़े बता रहे हैं कि 2011 से 2022 तक देश के कुल 13.85 लाख लोगों ने अपने देश की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश प्रस्थान कर गए जिनमें से करीब 7 लाख लोग अमेरिका चले गए। हैरान करने वाली बात है कि नागरिकता छोड़ने वाले करोड़पतियों की संख्या मात्र 2.5% है अर्थात जिन लोगों ने नागरिकता त्याग किया, उनमें 97.5% नौकरीपेशा रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2010 तक नागरिकता त्याग करने वाले 7% की वार्षिक दर से बढ़ रहे थे जो अब करीब 29% हो गई है। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, इसलिए किसी दूसरे देश में बसने की लालसा रखने वाले लोगों को देश की नागरिकता छोड़ना भी विवशता है। विचारणीय है कि देश की 3.75 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, लोकतांत्रिक संविधान है फिर क्यों लोग अपनी भाषा, संस्कृति, रहन-सहन के स्तर, सामाजिक ताने-बाने एवं परिजनों को अलविदा कर रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर और बेहतरी के लिए जरूरी है कि देश की प्रतिभाओं को देश में ही काम करने के वातावरण और अवसर तलाश किए जाएं। देश में इतने बड़े संकट को किसी भी राजनीतिक दल द्वारा अपने चुनाव घोषणापत्र या वचनपत्र में समाधान का सूत्र नहीं देना, स्पष्ट करता है कि ऐसे राष्ट्रीय महत्त्व का विषय उनके लिए उदासीनता से भरपूर है। इस पलायन का सबसे गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम यह परिलक्षित हुआ है कि पलायनकर्ताओं के आधे परिवार जब देश में रह जाते हैं, तो उनकी वृद्धावस्था में उनकी समुचित देखभाल भी प्रभावित हो रही है।

इंटरनेशनल कोर्ट का संकट

सामयिक

डॉ. ब्रह्मदीप अलूने

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) ने संतुलन के तराजू में इस्राइल के शीर्ष नेताओं और हमास के शीर्ष नेताओं को साथ रखने का साहस दिखाया तो पूरी दुनिया में हल्ला मच गया। आईसीसी के अभियोजन पक्ष ने हमास पर युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध, मर्डर, रेप, बंधक बनाने जैसे आरोप लगाए गए हैं। वहीं नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध, जिनमें विनाश, उत्पीड़न, युद्ध के तरीके के रूप में भुखमरी पैदा करना, मानवीय राहत आपूर्ति से इनकार करना और हमास को हराने के प्रयास में जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाना शामिल है। करीम रवांडा, लेबनान और सिएरा लियोन की आपराधिक अदालतों में भी काम कर चुके हैं। ये तीनों देश गृह युद्ध और हिंसा की चपेट में आ चुके हैं।

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने इस्राइल और हमास पर जो आरोप लगाए हैं, उनकी पुष्टि इन घटनाओं से की जा सकती है। सात अक्टूबर, 2023 को हमास ने इस्राइल पर हमला किया था। हमले में 1200 लोग मारे गए थे और कई लोगों को बंधक बनाया गया था। हमास के लड़ाकों ने कई महिलाओं के साथ गैंगरेप किए, उनकी निर्मम हत्याएं की और उनके शरीर को क्षत-विक्षत कर दिया। कई लोगों की गर्दन और उनके अंग काट कर सड़क पर फेंक दिए गए और फिर आतंकी उनके साथ खेल रहे थे।

कई लोगों ने लोगों की हत्या, रेप और सिर काटे जाने की आवाजें और चीखें सुनीं। हमास के आतंकवादियों के विभिन्न समूहों की क्रूरता के तरीके अलग-अलग थे। इस्राइल के पुलिस प्रमुख याकोव शबताई ने कहा कि यह पूर्वनियोजित घटना थी। माना जाता है कि हमास ने इस्लामिक स्टेट समूह और बोस्निया से महिलाओं के शरीर को हथियार बनाने का तरीका सीखा। यह सब इतना भयावह था कि कई लोग इस्राइल के मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों में भर्ती हैं, जो उस खौफ से अब भी नहीं उबर पाए हैं, और पागल हो गए हैं। हमास जिन्हें बंधक बना कर ले गया, वे या तो मारे गए हैं, या अंधेरी सुरंगों में नारकीय जीवन जीने को मजबूर कर दिए गए हैं। हमास की निर्ममता का जवाब इस्राइल ने बेहद प्रतिशोधात्मक तरीके से दिया है। इस्राइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक गजा और वेस्ट बैंक में 35 हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सात अक्टूबर को हमास हमले के बाद इस्राइल ने गजा पट्टी की पूरी तरह से घेराबंदी का आदेश दिया अर्थात समूची आबादी का बिजली, पानी और ईंधन बंद कर दिया गया। इस्राइल फिलस्तीनी क्षेत्रों पर लगातार हवाई और

जमीनी हमले कर रहा है। फिलस्तीनी घायलों को भी नहीं बख्श रहा। गजा में फिलस्तीनी कैदियों को अस्पताल में बिस्तरों पर बेड़ियों से बांध कर रखा जाता है और आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। कभी-कभी उनके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। इस्राइली सेना ने गजा में पूर्वी रफाह के अलग-अलग इलाकों में हमले कर लाखों लोगों को बेघरबार कर दिया है। इस्राइली हवाई हमलों और नाकाबंदी के कारण अधिकांश अस्पतालों ने काम करना बंद कर दिया है। बिजली और ईंधन की कमी के कारण लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। फिलस्तीनी क्षेत्रों में अकाल जैसे हालात बन गए हैं।

हमास को अपने अपराधों पर कोई अफसोस नहीं है और वह बंधकों को छोड़कर युद्ध खत्म करने की कोशिशें भी नहीं कर रहा। वहीं इस्राइल ने आईसीसी अभियोजक के इस दावे को जोरदार तरीके से खारिज कर दिया है कि गाजा में आईडीएफ का अभियान जानबूझकर फिलिस्तीनी नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से है। युद्ध अपराध और मानवाधिकार की समस्या को लेकर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की निष्पक्षता को नकारने से वैश्विक ताकतों ने भी परहेज नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस निर्णय को भयावह बताते हुए कहा कि इस्राइल और हमास के बीच कोई समानता नहीं है। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला ने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार और आतंकवादी संगठन की झूठी तुलना को भयावह और पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया।

इस्राइली राष्ट्रपति इसहाक हरजोग ने इस्राइल को लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार और हमास को नृशंस आतंकवादी बताते हुए आईसीसी की तुलना को अपमानजनक कहा। वहीं हमास नेताओं ने करीम खान की मांग के बारे में कहा कि वो कातिल और पीड़ित को एक बराबर रख रहे हैं। दुनिया भर में युद्ध और हिंसा के हालात हैं, ऐसे में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के निर्णय को नजीर की तरह लिया जाना चाहिए था जिससे संयुक्त राष्ट्र में करोड़ों लोगों का विश्वास बढ़ सकता था। वहीं संकट यह है कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के निर्णयों का पालन कैसे होगा। आईसीसी के समझौते पर जिन 124 देशों ने हस्ताक्षर किए थे उनमें इस्राइल शामिल नहीं है। यानी आईसीसी का सदस्य नहीं है। फिलस्तीन समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में शामिल है, ऐसे में आईसीसी के पास कानूनी अधिकार है कि वो कार्रवाई कर सके। अब सवाल है कि अगर वारंट जारी किया जाता है तो फिलस्तीनी प्रशासन को हमास के नेता याह्या सिनवार, हमास की अल कासिम ब्रिगेड के नेता मोहम्मद दियाब इब्राहिम अल मसरी और हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हनियेह को गिरफ्तार करना होगा। फिलस्तीन में कोई प्रशासन है ही नहीं और यह हमास के प्रभाव क्षेत्र में है।

अतः नामुमकिन है कि हमास अपने प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर ले। वहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ वारंट जारी किया जाता है तो आईसीसी के जिस समझौते पर जिन देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, उनको मौका मिलने पर जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया गया है, उसे हिरासत में लेना होगा। नेतन्याहू को दूसरा कोई देश गिरफ्तार कर ले, यह भी नामुमकिन है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के गिरफ्तारी वारंट को जायज ठहराते हुए करीम खान ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों और सशस्त्र संघर्ष से जुड़े कानूनों को सभी पक्षों को मानना होगा, फिर चाहे आप कोई भी हों, लेकिन लगता है कि गिरफ्तारी वारंट ठीक उसी तरह मजाक बन जाएगा, जैसे पुतिन के खिलाफ जारी होने के बाद भी वे चीन के खास मेहमान बन कर आ गए थे।

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने इस्राइल और हमास पर जो आरोप लगाए हैं, उनकी पुष्टि घटनाओं से की जा सकती है। सात अक्टूबर, 2023 को हमास ने इस्राइल पर हमला किया था। हमले में 1200 लोग मारे गए थे और कई लोगों को बंधक बनाया गया था। हमास के लड़ाकों ने कई महिलाओं के साथ गैंगरेप किए, उनकी निर्मम हत्याएं की और उनके शरीर को क्षत-विक्षत कर दिया। कई लोगों की गर्दन और उनके अंग काट कर सड़क पर फेंक दिए गए और फिर आतंकी उनके साथ खेल रहे थे। कई लोगों ने लोगों की हत्या, रेप और सिर काटे जाने की आवाजें और चीखें सुनीं

भारतीयों में बढ़ रही हवाई यात्रा की चाहत

- पहले से कहीं अधिक भारतीय अब देश के भीतर या बाहर की हवाई यात्रा कर रहे हैं। मास्टरकार्ड इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट (एमईआई) की रिपोर्ट 'यात्रा रुझान 2024: सीमाओं से परे' में कहा गया है कि 2024 में बढ़ते मध्यम वर्ग और हवाई मार्गों की क्षमता बढ़ने से पहले से कहीं अधिक भारतीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यात्रा कर रहे हैं
- मास्टरकार्ड के मुख्य अर्थशास्त्री (एशिया प्रशांत) डेविड मान के मुताबिक, एशिया प्रशांत क्षेत्र में उपभोक्ताओं में यात्रा करने की तीव्र चाहत और मंशा है, और वे अपनी यात्राओं से बेहतरीन अनुभव हासिल करने के लिए अधिक समझदार हो रहे हैं

(स्रोत : मीडिया इन्फुटस)

एक सपा विधायक को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने 1995 में यातायात अवरुद्ध कर दिया था, और इस बाबत दर्ज मामले में अदालत उनकी जमानत अर्जी नामंजूर कर चुकी है। लेकिन बृजभूषण, जो छेड़छाड़ के अनेक आरोपों के अभियुक्त हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। अदालत को भी इस बात की ज्यादा परवाह नहीं है।

रोहिणी सिंह, पत्रकार@rohini_sgh

पुण्यतिथि | मणेन्द्र मिश्रा

किसानों के असली रहनुमा

देश की आजादी के शुरुआती दशकों में जनसंचार माध्यमों के खासे अभाव के बाद भी किसानों की लड़ाई लड़ने वाले नेता की पहचान अखिल भारतीय स्तर पर किसान मसीहा के रूप में स्थापित होना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ऐसे में चौधरी चरण सिंह समकालीन पीढ़ी के लिए उस दौर के अचंभित करने वाले नेता के तौर पर ही पहचाने जाते हैं। उनके किसान हितैषी व्यक्तित्व का ही प्रभाव रहा कि मौजूदा भारत सरकार को चुनावी वर्ष में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित कर उस महान धारा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी पड़ी।

चौ. चरण सिंह ने लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में पहली बार प्रशासनिक सेवाओं में खेतिहर और ग्रामीणों के लिए पचास फीसद आरक्षण की बात की। लालकिले की प्राचीर से बोलते हुए खेती-किसानी और नौजवानों के रोजगार को ही मुद्दा बनाते रहे। जहां एक ओर उन्होंने राजनीतिक भ्रष्टाचार से खुद को आजीवन बचाए रखा, वहीं अपने से जुड़े लोगों की शुचिता और साख के मजबूत बने रहने के लिए विशेष अनुशासन के नियम को भी बनाए रखा। उनके व्यक्तित्व का ही असर था कि राजनीति में गलत और अन्याय करने वाला शख्स उनके आसपास भी नहीं आ सका। देश के शीर्षस्थ पद पर पहुंचने की यात्रा के दौरान वे राग-द्वेष से पूरी तरह मुक्त रहकर अपनी दिनचर्या का संपूर्ण समय समाज के वंचित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के विषय में कार्य करते रहे। उनके लेखन को पढ़ने और समझने से एक दृष्टि पैदा होती है कि कैसे राजनीति में रहते हुए चकाचौंध से दूर रह कर आमजन के हित का काम पूरी ईमानदारी से किया जा सकता है। 1937 में पहली बार बागपत-गाजियाबाद परिक्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद ही उन्होंने 'लैंड यूटीलाइजेशन बिल' बनाकर सरकार द्वारा इस पर विशेष विचार का आग्रह किया था। फलस्वरूप किसान आंदोलन के अग्रणी नेताओं ने उन्हें विशेष महत्त्व दिया। किसान आंदोलन के प्रो. एन.जी. रंगा ने 'मंडी समिति एक्ट' में चरण सिंह के सुझावों को शामिल किया था। 1950 में यूपी के मुख्यमंत्री संपूर्णानंद की सरकार में चौधरी साहब के प्रयास और मार्गदर्शन में ही जमींदारी उन्मूलन विधेयक बना जो एक जुलाई, 1952 को लागू भी हो गया।

इसी तरह 1964 में सुचेता कृपलानी की सरकार में बतौर कृषि मंत्री उन्होंने 'कृषक समाज' की स्थापना के

माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का प्रयास शुरू किया जिसे आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री बनने के बाद 'चकबंदी कानून' को अतिरिक्त मजबूत करते हुए किसान हित का ध्यान रखा। 23 दिसम्बर, 1977 को केंद्र सरकार द्वारा उन्हें मंत्रिमंडल से निकाले जाने के विरोध में आयोजित किसान रैली की ऐतिहासिक भीड़ के विषय में जानकर तत्कालीन समय में उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। 1977 में जनता पार्टी की प्रथम बैठक में भारतीय अर्थव्यवस्था और किसान नीति की बेहतरी के लिए बनाई गई रिपोर्ट की चर्चा करते हुए उन्होंने लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए बजट का 40 प्रतिशत हिस्सा कृषि पर व्यय करने से लेकर 50 फीसद गांवों के विकास पर खर्च करने का पक्ष रखा। किसान विकास योजनाओं में धन की पर्याप्त उपलब्धता करने के लिए उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान नाबार्ड का गठन किया जिसकी सफलता आज भी निर्विवाद है। 'मेरे सपनों का भारत' विषय पर चर्चा करते हुए उन्होंने पांच बिंदुओं पर अपनी बात कही थी कि प्राथमिक आवश्यकताएं सब की पूरी हों, ऐशो-आराम की चीजें नहीं। दूसरे, सब को रोजगार मुहैया हो, तीसरे, अमीरों और गरीबों में अंतर कम से कम होता जाए। चौथे, हर आदमी ईमानदार हो अर्थात देश में भ्रष्टाचार न हो और हर आदमी रोटी कमाने के काम में स्वतंत्र रहे, अपने कर्त्तव्य का ईमानदारी से पालन करता रहे। पांचवें, हर आदमी अपने मुल्क को तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाने का स्वप्न देखे और एक यह भी कि भारत में ऊंच-नीच का भेदभाव बिल्कुल न रहे।

इसके साथ ही चौधरी साहब ने एक ठोस आर्थिक नीति का मॉडल प्रस्तुत किया। गांधीवादी परंपरा के चौधरी चरण सिंह अपने सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत संपत्ति के आग्रह से पूरी तरह दूर रहे। 1974 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनके दो प्रिय शिष्य नौजवान सतपाल मलिक और राजेन्द्र चौधरी उभरे जो आज भी उस धारा के प्रकाश बिंदु के रूप में क्रमशः पूर्व राज्यपाल एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री के रूप में उनकी वैचारिकी को जीवंत बनाए हुए हैं। बीते कुछ वर्षों में जिस तरह किसानों के मुद्दों और उनका दखल एक दबाव समूह के रूप में उभरा है उसे चौधरी साहब की नीतियों के आधार पर समाजवादी विचार परंपरा के वाहक अखिलेश यादव राजनीति के केंद्र में बनाए हुए हैं। आज जब राजनीति व्यवसाय, विचारहीनता और पदलोलुपता के मकड़जाल में उलझता चला जा रही है, ऐसे में चौधरी चरण सिंह की याद बेपटरी हो चुकी राजनीति में प्रकाशपुंज की भांति प्रतीत होती है। चौधरी साहब की पुण्यतिथि पर सच्ची श्रद्धांजलि उनकी किसानोन्मुख छवि पर आमजन के बीच विमर्श करते हुए किसानों की मूलभूत समस्याओं के विषय में मौलिक एवं सहज समाधान प्राप्त करने का प्रयास हो सकती है।

पसंद-नापसंद | सद्गुरु

आध्यात्मिक प्रक्रिया के बारे में बहुत ज्यादा लिखा, कहा, और किया जा चुका है। यह

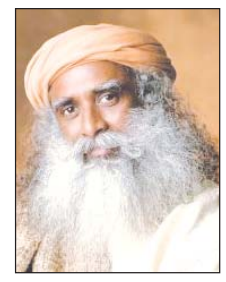

कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको अपने जीवन में बाहर से लानी है। यह ऐसी चीज है जो आप हैं। आप सिर्फ उसी की खोजबीन कर रहे हैं, जो मौजूद है। यह कह चुकने के बाद, वह क्या है जो आपको अपने प्राणी की प्रकृति की खोजबीन करने और जानने नहीं देता? यह इस पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक पहलू के साथ, और साथ ही अपने कर्म संग्रह के साथ कितना उलझे हुए हैं। सामाजिक प्रणालियां आपको तमाम चीजों के बारे में सख्त पसंद-नापसंद बनाने में प्रशिक्षित करती हैं। आपका शारीरिक ढांचा और आपका मनोवैज्ञानिक ढांचा इस पर निर्भर करता है कि आपका कर्म संग्रह किस किस्म का है। आप उसमें कितनी गहराई से घिरे हुए हैं। यह इस पर निभर करता है कि आपने उसके साथ कितनी गहरी पहचान बनाई हुई है। किसी चीज के साथ खुद को जोड़ने की प्रक्रिया आपके जीवन और सामाजिक सिस्टम में बनी हुई है-दुनिया में हर जगह, कई अलग-अलग तरीकों से। उदाहरण के लिए, जब आप दो साल के थे, तो हो सकता है कि आप बहुत आकर्षक न रहे हों, लेकिन अगर आपके माता-पिता ने यह न माना होता कि आप बहुत प्यारे हैं, तो उन्होंने आपके डायपर नहीं बदले होते, चीखती-चिल्लाती रातें बिना सोए नहीं गुजारी होतीं। जब आपको लगता है कि आप किसी के प्रेम में हैं, तो आप उनके अच्छे गुणों को बढ़ा-चढ़ाकर देखते हैं। जब आप किसी से घृणा करते हैं, तो आप उनके सारे दुर्गुणों को बढ़ा-चढ़ाकर देखते हैं, या उनकी बुराइयां खोज लेते हैं। एक व्यक्ति के रूप में आप जो हैं-एक प्राणी के रूप में नहीं-वह आप अपनी पसंद-नापसंद के कारण हैं। यह आपकी पसंद-नापसंद हैं जो आपके व्यक्तित्व को तय करती हैं, और एक व्यक्ति के रूप में आपको अलग बनाती हैं। आज से शुरुआत करके, आप बस अपनी एक पसंद और एक नापसंद को चुन लीजिए और, एक महीने के समय में, सचेतन होकर उन्हें दूर कर दीजिए। हर महीने इस प्रक्रिया को दोहराइए। आपने अपने व्यक्तित्व के रूप में जो झूठ रच रखा है, उसका आधार आपकी पसंद-और नापसंद हैं।

रीडर्स मेल

ईवीएम की पारदर्शिता पर सफाई

चुनाव आयोग को बार-बार ईवीएम की सुरक्षा और पारदर्शिता पर सफाई देनी पड़ रही है। कुछ विपक्षी नेता ईवीएम की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठा रहे हैं जबकि चुनाव आयोग ने सभी प्रत्याशियों को मशीन से जुड़ी पूरी जानकारी दी है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय भी ईवीएम की सुरक्षा पर अपनी मुहर लगा चुके हैं। बावजूद, विपक्षी दल बार-बार इसे मुद्दा बनाते रहते हैं। समझना आवश्यक है कि चुनाव आयोग ने सभी आवश्यक उपाय किए हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे। हमें ईवीएम पर दोषारोपण की बजाय अपनी चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। ईवीएम का उपयोग पिछले कई चुनावों में सफलतापूर्वक किया गया है और इसने हमारी चुनाव प्रक्रिया को तेज और निष्पक्ष बनाया है। हमें तकनीकी सुधारों के साथ-साथ राजनीतिक दलों के बीच विश्वास बहाल करने की दिशा में भी कदम उठाने चाहिए। सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि चुनाव प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए सभी मिलकर काम करें।

अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़, उप्र

जैव-विविधता पर दबाव

भारत जैव-विविधता समृद्ध देश है। विश्व का 2.4 प्रतिशत क्षेत्रफल होने के बावजूद यह विश्व की 7-8 प्रतिशत प्रजातियों (जिनमें 45,000 पादप प्रजातियां एवं 91,000 जंतु प्रजातियां) का पर्यावास स्थल है। विश्व के 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से चार भारत में हैं। विश्व के 17 मेगा-डायवर्सिटी देशों में भारत शामिल है। जब दुनिया के लोगों के सामने अपने उन कुदरती इको सिस्टमों का पुनरुद्धार करने की चुनौती है, जो विभिन्न कारणों से नष्ट हो रहे हैं तो इस व्यापक चिंता से भारत के लोग भी अलग नहीं रह सकते। बहुत तेज गति वाली आर्थिक वृद्धि और विकास नियोजन में पर्यावरणीय चिंताओं को इंटीग्रेट न कर पाने की सीमाओं या कमजोरियों या दूरदर्शिता के अभाव के चलते भारत की जैव-विविधता पर भी अनावश्यक और अतिरिक्त दबाव पड़ रहे हैं। ऐसे में संरक्षण की हर स्तर की पहल स्वागत योग्य है। खासकर यह ध्यान रखते हुए कि जैव संपदा और मनुष्य अस्तित्व के बीच गहरा नाता है।

अमित बैजनाथ गर्ग, ई मेल से

संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की दरकार

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर इस उद्देश्य से की थी कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय संघर्ष के मामलों में हस्तक्षेप करने से भविष्य में पुनः विश्व युद्ध जैसे हालात न उभरने पाएं। अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस वैश्विक शांति के लिए अपने प्राणों की आहूति देने वाले ऐसे संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों की स्मृति के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने शांति स्थापना में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इस दिन संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रबंधन कार्यों में अपने उच्च स्तर की व्यावसायिकता, समर्पण और साहस का प्रदर्शन करते हुए जान गंवाने वाले शांति रक्षकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से आज हालात अलग हैं, और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर अनेक मौकों पर सवालिया निशान भी लगते रहे हैं। भीषण रूस-यूक्रेन युद्ध और इस्राइल-फिलिस्तीन युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र अब तक कुछ नहीं कर सका है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र में आमूल फेरबदल की मांग निरंतर उठ रही है।

योगेश कुमार गोयल, दिल्ली
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **जिया कादरी** द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। **समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र*** ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, **फैक्स** - 23352370, **दूरभाष - नोएडा प्रेस** 0120-2444755, 2444756 **फैक्स** - 2550750

वर्ष-33, अंक 285 आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

https://t.me/AINewsPaper

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। बुधवार, 29 मई 2024

पद्मश्री ने इलाज रोका

छत्तीसगढ़ के बस्तर स्थित नारायणपुर जिले में रहने वाले 'वैद्यराज' हेमचंद मांझी की निराशा चिंताजनक है। 72 साल के मांझी 20 साल की उम्र से जड़ी-बूटियों के सहारे आदिवासियों का इलाज करते रहे हैं। लेकिन माओवादियों की ओर से लगातार मिलती धमकियों से तंग आकर उन्होंने अपना यह काम बंद करने का फैसला किया है।

माओवादियों का कोप | मांझी को आदिवासियों की आजीवन सेवा की एवज में पिछले महीने ही पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। लेकिन माओवादियों का कोपभाजन वह पहले से बने हुए हैं। छह महीने पहले माओवादियों ने उनके भतीजे कोमल की हत्या कर दी थी। उनके कई और रिश्तेदार माओवादी हिंसा की भेंट चढ़ चुके हैं।

माओवादियों का डर

गद्दारी का आरोप | माओवादियों मांझी को गद्दार बताते हुए आरोप लगाते हैं कि वह स्थानीय आमदायी खदान प्रॉजेक्ट को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। मांझी खदान प्रॉजेक्ट से कोई लेना-देना होने से इनकार करते हैं।

दोतरफा विरोध | माओवाद प्रभावित इलाकों में इस तरह की स्थिति कोई नई बात नहीं है। इन इलाकों में पुलिस-प्रशासन और प्रॉजेक्ट संचालकों से माओवादियों का सीधा और तीखा विरोध होता है। ऐसे में इन इलाकों में शांतिपूर्ण ढंग से आदिवासियों के बीच रचनात्मक कार्य कर रहे लोगों को अक्सर इन दोनों ही पक्षों का विरोध झेलना पड़ता है। पुलिस उन्हें नक्सल सिंपैथाइजर समझती है तो नक्सली उन पर पुलिस और पूंजीपतियों का एजेंट होने का ठप्पा लगाते हैं।

दो नजरिये | निश्चित रूप से इसका स्थायी इलाज यही है कि इन क्षेत्रों को माओवादी प्रभाव से मुक्त किया जाए। लेकिन काफी कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसके लिए उपाय क्या अपनाए जा रहे हैं। आम तौर पर दो ही स्थितियां दिखती हैं। कुछ सरकारें माओवाद को सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक समस्या मानते हुए पुलिस कार्रवाई के मोर्चे पर ढिलाई बरतने लगती हैं तो कुछ अन्य सरकारें पूरा जोर पुलिस बलों की सख्ती पर लगा देती हैं।

सख्ती के साथ पारदर्शिता | छत्तीसगढ़ में हाल के दिनों में पुलिस कार्रवाई पर जोर बढ़ा है। इस साल के इन पांच महीनों में ही सुरक्षा बलों के हाथों 116 माओवादी मारे जा चुके हैं जबकि 2023 में पूरे साल के दौरान यह संख्या 22 थी। स्वाभाविक ही फेक एनकाउंटर के आरोप भी लग रहे हैं। पुलिस की सख्ती माओवाद से मुक्ति के प्रयासों का अहम हिस्सा है और रहेगी। लेकिन जरूरी है कि बेकसूरों के मारे जाने की किसी भी शिकायत को अनदेखा न किया जाए क्योंकि फेक एनकाउंटर का कोई एक भी मामला दर्जनों जेनुइन ऑपरेशंस के असर पर पानी फेर देता है।

इन दिनों

AI में भारत

मृत्युंजय राय

दुनिया में इन दिनों टेक्नॉलजी वॉर भी चल रही है। यह मुकाबला खासतौर पर अमेरिका और चीन के बीच दिख रहा है। इस जंग में चीन की बढ़त रोकने के लिए अमेरिका से कई चीजों के वहां निर्यात पर प्रतिबंध लगा है। खासतौर पर अत्याधुनिक चिप के चीन को निर्यात पर उसने सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं। यह बात इसलिए मायने रखती है कि जेनरेटिव AI का जमाना शुरू हो चुका है, जिसके लिए खास चिप की जरूरत पड़ती है। अमेरिका और चीन दुनिया की दो बड़ी इकॉनमी हैं और भारत के कुछ वर्षों में पांचवें से तीसरे नंबर पर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है।

केंद्र सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प भी किया है। लेकिन इसके लिए भारत को भी AI और जेनरेटिव AI की टेक्नॉलजी में आगे बढ़ना होगा, जिसमें अभी वह पीछे है। कई चीजें हैं, जो इसमें भारत की मदद कर सकती हैं। गूगल के बॉस सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के बॉस सत्य नडेला ने इसकी ओर इशारा किया है। दोनों का कहना है कि भारत को AI युग में ले जाने में यहां इंटरनेट यूजर्स की बड़ी संख्या मददगार हो सकती है।

भारत की दूसरी बड़ी ताकत है सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की भारी संख्या। असल में, AI की मदद से अगर देश प्रॉडक्टिविटी बढ़ाने में कामयाब रहा तो उसके लिए विकसित देश के लक्ष्य की ओर बढ़ना आसान होगा। इन्फॉरमेशन टेक्नॉलजी सर्विसेज की दुनिया में वह अपना मकाम बना चुका है। AI की मदद से सर्विसेज एक्सपोर्ट कहीं अधिक तेजी से बढ़ सकता है। रघुराम राजन जैसे अर्थशास्त्री भी कह चुके हैं कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तुलना में सर्विसेज इंडस्ट्री की ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ने हाल के वर्षों में कुछ चीजों की मैन्युफैक्चरिंग में कामयाबी हासिल की है। खासतौर पर एपल की भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कामयाब रही है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी यह कामयाबी दिख रही है। वहीं, डिफेंस एक्सपोर्ट में भी पिछले कुछ वर्षों में अच्छी बढ़ोतरी हुई है।

मौजूदा सरकार 'आत्मनिर्भर भारत' कैंपेन के जरिये इन क्षेत्रों पर ध्यान दे रही है और उसने परफॉरमेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) जैसी योजनाएं भी कई क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की हैं। ये प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन AI में काममयाबी का भी भारत के पास आधार है। हां, इसके लिए लोगों को स्किल सिखानी होगी। यहां सरकार की भूमिका हो सकती है। दूसरी ओर, बड़ी टेक्नॉलजी कंपनियां अपने एंप्लॉयीज को जल्द ही AI स्किल्स सिखाना शुरू कर सकती हैं। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इंडस्ट्री में AI के जानकारों की मांग बढ़नी तय है, जो देश को विकास के नए रास्ते पर ले जाएंगे।

एकदा

सच की ताकत

तब बॉम्बे (मुंबई) ब्रिटिश भारत का एक प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। वहां रुस्तमजी सहराबजी मुदलियार का व्यापार और कानून का व्यवसाय था। बोलचाल में लोग उन्हें रुस्तमजी कहते थे। वह गांधीजी के मुवक्किल और निकटतम सहयोगी भी थे। वह अपना अधिकतर कार्य गांधीजी की सलाह से ही करते थे। उन दिनों कलकत्ता से उनका सामान आता था, पर वह इस पर चुंगी चुराते थे। यह बात उन्होंने गांधीजी से छिपाई हुई थी। संयोगवश एक बार चुंगी अधिकारियों ने उनकी यह चोरी पकड़ ली। अब उनके जेल जाने की नौबत आ गई। स्वयं को मुसीबत में देखकर वह दौड़े-दौड़े गांधीजी के पास गए और बोले, 'बापू, किसी तरह मुझे जेल जाने से बचा लीजिए। जो आप कहेंगे, मैं वही करूंगा।' गांधीजी को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने रुस्तमजी को बुरी तरह फटकारा। वह बोले, 'अगर तुम वास्तव में मेरी सलाह मानना चाहते हो, तो अधिकारियों के पास जाकर अपना अपराध स्वीकार कर लो। सच बोलने से तुम्हें जेल ही क्यों न हो जाए, पर तुम्हारी अंतरात्मा को संतुष्टि मिलेगी। सच बहुत बड़ी शक्ति है।' रुस्तमजी तुरंत चुंगी अधिकारियों के पास पहुंचे और उनके समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अधिकारी उनकी स्पष्टवादिता से प्रसन्न हुए और बोले, 'यदि तुम चुंगी की बकाया राशि से दोगुनी राशि जमा करा देते हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन याद रखना कि तुम्हें तुम्हारे सच बोलने के कारण और इस शर्त पर छोड़ा जा रहा है कि भविष्य में तुम ऐसा कभी नहीं करोगे।' रुस्तमजी ने स्वीकार कर लिया। अब रुस्तमजी सच की शक्ति को पहचान चुके थे।

Subrata Dhar

संकलन : **रेनू सैनी**

इब्राहिम रईसी की हेलिकॉप्टर हादसे में मौत के बाद देश के लिए राजनीतिक संकट गहरा गया है

ईरान के लिए क्या है सबसे बड़ा सवाल

अमिताभ सिंह

ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की पिछले दिनों हेलिकॉप्टर दुर्घटना में हुई अकाल मौत ने ईरान और पश्चिम एशिया क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति को लेकर अहम सवाल खड़े किए हैं। यह घटना इस्राइल-हमास संघर्ष की पृष्ठभूमि में ईरान और इस्राइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई है। ध्यान रहे, इस संघर्ष में 35,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं।

प्रतिरोध की धुरी | खास बात यह कि ईरान इस संघर्ष का एक पक्ष है। यह इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में अपने प्रॉक्सी के जरिए इस्राइली राज्य के खिलाफ प्रतिरोध में शामिल है और इसे 'प्रतिरोध की धुरी' बताता है। वैसे, शुरुआती जांच के मुताबिक, यह मौत एक दुर्घटना थी। इसके पीछे किसी तरह की अंतरराष्ट्रीय या घरेलू साजिश की संभावना को अधिकारियों ने खारिज कर दिया है।

उत्तराधिकारी कौन | इब्राहिम रईसी की इस अचानक और दुखद मृत्यु का पहला प्रभाव ईरानी राजनीति पर पड़ने वाला है। सबसे बड़ा सवाल जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है, यह है कि रईसी का उत्तराधिकारी कौन होगा। ईरान के लोगों के मन में दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई का उत्तराधिकारी कौन बनेगा?

रखी मजबूत नींव | इब्राहिम रईसी एक कट्टर धार्मिक प्रचारक थे, जिन्हें अयातुल्लाह अली खामेनेई की अगुआई वाली ईरान की सर्वोच्च परिषद के सदस्यों का वरदहस्त हासिल था। 1980 के दशक में केवल 25 वर्ष की उम्र में वह ईरान के स्टेट प्रॉसीक्यूटर बन गए थे। उन्हें ईरान में इस्लामी शासन की मजबूत नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। हालांकि इस क्रम में वह इस्लामी गणराज्य का विरोध करने वाले बहुत से लोगों की फांसी के लिए भी जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। इस्लामी गणराज्य ईरान में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए, उन्हें अक्सर सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था।

नाजुक है मामला
- इस्राइल-ईरान रिश्तों में है तनाव
- जारी है ईरानी परमाणु कार्यक्रम
- रूस-चीन-ईरान त्रिगुट का खतरा

बड़े बदलाव के आसार नहीं | बहरहाल, रईसी की मौत किसी भी तरह से ईरानी राजनीति में कोई बड़ा बदलाव लाएगी, इसके कोई आसार नहीं दिखते। हालांकि ईरान में नियमित शासन संचालन में उनकी अहम भूमिका रहती थी और वह कट्टरपंथियों की पसंद माने जाते थे। उनके नेतृत्व में, ईरान ने इस्राइल पर हमला करके अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया और चीन, भारत और रूस जैसी बड़ी शक्तियों के साथ दोस्ती की। हालांकि उन्होंने या धार्मिक नेतृत्व ने इस्राइल या अमेरिका के साथ सीधे टकराव मोल नहीं लिया, लेकिन इस क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति का एहसास कराने में पीछे नहीं रहे।

AP

दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार के दौरान तेहरान में भावभीनी विदाई

विदेश नीति की कामयाबी | रईसी की विदेश नीति की प्राथमिकताएं कई लिहाज से सराहनीय मानी जाती हैं। उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस का समर्थन किया। उसे ड्रोन की सप्लाई की। रूस भी चीन को पीछे छोड़ते हुए ईरान में सबसे बड़ा निवेशक बन गया। चीन के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने में भी वह उतने ही कामयाब रहे। वह 20 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले ईरानी राष्ट्रपति बने और अरबों डॉलर के 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 2023 में चीन को ईरान का तेल निर्यात 50% बढ़ गया।

परमाणु संवर्धन कार्यक्रम | उन्होंने 2023 में ईरान को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की सदस्यता दिलाई और 2024 में भारत के आमंत्रण पर वृहद-ब्रिक्स के सदस्य बने। उनके शासन के दौरान ईरान और सऊदी अरब के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित होना भी एक बड़ी घटना रही। यही नहीं अमेरिका, इस्राइल और अन्य शक्तियों की आपत्तियों के बावजूद उन्होंने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम की योजना जारी रखी।

नाजुक हालात | यह त्रासदी ऐसे समय हुई है, जब इस्राइल और ईरान के बीच सैन्य तनाव चरम पर है। 1979 में एक इस्लामी राष्ट्र बनने के बाद से पहली बार ईरान ने सीधे इस्राइल पर हमला किया और जवाब में इस्राइल ने भी इस्फहान में हवाई हमले किए। इस्राइल-हमास संघर्ष के निकट भविष्य में अंत का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। ऐसे में ईरान की विदेश नीति में बड़े बदलाव की कोई संभावना नहीं मानी जा सकती। पूर मामले का केंद्रबिंदु यह है कि ईरान में दो उत्तराधिकार कैसे तय होते हैं: एक नए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और ईरान के सर्वोच्च नेता का दीर्घकालिक उत्तराधिकारी कौन होता है।

बढ़ेगा दबाव | अमेरिका और इस्राइल मौजूदा हालात का फायदा उठाते हुए ईरान को राजनीतिक और आर्थिक तौर पर दबाव में लाने का प्रयास करेंगे। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पहले से विवाद का विषय रहा है। इसी के चलते पश्चिम और व्यापक विश्व के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो पाए।

गंभीर चुनौती | अगर ज्यादा दबाव डाला गया तो संभव है कि ईरान, चीन और रूस के ज्यादा करीब चला जाए। ऐसा हुआ तो क्षेत्र और विश्व में गंभीर चुनौती की स्थिति पैदा हो सकती है। कुल मिलाकर, ईरान के भविष्य के लिहाज से यह देखना दिलचस्प होगा कि वह इस्राइल-हमास संघर्ष पर कैसे प्रतिक्रिया करता है और अपने परमाणु मुद्दे को कैसे संभालता है।

(लेखक स्कूल ऑफ इंटरनैशनल स्टडीज, JNU में असिस्टेंट प्रफेसर हैं)

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

शास्त्र ज्ञान देते हैं पर आत्मज्ञान गुरु से ही मिलता है

आनंदमूर्ति गुरुमां

'**दीपो दीपान्तरं** यथा', जैसे किसी अनजले दीपक की बत्ती को जले हुए दीपक के पास ले जाने से उसकी ज्योति उछल कर अनजली बत्ती तक चली जाती है और दूसरा दीपक भी रोशन हो उठता है, उसी तरह से गुरु का संपर्क भी खोजी को रोशन कर देता है। गुरु एक जला हुआ दीपक है और खोजी एक अनजला दीपक। गुरु के समीप रहते-रहते शिष्य को एक दिन ज्ञान का प्रसाद मिल ही जाता है। शिष्य के अंतःकरण में ब्रह्मभाव को प्रकट कर देते हैं सद्गुरु।

गुरुदेव की कृपा से अपने भीतर ही आत्मानंद प्राप्त कर, समता और मुक्ति के मार्ग से शिष्य आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है। ज्ञान अगर किताबों, शास्त्रों और उपनिषदों में है, तो जाकर पढ़ लो, ढूंढ लो, देख लो! वेद, शास्त्र और श्रुतियों को पढ़कर आप विद्वान तो हो सकते हैं, पर आत्मज्ञानी नहीं हो सकते। आत्मज्ञानी तो आप केवल गुरु की कृपा से ही हो सकते हो। कोई और तरीका नहीं है!

गुरु की कृपा से ही आपके अंदर सबसे पहले आती है समता। समता का अर्थ क्या है? अभी आप अपने जीवन को दो हिस्सों में बांटकर जी रहे हैं, एक मैं और एक तू। इस 'मैं' के साथ 'मेरे' पन का और 'तू' के साथ 'तेरे' पन का जाल भी आ जाता है। मैं और मेरा परिवार, तू और तेरा परिवार। इस तरह हमारी कितनी सारी 'मैं' हैं और कितने सारे 'तू'। इन्हीं भिन्न-भिन्न 'मैं' और भिन्न-भिन्न 'तू' का नाम संसार है। 'मैं और मेरा परिवार खुश रहे, सुखी रहे, दुखी न हो, बंधन न हो, मेरा परिवार आनंद में रहे, हम भय और शोक से मुक्त रहें। अगर तुम्हारे कारण मेरे सुख में बाधा पड़ जाए तो मैं तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं चाहूंगा। मैं तुमसे लड़ूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा, ताकि तुम मुझे पीड़ा न दे सको।' इस तरह का भाव रखना समता नहीं है। समता यानी सम दृष्टि से देखना। मैं और तू में भेद न करना।

शिष्य इस तरह मैं और तू का भेद अपने मन में न रखें। सभी अपने हैं, ऐसी सोच हो। शिष्य अपने शरीर के संबंधियों को वैसे ही देखता है, जैसे कि वे दुर्घटनावश हुए हैं। जैसे मां-बाप के दुर्घटनावश मिलने से तुम पैदा हो गए, ऐसे ही दुर्घटनावश तुम भी अपने बच्चों के मां-बाप बन जाते हो। ऐसे ही तो यह संसार चल रहा है। यहां सब कुछ सच सा लगता है। एक के बाद एक का आना, रिश्ता बनते जाना। शादी होना, फिर बच्चा होना, फिर बच्चे की शादी होना। संसार के इस क्रम में तुम्हें कोई यह कहने वाला मिलता ही नहीं कि यह संसार झूठ है! तेरे दादा-दादी नहीं रहे, तेरे मां-बाप भी एक दिन नहीं रहेंगे। एक दिन तू भी चला जाएगा। इसलिए तू उसी का चिंतन कर जो अजर, अमर, अविनाशी है। तू उसी को तलाश जो सत्य सनातन है।

यह बात किसी सद्गुरु, किसी संत के सिवाय और कोई तुम्हें नहीं बताएगा। सत्संग में जाकर ही यह बात सुनने को मिलती है। अन्यथा कोई तुमसे नहीं पूछेगा कि ध्यान में मन ठीक से लगता है या नहीं? मन में विवेक जागा या नहीं? संसारी तो तुमसे यही पूछेगा कि पैसे कितने बनाए? कारोबार कैसा है? इसके अलावा कोई तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का हालचाल पूछ लेगा। लेकिन यह कोई नहीं पूछेगा कि मन को तुमने संसार में फंसाया तो नहीं? इस कीचड़ में कहीं गिर तो नहीं गए? 'संसार में अटकना नहीं है, इस कीचड़ में गिरना नहीं है', यह बात केवल कोई संत या गुरु ही बता सकता है।

परमाणु सामग्री की चोरी बढ़ी

क्या हैं खतरे

दुनिया भर में रेडियोएक्टिव मटीरियल चुराने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले साल ऐसी डेढ़ सौ से भी अधिक चोरियां हुई हैं। इसी हफ्ते रूस ने भारत को नेक्स्ट जेनरेशन न्यूक्लियर फ्यूल देने की घोषणा की है, क्या भारत ऐसी चोरियों से अछूता है?

रेडियोएक्टिव मटीरियल की चोरी

2023 में 31 देशों में 168 चोरी के मामले सामने आए

इनमें से छह मामले बेहद गंभीर

- **2022 में** ऐसी 146 घटनाएं रिपोर्ट की गईं
- **बीते 30 साल में** 4,243 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए
- **कुल मामलों में** से 350 केस गंभीर

डर्टी बम
IAEA को डर है कि चोरी किए गए यूरेनियम से डर्टी बम बनाए जा सकते हैं, जो रेडियोधर्मी प्रदूषण फैला सकते हैं।

खतरा
एक टन प्राकृतिक यूरेनियम से 5.6 किलोग्राम हथियार-ग्रेड यूरेनियम बन सकता है। हिरोशिमा में अमेरिका ने 64 किलोग्राम यूरेनियम वाले एटम बम का इस्तेमाल किया था।

भारत का हाल

जून 2021 में
झारखंड में 6.4 किलोग्राम यूरेनियम के साथ सात लोग गिरफ्तार

मई 2021 में
7 किलोग्राम प्राकृतिक यूरेनियम बेचने की कोशिश में गिरफ्तारी

फरवरी 2022 में
नेपाल में दो भारतीयों सहित आठ लोग यूरेनियम जैसा पदार्थ बेचते पकड़े गए

बड़े साइबर अटैक

- 'हू एम आई=नो न्यूक्लियर पावर' ने 2014 में कोरियाई परमाणु संयंत्र हैक किया
- उत्तर कोरिया के लाजरस ग्रुप ने 2019 में भारतीय परमाणु संयंत्र में मैलवेयर डाला
- 2003 में स्लैमर वर्म ने एक परमाणु संयंत्र का कंप्यूटर संक्रमित किया

बड़ी वारदात

- जापान के याकूजा डॉन ताकेशी इबीसावा पर फरवरी में परमाणु सामग्री की तस्करी का आरोप
- 2022 में IAEA से 2.5 टन यूरेनियम गायब हुआ

न्यूक्लियर फ्यूल

रूस के परमाणु ऊर्जा प्रमुख एलेक्सी लिखचेव के मुताबिक अगले महीने रूस भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन सप्लाई कर देगा

सुरक्षा में अव्वल- ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड

सुरक्षा में फिसड्डी- उत्तर कोरिया, ईरान, भारत, पाकिस्तान, रूस

आतंकियों की क्षमता

- 2016 में ISIS की यूके और यूरोप पर परमाणु हमले की योजना
- 2014 में ISIS ने मोसुल विश्वविद्यालय के परमाणु सामग्री पर कब्जा किया
- North Caucasus के आतंकियों ने एक परमाणु पनडुब्बी जब्त करने की कोशिश की
- एक जापानी आतंकी ग्रुप ने परमाणु हथियार हासिल करने का प्रयास किया

ICONS 2024

पिछले हफ्ते विएना में हुए चौथे अंतरराष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में ये बातें सामने आईं:
- केवल 145 देश रेडियोएक्टिव मटीरियल चोरी की रिपोर्ट करते हैं
- जेनरेटिव AI अब विकिरण के नतीजों का नकली चित्र बना सकता है
- परमाणु सामग्री की चोरी और तोड़फोड़ एक बड़ा खतरा
- साइबर हमलों से लड़ने के लिए नए सुरक्षा कार्यक्रम चाहिए

(सोर्स : IAEA, NTI Index, वर्ल्ड न्यूक्लियर असोसिएशन, BBC, NYT, 9/11 कमिशन, NATO)

कंटेंट: **राहुल पाण्डेय**, ग्राफिक्स: **अमित धींगड़ा**

क्यों खास है पायल कपाड़िया की यह जीत

प्रदीप सरदाना

वह 5 अक्टूबर 1946 की शाम थी। जब फ्रांस के प्रथम कान फिल्म समारोह में एक भारतीय फिल्म 'नीचा नगर' को 'ग्रां प्री' पुरस्कार मिला तो पूरी दुनिया की निगाहें भारत को आश्चर्य से देखने लगीं। यह पहला मौका था जब किसी भारतीय फिल्म को अंतरराष्ट्रीय मंच पर कोई बड़ा सम्मान मिला था। अब 78 साल बाद वह क्षण फिर से आया। कान में भारतीय फिल्म 'All We Imagine as Light' ने ग्रां प्री जीता है।

दो नर्सों की कहानी | 'All We Imagine as Light' हिंदी-मलयाली फिल्म है। निर्देशन किया है पायल कपाड़िया ने। मुंबई की पृष्ठभूमि पर केरल की दो नर्सों, प्रभा और अनु की मार्मिक और रोमांचक कहानी दिखाती है। यह फिल्म कोई करिश्मा करेगी, इसके संकेत पहले ही मिलने लगे थे। एक तो इसलिए कि यह ऐसी भारतीय फिल्म रही, जिसे 30 बरस बाद कान फिल्मोत्सव के मुख्य प्रतियोगिता वर्ग के लिए चुना गया। इससे पहले 1994 में शाजी एन. करुण की 'स्वाहम' को सिलेक्ट किया गया था। इसी प्रतियोगिता वर्ग में प्रदर्शन से कोई फिल्म कान का प्रथम पुरस्कार 'पाम डी'ओर' या दूसरा बड़ा पुरस्कार 'ग्रां प्री' हासिल कर सकती है।

तालियों से स्वागत | 'All We Imagine as Light' प्रथम पुरस्कार तो नहीं जीत सकी, लेकिन 'ग्रां प्री' जीतकर भी ऐसा इतिहास रच दिया है, जिसे भुलाया नहीं जा सकेगा। कुल 22 श्रेष्ठ प्रतियोगी फिल्मों में से इस फिल्म को पुरस्कार मिलना गौरव की बात है। 23 मई को जब फ्रेंच रिवेरा में इसका प्रीमियर हुआ, तो खचाखच भरा सभागार झूम उठा। यह फिल्म विश्व के कई बड़े फिल्मकारों, जूरी और दर्शकों को इतनी पसंद आई कि सभी खड़े होकर लगातार 8 मिनट तक तालियां बजाते रहे।

कलाकारों की प्रशंसा | 25 मई को 'All We Imagine as Light' को ग्रां प्री देने की घोषणा हुई। जब 38 साल की पायल कपाड़िया पुरस्कार लेने पहुंचीं तो उन्होंने फिल्म के मुख्य कलाकारों - कानी कुसरुती, दिव्य प्रभा और छाया कदम को भी मंच पर बुलाया। पायल ने कलाकारों की तारीफ करते हुए कहा कि इन तीनों महिलाओं के बिना यह फिल्म संभव नहीं हो पाती।

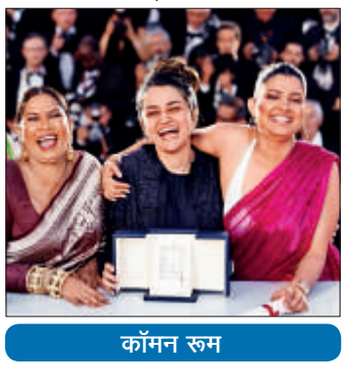

कॉमन रूम

नीचा नगर | फिल्म की टीम ने मंच पर खड़े होकर इस बड़ी सफलता को महसूस किया। हालांकि 'नीचा नगर' की टीम इस मौके को नहीं देख सकी थी। जब इसे ग्रां प्री मिला था, तो पुरस्कार लेने के लिए कान में कोई मौजूद नहीं था। फिल्म की नायिका कामिनी कौशल ने बाद में मुझसे कहा था, 'हम तो फ्रांस जा भी नहीं सके थे।'

शिखर पर कब्जा | कान फिल्म फेस्टिवल के विभिन्न खंडों में भारतीय फिल्में लगातार प्रदर्शित होती रही हैं। 'सलाम बॉम्बे' और 'द लंच बॉक्स' जैसी फिल्मों को कुछ और पुरस्कार भी मिले। लेकिन, कान के दो शिखर पुरस्कार 'पाम डी'ओर' और 'ग्रां प्री' दूर ही रहे। सत्यजीत रे, राजकपूर, वी शांताराम, बिमल रॉय, मृणाल सेन, दीपा मेहता और मीरा नायर जैसे भारतीय फिल्मकारों ने वहां काफी चर्चा बटोरी, लेकिन भारतीय दर्शकों के लिए तो कान का मतलब वहां का रेड कार्पेट ही रहा।

पुरस्कारों की झड़ी | FTII की पूर्व छात्रा पायल कपाड़िया के अलावा संस्थान के छात्र चिदानंद नायक की कन्नड़ लोककथा पर आधारित लघु फिल्म 'सनफ्लावर्स आर द फर्स्ट वंस टू नो' ने भी 'ला सिनेफ' का प्रथम पुरस्कार जीता है। वहीं, FTII के एक और पूर्व छात्र सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवन भी 'पियरे एंजनिक्स' पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई बन गए। इतना ही नहीं, भारतीय मूल की अनसूया सेनगुप्ता ने भी बुल्गारिया के फिल्मकार की 'द शेमलेस' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतकर भारत की जय-जय करा दी है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म समीक्षक हैं)

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्स: 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

कुदरत का कोप

समुद्र तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान जैसे हर वर्ष का सिलसिला बन चुका है। कभी दक्षिण भारत, तो कभी महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और ओड़ीशा इसकी तबाही झेलने को अभिशप्त हैं। हालांकि भूवैज्ञानिक अध्ययनों, मौसम विज्ञान विभाग की निरंतर निगरानी और अत्याधुनिक तकनीक की मदद से समुद्री हलचलों का पहले ही पता लगा लिया और सूचना तकनीक के जरिए लोगों को सतर्क कर दिया जाता है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा प्रबंधन दलों के सहयोग से किसी बड़े नुकसान को रोकने की कोशिश की जाती है। इस तरह काफी हद तक जानमाल का नुकसान रुक जाता है। मगर हर बार तूफान जनजीवन और अर्थव्यवस्था पर अपने गहरे घाव छोड़ ही जाता है। रविवार को बंगाल की खाड़ी से उठे रेमल चक्रवाती तूफान ने पश्चिम बंगाल के साथ-साथ पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई। अब हालांकि तूफान का वेग धीमा पड़ गया है, मगर इसका असर बिहार और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बने रहने की संभावना जताई गई है। पश्चिम बंगाल में इस तूफान ने उनतीस हजार से अधिक घरों को नष्ट कर दिया, हजारों पेड़ उखड़ गए, दो लाख से ऊपर लोगों को करीब साढ़े चौदह सौ आश्रय स्थलों पर पहुंचाना पड़ा। कई लोगों की मौत हो गई।

रेमल तूफान ने पश्चिम बंगाल सरकार के सामने एक बार फिर जनजीवन बहाल करने की बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। हजारों घरों की बिजली काट दी गई है। सैकड़ों खंभे टूट कर गिर चुके हैं। पिछले तीन दिन से पश्चिम बंगाल और असम की हवाई तथा रेल सेवाएं रोक दी गई हैं। इस तरह उन इलाकों में कारोबार को कितना नुकसान पहुंचा है, अंदाजा लगाया जा सकता है। जो लोग बेघर हो गए हैं, उनका जीवन कब पटरी पर लौटेगा, उन्हें सरकारी मदद कितनी मिल पाएगी, इस सब का आकलन करना अभी मुश्किल है। कुदरत के कोप के सामने व्यवस्थाएं किस कदर निस्सहाय पड़ जाती हैं, रेमल जैसी घटनाएं इसका उदाहरण हैं। ऐसा नहीं कि यह कोई पहली आपदा है। पिछले कुछ वर्षों में चक्रवाती तूफान, बारिश, बाढ़ और आंधी-तूफान से लगातार तबाही के मंजर सामने आते रहे हैं। उनसे पार पाने के उपाय भी सरकारें जुटाती रही हैं। मगर कुदरत के कहर को रोकने का कोई उपाय उनके पास नहीं है। छिपा तथ्य नहीं है कि प्राकृतिक आपदा की बढ़ती घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। समुद्र का स्वाभाविक तापमान उसकी सहनशीलता को पार कर चुका है। इसी के चलते अल-नीनो और ला-नीना जैसी स्थितियां पैदा होती हैं।

कुदरत बार-बार शायद यह चेतावनी दे रही है कि अगर उसके साथ छेड़छाड़ से परहेज नहीं किया गया, तो लाख उपाय किए जाएं, स्थितियां विकट ही होती जानी हैं। हर वर्ष जलवायु परिवर्तन के संकटों से पार पाने के लिए बैठकें आयोजित होती हैं, उनमें दुनिया भर के देश इससे पार पाने के उपायों पर अमल का संकल्प दोहराते हैं, मगर अभी तक इस दिशा में कोई उल्लेखनीय नतीजा सामने नहीं आ सका है। आर्थिक विकास की होड़ में कुदरत की परवाह ही किसी में नहीं दिखती। ताकतवर देश कमजोर देशों पर दबाव डाल कर प्रदूषण और हानिकारक गैसों, जहरीले रासायनिक कचरे के उत्पादन को कम करना चाहते हैं, मगर अपने ऊपर लगाम लगाने को तैयार नहीं दिखते। इसका नतीजा कुदरत के कहर के रूप में हमारे ऊपर टूट रहा है।

अक्षम्य अपराध

महाराष्ट्र के पुणे में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों की जान चली जाने के बाद आरोपी चालक को बचाने के लिए जिस स्तर के विषाक्त खेल सामने आए हैं, वे हैरान करने वाले हैं। होना तो यह चाहिए था कि आरोपी को संबंधित कानूनों के तहत कठघरे में खड़ा किया जाता और उचित सजा दी जाती। मगर अफसोस कि इसमें शुरू से ही कानूनी पक्ष को कमजोर करने से लेकर मामले को दबाने और आरोपी को बचाने के मकसद से हर स्तर पर गड़बड़ी करने की कोशिश की गई। आरोपी के नाबालिग होने के आधार पर अदालत में बिना देर किए उसे यातायात संचालन में सहयोग देने और निबंध लिखने जैसी बेहद हल्की शर्तों के साथ जमानत दे दी गई। कानून में इस तरह जमानत देने का आधार हो सकता है, मगर तथ्य यह भी है कि इस घटना में बिना पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस के शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले आरोपी की गैरजिम्मेदारी ने दो लोगों की जान ले ली।

एक गंभीर अपराध करने वाले को बचाने के पीछे इसके सिवा और क्या कारण हो सकता है कि आरोपी रईस परिवार से है और पुलिस ऐसी स्थिति में कई बार परोक्ष प्रभाव में काम करती है। सच यह है कि मामले ने तूल पकड़ा तब कार्रवाई का तरीका बदला। आरोपी की जमानत रद्द हुई और लापरवाही बरतने के आरोप में दो पुलिस अफसरों को निलंबित किया गया। यह उजागर हुआ कि अस्पताल में आरोपी के खून का जो नमूना लिया गया था, उसे कूड़ेदान में फेंक दिया गया और दूसरे व्यक्ति का खून लेकर फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजा गया। इस आरोप में दो डाक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। इस हरकत ने अन्य अपराधों के मामले में भी फोरेंसिक जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले आरोपी के दादा को ड्राइवर का अपहरण करने, धमकी देने और अपराध कबूल करने को मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस घटना के बाद जो हुआ, उससे यही जाहिर हुआ है कि समूचा तंत्र किसी रसूखदार आरोपी के बचाव में कितना गैरजिम्मेदार हो सकता है।

धरती की थाती सहेजती स्त्रियां

पर्यावरण संरक्षण, खासकर वन संरक्षण को लेकर महिलाएं शुरू से ही जागरूक रही हैं। हमारे देश में महिलाओं ने अपने जमीनी अनुभव से पर्यावरण की बहस में एक अलग दृष्टिकोण पेश किया है।

विनीता परमार

सत्तर के दशक में दार्शनिकों ने स्त्रीवादी विचारधारा में एक नई परिकल्पना जोड़ी, जिसे 'ईको फेमिनिज्म' यानी पारिस्थितिक स्त्रीवाद कहा जाता है। इसमें प्रकृति और महिलाओं में समानता स्थापित करते हुए उनकी परेशानियों को उजागर किया जाता है। पारिस्थितिक स्त्रीवाद की अवधारणा का श्रेय फ्रांसीसी स्त्रीवादी चिंतक फ्रांस्वा द यूबोन को जाता है, जिन्होंने 1974 में प्रकाशित लेख 'ले फेमनिज्म ओ ला मार्ट' में इसका उल्लेख किया था।

पृथ्वी और पृथ्वी की समानधर्मा स्त्री ने खुद को, पृथ्वी और अन्य शोषित जातियों, नस्लों को बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया। प्राकृतिक संसाधनों- वन, मिट्टी और जल से महिलाओं का सीधा और गहरा संबंध है। प्राचीन काल से महिलाओं और आदिवासियों को ही प्रकृति का संरक्षक माना गया है। आदिवासी समाज में वन-संपदा की अर्थव्यवस्था पूरी तरह महिलाओं की मानी जाती है। पर्यावरण संरक्षण, खासकर वन संरक्षण को लेकर महिलाएं शुरू से ही जागरूक रही हैं। हमारे देश में महिलाओं ने अपने जमीनी अनुभव से पर्यावरण की बहस में एक अलग दृष्टिकोण पेश किया है। गरीब महिलाओं के जीवन को भी पर्यावरण सुरक्षा के मुद्दे पर विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे मुद्दों को व्यापक और समग्र परिप्रेक्ष्य में देखती हैं। वे स्पष्ट रूप से समझती हैं कि अर्थशास्त्र और पर्यावरण एक-दूसरे पर निर्भर हैं। उन्हें पता है कि पानी और बिजली की बचत से पैसे और पर्यावरण दोनों को बचाया जा सकता है।

महिलाएं अपने घर की हर चीज के उपयोग का रास्ता खोज लेती हैं। मसलन, सब्जी के डंठल की सब्जी हो या फटे-पुराने कपड़े की कथरी। जब हम भारतीय परंपराओं और अपने आदिवासी जीवन को देखते हैं, जिसका आधार प्रकृति है, उसमें दूब घास से लेकर बाघ तक को बचाने के उपाय हैं। हमारी पुरखिनों ने सम्मान दिया तो प्रकृति ने भी उनकी रक्षा की। बहनापे के साथ महिलाएं पृथ्वी का खयाल रखती रहीं हैं। इस ग्रह के संसाधनों के उपभोग के समय खुद के विषय में स्त्री यह सोचती है कि खुद और पृथ्वी पर लोगों के निर्विवाद नियंत्रण पर अंकुश लगे।

इस बीच, अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाओं में दूसरों की देखभाल करने के मामले में उच्च स्तर का समाजीकरण होता है। इस वजह से उनमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता की संभावना बढ़ जाती है। आज भी अधिकांश महिलाएं घर के कामों, कचरा निपटान, घरेलू खरीदारी, कपड़े धोने आदि की जिम्मेदारी निभाती हैं। इसलिए धरती रक्षक अधिकांश उत्पाद महिला उपभोक्ता केंद्रित होते हैं। फिर सभ्यता के विकास के कालक्रम में पर्यावरण संरक्षण को महिलाओं ने व्रत-त्योहार से जोड़ दिया, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज भी महिलाओं द्वारा व्रत-त्योहार के अवसरों पर या यों ही प्रतिदिन के क्रियाकलापों और पूजा-अर्चना में अनेक वृक्षों यथा- पीपल, तुलसी, आंवला, अशोक, बेल, शमी, नीम, आम आदि वृक्षों तथा अनेक पुष्पों और विभिन्न पशुओं जैसे गाय, बैल, चूहा, घोड़ा, सांप, बंदर, उल्लू आदि को सम्मिलित करना और उनकी पूजा-अर्चना के माध्यम से संरक्षण करना देखने को मिलता है।

यही नहीं, जल-स्रोतों के प्रति भी संरक्षण की भावना महिलाओं में प्राचीन काल से चली आ रही है, जैसे- गंगा पूजन, कुआं पूजन, तालाब पूजन। इस प्रकार स्पष्ट है कि संपूर्ण पारिस्थितिकी को संतुलित बनाए रखने के प्रति महिलाएं सदा से अग्रणी रही हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में रची-बसी महिलाओं में प्रकृति संरक्षण की भावना पीढ़ी-दर-पीढ़ी पोषित होती चली आई है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय क्षय का महिलाओं के समय, आय, स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भारत की सामाजिक रचना, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण ने महिलाओं की जीवन-शैली को बुरी तरह प्रभावित किया है। यही कारण है कि पर्यावरण और प्रकृति से सीधे संपर्क में रहने के कारण ग्रामीण महिलाएं पर्यावरण संरक्षण के प्रति अधिक सचेष्ट हैं।

> हमारी भारतीय संस्कृति में रची-बसी महिलाओं में प्रकृति संरक्षण की भावना पीढ़ी-दर-पीढ़ी पोषित होती चली आई है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय क्षय का महिलाओं के समय, आय, स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भारत की सामाजिक रचना, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण ने महिलाओं की जीवन-शैली को बुरी तरह प्रभावित किया है। यही कारण है कि पर्यावरण और प्रकृति से सीधे संपर्क में रहने के कारण ग्रामीण महिलाएं पर्यावरण संरक्षण के प्रति अधिक सचेष्ट हैं।

आज बचे-खुचे जंगली क्षेत्रों में जहां अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, जलाने के लिए महिलाओं को लकड़ी एकत्र करने कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। खासकर रेगिस्तानी इलाकों, पठारी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में, पानी जुटाने का भी दायित्व महिलाओं पर है और पानी के लिए उन्हें 10-15 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है।

इस तरह पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं ने विशेष भूमिका निभाई है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। इन महिलाओं ने अपने आसपास की पर्यावरणीय समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की है। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुके 'चिपको आंदोलन' ने पर्यावरण संरक्षण, खासकर वन-संरक्षण की दिशा में एक नई चेतना पैदा की है। यह आंदोलन पूरी तरह महिलाओं से जुड़ा है। आज भी पहाड़ों पर महिलाएं यही प्रक्रिया अपना कर पेड़ों को बचाने में लगी हैं। यह 'चिपको आंदोलन' उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों- चमोली, कुमाऊं, गढ़वाल, पिथौरागढ़ आदि में प्रारंभ हुआ और जंगलों के विनाश के विरुद्ध सफल आंदोलन के रूप में पूरी दुनिया में सराहा जा चुका है। इस आंदोलन का संचालन करने वाली पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों की रहने वाली निरक्षर और अनपढ़ महिलाएं हैं।

पर्यावरण संरक्षण के साथ भारतीय महिलाओं की प्रत्यक्ष चिंता 1731 ई. में ही दिखाई दे गई थी। महाराजा अभय सिंह ने किले के निर्माण के लिए बिश्नोई समाज द्वारा पूजित खेजड़ी के पेड़ों को काटने का शाही आदेश दिया। उसका विरोध करते हुए अमृता देवी के नेतृत्व में गांव वालों ने असहमति का एक नया रूप प्रस्तुत किया। अहिंसक ग्रामीणों ने पेड़ों को गले लगा लिया था। इस आंदोलन में अमृता देवी के साथ उनकी तीन बेटियों और 363 ग्रामीणों के सिर कलम कर दिए गए थे।

राजस्थान में उदयपुर के निकट ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं ऊसर और रेतीली भूमि को हरे-भरे खेतों में बदल रही हैं। हिमाचल प्रदेश की महिलाएं भी पर्यावरण-संरक्षण कार्यक्रम में किसी से पीछे नहीं हैं। कर्नाटक का अप्पिको आंदोलन महत्त्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण आंदोलन है। वर्ष 2021 में कर्नाटक की आदिवासी महिला तुलसी गौड़ा को 30,000 से अधिक पेड़ लगाने के कारण पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। केरल के पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर में 'साइलेंट वैली' महत्त्वपूर्ण है, जो जैव विविधता 'हाटस्पाट' में से एक है। 'साइलेंट वैली आंदोलन' केरल सरकार के एक फैसले के खिलाफ था। वहां पनबिजली परियोजना के लिए एक बांध का निर्माण प्रस्तावित था। मलयालम कवयित्री और पर्यावरणविद सुगाथा कुमारी इसमें प्रमुख नेता थीं। परिणामस्वरूप परियोजना को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के बाद केरल सरकार ने रद्द कर दिया था। 1984 में साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया।

इस प्रकार संस्कृति, धर्म, साहित्य में महिलाओं और प्रकृति के बीच संबंधों की खोज करता पारिस्थितिक स्त्रीवाद भारत की जीवन शैली में है। जरूरत पड़ने पर महिलाओं ने संघर्ष किया, खुद से अधिक इस धरती के साथ बहनापा निभाया है। आज भी विकास के नाम पर कटते पेड़ों को बचाने के लिए महिलाएं तैयार हैं।

ज्ञान की गरिमा

अमिताभ स.

एक कहावत है कि शीशे के घरों में रहने वालों को दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। लेकिन हाल में देखा कि इस मशहूर कहावत से शायद बेखबर समझदार नेता शीशे के घरों में रहने के बावजूद अपने विपक्षी नेताओं के घरों पर पत्थर मारने से बाज नहीं आए। अपने गिरेबान में झांके बिना सभी बेमानी बहसों में उलझते रहे। इस पर एक छोटा-सा उद्धरण है- एक बार एक संत ऐसे गांव से गुजरे जहां एक विद्वान रहते थे। उनके शिष्यों ने उन दोनों में एक वाद-विवाद कराने की योजना बनाई, ताकि जाना जा सके कि कौन ज्यादा प्रतिभाशाली है। उनमें तीखी बहस का अंदेशा था, इसलिए आयोजन स्थल पर भीड़ जमा हो गई। मगर वहां जो हुआ, वह देख कर सभी हैरान हो गए। उन दोनों विद्वानों ने एक दूसरे को सादर नमन किया और चुपचाप अपने-अपने घर लौट गए। बाद में एक युवा शिष्य ने एक संत से पूछ लिया कि उन्होंने वाद-विवाद क्यों नहीं किया! संत ने जवाब दिया, 'वह जानता था कि मैं जानता हूं। मैं जानता हूं कि वह जानता था।' असल में, दोनों महापुरुषों ने उस छोटी-सी मुलाकात में ही एक दूसरे की योग्यता को भली-भांति पहचान लिया था। साथ ही, समझ भी लिया था कि केवल दिखावे के लिए कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार, शालीन मौन ने सब कुछ कह दिया।

एक श्लोक है- 'मौनं सर्वार्थ साधनम्'। तात्पर्य यह है कि मौन का औजार हर मोर्चा जीतने की शक्ति रखता है। मौन बेसिर-पैर की बहसों की और क्रोध से छुटकारे की सर्वश्रेष्ठ और कारगर चिकित्सा भी है। निराधार बोलना और कटु वचन इंसान के बड़े आंतरिक शत्रु हैं, क्योंकि इससे खुद पर की काबू खो जाता है और मुख से अपशब्द निकल पड़ते हैं। बोलने या न बोलने के द्वंद्व पर स्वामी विवेकानंद की राय है कि श्रेष्ठ इंसान होने का मतलब दूसरों को अस्वीकार करना नहीं है। श्रेष्ठ इंसान दूसरों और अपने विचारों में जो अच्छा है, बेहतर है, उसे स्वीकार करता है। साथ-साथ हमारे भीतर और दूसरों के भीतर जो बुरा है, उसे भी स्वीकार करने से नहीं पीछे हटता। इसीलिए माना जाता है कि पहलवान असली बलवान नहीं होता, बल्कि बलवान वह है, जो खामखा की बहसों में न उलझे और उससे जन्मे क्रोध में खुद को नियंत्रित रख सके। कहा भी गया है कि सहन न करना और बात-बेबात पर गाली-गलौज में उलझे रहना सही समझ के दुश्मन हैं। लेखक आरिसन स्वेट मार्डेन के मुताबिक वाद-विवाद बुरा नहीं है। इसमें बुराई तब है, जब इंसान विवेक खो देता है और आपे से बाहर हो जाता है। वास्तव में, विवेकशीलता से ही व्यक्ति सही-गलत का बोध करता है। जब-जब चित्त शांत होता है, मन-मस्तिष्क में स्थिरता आ जाती है। फिर कोई झूठ-मूठ की बहस या अपने झूठ को सच साबित करने में नहीं जुटता। इसीलिए नासमझ ही बहसों को बढ़-चढ़ कर हवा देता है, जबकि समझदार खुद पर काबू रखता है।

हर बच्चे को उसकी दादी-नानी बचपन में सीख देने वाले कई वृत्तांत सुनाती है। बाल पत्रिकाओं में भी ऐसी छोटी-छोटी कहानियां पढ़ी जा सकती हैं। ऐसा ही एक वृत्तांत है- गुरु नानक देव अपनी पद यात्राओं के दौरान मुल्तान पहुंचे, तो वहां पहले से कई धर्म प्रचारक मौजूद थे। एक संत ने उन्हें दूध से लबालब भरा कटोरा भेजा। गुरु नानक देव ने बगीचे से चमेली का एक फूल तोड़ कर दूध पर हल्के से टिका दिया और कटोरा संत को लौटा दिया। दूध से लबालब कटोरा जैसे का तैसे बिना पिए लौटा देख कर संत के शिष्य तिलमिलाए। शिष्यों को लगा कि गुरु नानक देव ने उनके गुरु का अपमान किया है। संत ने उन्हें शांत किया और समझाया- 'शिष्यो, परेशानी की कोई बात नहीं है। बात इत्ती-सी है कि मैंने गुरु नानक से एक प्रश्न किया था। प्रश्न था कि मुल्तान में पहले से ही दूध जैसे पवित्र-शुद्ध चरित्रवान संत विराजमान हैं, फिर उन्हें यहां पधारने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? उन्होंने उत्तर भेजा कि जैसे कटोरे में लबालब भरे दूध का चमेली के फूल ने तिनका भर भी हर्ज नहीं किया, बल्कि उसकी शोभा ही बढ़ाई है। मैं भी इसी तरह इस नन्हे चमेली के फूल की भांति यहां रहूंगा।' माना जाता है कि ज्यादा बोलने वाला इंसान कभी भी तथ्यपूर्ण बातें नहीं करता।

इसलिए कम बोलना चाहिए, ताकि सटीक बोला जा सके। कबीर के वचन सदियों से नसीहत दे रहे हैं कि 'ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय/ औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय'। तात्पर्य है कि बहस छिड़े, तो भी ऐसी मधुर वाणी का साथ कतई मत छोड़िए कि कहने वाले का मिजाज भी शीतल रहे और सुनने वाला भी प्रसन्न हो जाए। सो, बेहतरी और समझदारी इसी में है कि बहसबाजी में खपती भारी उर्जा को सही दिशा दी जाए। रूसी साहित्यकार चेखव यशमय जीवन के तीन सरल सूत्रों का जिक्र करते हैं- 'सदा धीमे बोलो, कम बोलो और मीठा बोलो।' यही मंत्र झूठ, क्रोध और कटुता से बचाव की शक्ति बन कर उभरता है।

दुनिया मेरे आगे

> विवेकशीलता से ही व्यक्ति सही-गलत का बोध करता है। जब चित्त शांत होता है, मन-मस्तिष्क में स्थिरता आ जाती है। फिर कोई झूठ-मूठ की बहस या अपने झूठ को सच साबित करने में नहीं जुटता। इसीलिए नासमझ बहसों को बढ़-चढ़ कर हवा देता है, जबकि समझदार खुद पर काबू रखता है।

समावेशी लोकतंत्र

वर्तमान में विश्व के ज्यादातर देश सांस्कृतिक बहुलता वाले हैं। खासकर भारत जैसी विभिन्नता, बहुलता, विश्व के किसी अन्य देश में नहीं है। प्रत्येक देश में मानव समाज किसी न किसी अनुपात में भिन्न सांस्कृतिक समूहों के मेल से बना हुआ समाज है, जो समाज में भेदभाव के प्रमुख मुद्दों को विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों के संदर्भ में संबोधित करता है। इसलिए बहुसांस्कृतिक समाज समूह विशिष्ट अधिकारों पर जोर देता है जो अल्पसंख्यक संस्कृति की सुरक्षा और पोषण के लिए आवश्यक है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत समाज के सभी वर्ग संप्रदाय और जातियों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के माध्यम से ही बहुसंस्कृतिवाद अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है, जिसमें सभी सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना और संवैधानिक रूप से उन्हें बराबर का स्थान देना है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि लोकतंत्र के भीतर समान नागरिक राजनीतिक अधिकारों को प्रदान करने के साथ-साथ समाज में व्याप्त भेदभाव को न्यूनतम और फिर खत्म किया जाए और हाशिये पर स्थित अल्पसंख्यकों जैसे समुदायों को समान अधिकार मिले।

- आशुतोष रंजन, इलाहाबाद विवि

संकट का तापमान

जलवायु परिवर्तन और बढ़ता तापमान हमारे समक्ष एक गंभीर संकट की तरह खड़ा है, जिसके प्रति अगर हम आज सजग नहीं हुए तो जल्द ही हमारे अस्तित्व के लिए यह एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इससे संबंधित खबरों में बताया जा चुका है कि बढ़ते तापमान की वजह से समुद्र का स्तर इस सदी के अंत तक इतना बढ़ जाएगा की बहुत से द्वीपों और शहरों का नामो-निशान मिट सकता है। अब भी समय है कि हम चेत जाएं। इतिहास साक्षी है कि जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चला है, वही अब तक सुरक्षित है जबकि प्रकृति के विरुद्ध जाने वाली प्रजातियों का कोई नामलेवा तक नहीं बचा है। हमें प्रकृति द्वारा निरंतर दी जा रही इन चेतावनियों को समझना चाहिए, नहीं तो हम आने वाली पीढ़ियों को जो संकट की विरासत देकर जाएंगे, उसके लिए सभ्यता का इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा।

- निपुण यादव, उन्नाव, उप्र

सहनशीलता का तकाजा

आज के युग में ऐसा लगता है कि व्यक्तियों में सहन करने की क्षमता घटती जा रही है। ऐसा शायद इसलिए है कि हमें देर-सबेर ऐसी घटनाएं देखने, सुनने या पढ़ने को मिल ही जाती हैं, जिसमें छोटी-सी बात को लेकर व्यक्ति एक दूसरे के खून के प्यासे, मारने-मरने को तैयार हो जाते हैं और घटना के बाद आने वाले नतीजों और दुखों के बारे में एक बार भी नहीं सोचते। आज स्थिति यह है कि छोटी-छोटी बातों को लेकर घर परिवार के सदस्य ही एक दूसरे को मौत के घाट उतार देते हैं। उन्हें होश नहीं रहता कि वे क्या कर रहे हैं। एक छोटी-सी गलती और पूरा परिवार बिखर जाता है। अगर परिवार के सदस्यों के बीच या अन्य से किसी बात को लेकर अनबन है तो उसका समाधान साथ बैठकर किया जा सकता है। साथ ही माता-पिता, घर के बड़े-बुजुर्गों को यह चाहिए कि वे अपने बच्चों को सहनशील बनाएं।

- रिंकू जायसवाल, सिंगरौली, मप्र

सड़क पर सफाई

पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय उच्चमार्गों से गुजरने वाले यात्रियों को एक भयंकर सडांध का सामना करना पड़ता है। यह दुर्गंध दुर्घटना में मृत पशुओं के शवों की होती है। इसकी वजह से पर्यावरण तो दूषित होता ही है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलने का भी खतरा रहता है। भारत में मृत पक्षियों और जानवरों के निपटान के लिए कोई एकल, व्यापक व्यवस्था नहीं है। हालांकि, विभिन्न कानून और नियम हैं जो विभिन्न स्थितियों में लागू होते हैं, लेकिन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रावधान करता है। इसमें मृत जानवरों के शवों को ठीक से निपटाने का प्रावधान शामिल है, ताकि वे जल निकायों या मिट्टी और वातावरण को दूषित न करें। टोल टैक्स वसूलने वाली संबंधित सड़क निर्माण कंपनियों का नैतिक दायित्व बनता है कि वे मृत पशु शवों के निस्तारण की जिम्मेदारी उठाएं।

- विमलेश पगारिया, बदनावर, मप्र

https://t.me/AINewsPaperPdf

www.readwhere.com

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

तूफान और गरमी

भारत आजकल प्रतिकूल मौसमों की मार झेल रहा है और इसमें सबसे त्रासद मिजोरम में हुआ भूस्खलन है। चक्रवात रेमल के वार से पश्चिम बंगाल तो किसी तरह संभलने लगा है, पर पूर्वोत्तर भारत में अनेक स्थानों पर बहुत बुरी स्थिति बन गई है। खराब मौसम के चलते बचाव प्रयासों में बाधा आ रही है। रेमल के असर से बिहार में भी कई स्थानों पर बारिश हुई है और उत्तर प्रदेश में भी इसके असर की संभावना है। मिजोरम में भूस्खलन व बारिश ने आइजोल को देश के बाकी हिस्सों से काट दिया है। मौसम की मार इतनी तगड़ी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-6 पर आवाजाही बंद हो गई है। पूर्वोत्तर में कई जगह चट्टानों के गिरने से कई अंतरराज्यीय राजमार्ग बाधित हो गए हैं। अधिकारी इंतजाम में लगे हैं, पर नुकसान का वास्तविक आकलन भारी बारिश के थमने के बाद ही किया जा सकेगा। आइजोल के बाहरी इलाके में पत्थर की खदान के ढहने से बीस से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है और अनेक लोग लापता हैं। असम में भी लोगों की मौत हुई है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, तो बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है।

चक्रवात रेमल ने बांग्लादेश में भी तबाही मचाई है। बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल में लाखों लोगों को एहतियातन विस्थापित किया गया है। भारत और बांग्लादेश को अगर मिला लें, तो चालीस से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है। तूफान और भारी बारिश की वजह से बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं। ज्यादातर इलाकों में विद्युत आपूर्ति बाधित है और बारिश के थमने के बाद ही आपूर्ति व्यवस्था सुधर सकती है। पश्चिम बंगाल में अकेले बिजली के 1,200 से ज्यादा खंभे गिरे हैं। तकलीफ से भरे ऐसे समय में सभी प्रभावित राज्य सरकारों को पूरी सक्रियता के साथ काम करना चाहिए। जिन लोगों ने घर-बार गंवा दिया है, उनके प्रति पूरी संवेदना होनी चाहिए। राहत कार्य में संसाधन की कमी आड़े नहीं आनी चाहिए। चक्रवात और उसके बाद बारिश के चलते कोलकाता महानगर पर भी भारी असर हुआ है। पश्चिम बंगाल के साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों में सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। समुद्री चक्रवात हमारे दौर का एक स्याह सच है, जो रह-रहकर हमें रुलाने लगा है। अतः हमें समुद्री तटों पर ऐसे इंतजाम या ऐसी बसावट के बारे में सोचना होगा, ताकि चक्रवात की स्थिति में कम से कम नुकसान हो। समुद्र तटीय इलाकों में किसी भी प्रकार के निर्माण के संबंध में मुकम्मल नीति होनी चाहिए।

देश में तूफान और बारिश से अलग एक विशाल क्षेत्र है, जहां पारा अपने आसमान को छू रहा है। कंक्रीट के जंगलों में रात में भी गरमी से राहत नहीं मिल रही है।

देश में तूफान और बारिश से अलग एक विशाल क्षेत्र ऐसा भी है, जहां पारा अपने आसमान को छू रहा है। गांवों से कहीं ज्यादा शहर के लोग परेशान हैं। कंक्रीट के जंगलों में रात के समय में गरमी से राहत नहीं मिल रही है। घर-द्वार तप रहे हैं। आगजनी की आशंका बढ़ गई है। अनेक इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। अस्पतालों को उचित ही सजग और तैयार रहने के लिए कहा गया है। आंकड़े स्पष्ट नहीं हैं, पर उत्तर भारत में पारा मौत की वजह बनने लगा है। बड़ी संख्या में लोग लू के चलते बीमार हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के छह राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अनुमान यही है कि आने वाले कुछ दिनों तक गरमी का प्रकोप ऐसे ही जारी रहने वाला है। गरमी, धूप और लू से बचने के लिए लोगों को स्वयं भी सचेत रहना होगा। बच्चों, बुजुर्गों का खास ध्यान रखने की जरूरत है। राहत की खबर यही है कि मानसून तीन-चार दिन में केरल में दस्तक देगा।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 29 मई 1949

काश्मीर का भविष्य

भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सभी दृष्टियों से काश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहा है। अतएव १५ अगस्त १९४७ के बाद ही यदि काश्मीर को भारत का अखंडित भाग घोषित कर दिया जाता, तो कोई आश्चर्य तथा अन्याय की बात न होती; किन्तु भारत ने इस रियासत के सम्बन्ध में बहुत संयम तथा उदार भावना से काम लिया है। यह जानते हुए भी कि जम्मू तथा काश्मीर के मुसलमान साम्प्रदायिकता की भावना से कोसों दूर हैं तथा लीग के 'दो राष्ट्र' वाले घातक सिद्धान्त के वे सर्वथा विरुद्ध हैं और शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में उन्होंने स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र के लिए अनवरत संग्राम किया है, भारत ने पाकिस्तान को कोई भी ऐसा अभियोग मढ़ने का अवसर न देना चाहा, जिससे पाकिस्तान यह शोर मचाने लगे कि काश्मीर के बहुसंख्यक मुसलमानों को जोर-जबर्दस्ती से भारत में रहने को बाध्य किया गया है। जब पाकिस्तान ने काश्मीर का दाना-पानी बन्द कर दिया और जनता अन्न-वस्त्र, नमक आदि के लिए तड़पने लगी और यातायात के लिए पेट्रोल के बिना मोटर-लारियां बेकार हो गईं, तो काश्मीर ने बहुत अनुनय-विनय की कि नाकेबन्दी समाप्त कर दी जाये। किन्तु पाकिस्तानी अधिकारियों के कानों में जू भी नहीं रेंगी। उन्होंने तो इस प्रकार की मिन्नत-आरजू के लिए अपने कान तब तक बहरे कर लेने का निश्चय कर लिया था जब तक कि काश्मीर घुटने टेककर पूर्ण रूप से पाकिस्तान के उदर में न समा जाये। इतना ही नहीं, कबायली हमलावरों तथा पाकिस्तानी आक्रान्ताओं ने काश्मीर की भूमि में प्रवेश करना प्रारम्भ कर दिया। काश्मीर की वह वेदना तथा छटपटाहट चेकोस्लोवाकिया तथा मध्य यूरोप के देशों की उस दुर्दशा का स्मरण कराती थीं जब कि नाजियों ने उन पर आक्रमण किया था। भारत इस स्थिति से अवगत था। किन्तु भारत तथा पाकिस्तान के बिगड़े हुए सम्बन्धों को और न बिगड़ने देने के लिए वह अपना कदम रोके रहा।

संकट बढ़ता जा रहा था और काश्मीर के प्राण प्रायः कंठगत हो गये थे। जब हमलावर घाटी में अनवरोध गति से आगे बढ़ते हुए श्रीनगर से कुछ ही दूर रह गये तो काश्मीर के नेता रक्षा की अपील लेकर दिल्ली आये और काश्मीर के महाराजा ने भारत सरकार को कहा कि काश्मीर भारत में सम्मिलित होना चाहता है। नरेश ने न कोई शर्त रखी थी और न यह अस्थायी सम्मिलन था।

अब किसी की नहीं सुन रहा इजरायल

यहां स्कैन करें

अश्विनी महापात्र | प्रोफेसर, जेएनयू

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब फलस्तीन समस्या का स्थायी निपटारा चाहते हैं। उनकी योजना मानो दुनिया के नक्शे से गाजा पट्टी को मिटा डालने की है।

दक्षिणी गाजा पट्टी में राफा पर इजरायली हमले के खास निहितार्थ हैं। बेशक, इस हमले में 40 से अधिक आम फलस्तीनियों की मौत हुई है और दुनिया भर में इसकी निंदा जारी है, लेकिन ऐसा लगता है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोच-समझकर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में ऑपरेशन प्रोटेक्टिव शील्ड (जुलाई, 2014), ऑपरेशन कास्ट लीड (दिसंबर, 2018), ऑपरेशन वॉल गार्जियन (मई, 2021) जैसी फौजी कार्रवाइयों के बावजूद इजरायल को इसलिए सफलता नहीं मिल सकी थी, क्योंकि सैन्य ऑपरेशन के बाद अंतरराष्ट्रीय दबाव में उसे संघर्ष-विराम करना पड़ता था और हालात पूर्ववत हो जाते थे। ऐसे संघर्ष-विराम में दोनों पक्षों द्वारा कैदियों की अदला-बदली की भी बात होती थी, लेकिन करीब एक करोड़ इजरायलियों की सुरक्षा का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाता था।

अब इजरायली प्रधानमंत्री इस परिपाटी को बदलते हुए दिख रहे हैं। इस युद्ध में हमास की मंशा यही लग रही थी कि अक्तूबर, 2023 में हमले के बाद संघर्ष-विराम कर लिया जाएगा और इजरायली बंधकों के बदले फलस्तीनी कैदियों को छुड़ाकर स्थिति सामान्य बना ली जाएगी। मगर नेतन्याहू अब इस समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं। उनकी योजना मानो दुनिया के नक्शे से गाजा पट्टी को मिटा डालने की है, ताकि हमास को सिर छिपाने की कोई जगह न मिले। इससे ही इजरायलियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। इजरायल का यह भी मानना है कि जब उत्तर और मध्य गाजा से फलस्तीनियों को दक्षिणी इलाकों में आने को कहा गया था, तब आम लोगों की भीड़ में कुछ हमास के लड़ाके भी यहां पर आ गए, जो रह-रहकर इजरायली सुरक्षा बलों को चुनौती देते रहे हैं। उसकी यह सोच उन हमलों से पुष्ट होती है, जो बीते दिनों इजरायल पर हुए हैं। माना जाता है कि उत्तर और मध्य गाजा में हमास ने अपना ठिकाना फिर से बना लिया है।

यही कारण है कि इजरायली प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय समुदाय की अवहेलना करते दिख रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वह किसी दबाव में आकर सैन्य कार्रवाई बंद नहीं करेंगे। अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से उनकी नाराजगी की एक वजह फलस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने वाले देशों की बढ़ती संख्या भी है। अब तक संयुक्त राष्ट्र के 195 सदस्य देशों में से 143 राष्ट्र फलस्तीन के पक्ष में हैं, जिनमें नया नाम आयरलैंड, नॉर्वे व स्पेन का है।

इतना ही नहीं, पिछले मार्च महीने में सुरक्षा परिषद् ने गाजा में संघर्ष-विराम और बिना शर्त इजरायली बंधकों की रिहाई संबंधी एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसका अमेरिका ने कोई विरोध नहीं किया, जबकि इससे पहले तक वह इजरायल के पक्ष में खड़ा रहा है। फिर, वाशिंगटन ने इजरायल को भेजी जाने वाली हथियारों की खेप भी टाल दी और राफा पर हमले की सूरत में इसे रद्द करने की चेतावनी दी थी, जिसे इजरायल ने नजरंदाज कर दिया है।

हालांकि, इन सबकी कीमत आम फलस्तीनी चुका रहे हैं। तकरीबन 10 लाख फलस्तीनी विगत अक्तूबर के बाद से पलायन करके दक्षिणी गाजा पट्टी में आ चुके थे, लेकिन ताजा हमले के बाद वे वापस उत्तर व मध्य इलाकों में लौटने लगे हैं। माना जा रहा है कि तीन लाख, 60 हजार फलस्तीनी राफा छोड़कर वापस लौट चुके हैं। जबकि, हालिया हमले में लगभग 1,000 लोगों की मौत के साथ अब तक तकरीबन 40 हजार फलस्तीनी इस युद्ध की भेंट चढ़ चुके हैं। फिर भी, इजरायल इसलिए नहीं पसीज रहा, क्योंकि उसकी नजर में यही आखिरी मौका है, जब वह हमास को जड़ से खत्म कर सकता है। स्पष्ट है, यह एक मानसिक खेल है, जो दोनों पक्षों की ओर से खेला जा रहा है।

ऐसे में, सवाल यही है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय अब क्या कर सकता है? अमेरिका बार-बार इजरायल से यही पूछ रहा है कि आखिर वह चाहता क्या है? वाशिंगटन के मुताबिक, समझौता ही इस जंग का अंतिम रास्ता है। मगर फलस्तीनी प्रशासन भी फिलहाल झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि इससे उसके पक्ष में बन रही सहानुभूति कम हो सकती है। जिस तरह से दुनिया भर के देश उसके पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं, विशेषकर अमेरिकी विश्वविद्यालयों में उसके पक्ष में प्रदर्शन हो रहे हैं, उससे उसमें यह भरोसा बना है कि अंतरराष्ट्रीय समर्थन उसके साथ है।

यह माना जा रहा था कि मिस्र, सऊदी अरब जैसे देश मिलकर इस मसले का हल निकाल लेंगे और हमास पर दबाव डालेंगे, ताकि वह कहीं और चला जाए। मगर इजरायल फलस्तीन जैसे किसी समुदाय का ही पक्षधर नहीं दिख रहा। वह गाजा पट्टी पर अपना अधिकार चाहता है। यही कारण है कि वह दो-राष्ट्र के सिद्धांत की भी मुखालफत करता है, जबकि तमाम शांतिप्रिय राष्ट्र इस सिद्धांत के हिमायती हैं।

कुछ लोग तर्क देते हैं कि इजरायल के भीतर जो फलस्तीन समर्थक आवाजें उठ रही हैं, वे इजरायलियों की अपनी सरकार से नाराजगी का संकेत है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। इजरायल में जहां-कहीं छिटपुट संख्या में फलस्तीन समर्थक हैं, खासतौर से वेस्ट बैंक में, वहीं विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। इसका बहुत ज्यादा अर्थ नहीं है। लिहाजा, सवाल यही है कि आखिर इस युद्ध का अंत कैसे हो? इजरायल फलस्तीन का पूर्ण सफाया चाहता है और उसकी नजर में फलस्तीनियों की मौजूदगी उसकी एक करोड़ आबादी की सुरक्षा को दांव पर लगाना है, पर यह व्यावहारिक समाधान नहीं हो सकता। तो, क्या दो-राष्ट्र का सिद्धांत ही समाधान है? अगर हां, तो यह कैसे संभव होगा? इन्हीं सवालों के जवाब में इजरायल-फलस्तीन समस्या का हल भी छिपा है।

तमाम संभावनाओं को देखें, तो उचित हल यही है कि दो-राष्ट्र के सिद्धांत को मान लिया जाए। तभी अंतरराष्ट्रीय समुदाय का दबाव फलस्तीनियों पर पड़ेगा और शांति-बहाली का प्रयास हो सकेगा। ऐसा करने पर शांति-सेना गाजा में तैनात हो सकेगी। दिक्कत यह है कि इस युद्ध को रोकने के लिए कोई भी कुछ खास करता नहीं दिख रहा। अरब देश चुप हैं। इस्लामी राष्ट्र भी कुछ नहीं कह रहे। ईरान ने इस मामले में काफी हद तक कदम बढ़ाए थे, लेकिन एक हवाई हादसे में अपने राष्ट्रपति की दुखद मौत और घरेलू चुनौतियों के कारण वह भी फिलहाल शांत पड़ता दिख रहा है। बाकी देश स्थिति पर निगाह जरूर बनाए हुए हैं, लेकिन वे निष्क्रिय ही जान पड़ते हैं। नतीजतन, यह युद्ध दिन-ब-दिन वीभत्स होता जा रहा है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

दौलतमंदों का दागदार दामन समाज और शिक्षा पर सवाल

यहां स्कैन करें

मनु जोसेफ | पत्रकार और उपन्यासकार

उस दिन मैं एक पूर्व नन के साथ बस में सफर कर रहा था। उसने हाल ही में कॉन्वेंट को अलविदा कहा था। अब उसे मस्ती करने से कोई नहीं रोक सकता था। उसने गाना और ताली बजाना शुरू कर दिया, वह कोशिश में लग गई कि बाकी लोग भी सुर में सुर मिलाएं। वह बाहर राहगीरों को भी आवाज देने लगी। इसके बावजूद आनंद न मिला, तो वह उलझन में पड़ गई।

वास्तव में, असंख्य भारतीय युवाओं की यही उलझन है। वे मौज-मस्ती की तलाश में निकलते हैं और निराशा हाथ लगती है। अंततः अनेक युवाओं को मौज की तलाश में नशे के आगोश में जाना पड़ता है। लड़खड़ाना पड़ता है, गिरना पड़ता है। वास्तव में यह वही मिजाज है, जो मैं भारत में असाधारण रूप से अमीर युवाओं में देखता हूं। ऐसे युवा मौज-मस्ती के खनिकों जैसे दिखते हैं। आखिरकार, वे बस इतना ही कर सकते हैं कि नशे में धुत होकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाने लगें। कभी वे पैदल चलने वालों को कुचल देते हैं, तो कभी पीछे से टक्कर मार देते हैं, जैसा पुणे में हुआ। नशे में धुत्त 17 वर्षीय लड़के ने पिता की पोर्श कार से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, दो लोगों की मौत हो गई। तब से भारत में बहुत लोग असमंजस में हैं कि उस किशोर के साथ क्या किया जाए? पहले उसे हादसे के 15 घंटे के भीतर जमानत पर रिहा कर दिया गया और बाद में लोगों के गुस्से की वजह से उसे वापस रिमांड पर ले लिया गया। किशोर का पिता विशाल अग्रवाल बिल्डर है, जिसके बारे में ऐसा लगता है कि उसने जानते-समझते हुए भी बेटे को कार दी। बाप ने बचने की बहुत कोशिश की, पर अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसके दादा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यहां कानूनी शब्दजाल से परे देखिए, वह किशोर ही नहीं, उसके खराब अभिभावक भी समाज के लिए खतरा बन जाने की वजह से गिरफ्तार कर लिए गए। वस्तुतः आज भारत के ज्यादातर अमीर परिवार ऐसे ही लोगों से भरे पड़े हैं।

अपने देश में नए अमीर समस्या नहीं हैं, उनका खराब व्यवहार समस्या बनकर खड़ा होने लगा है। पुणे का पोर्श हादसा इसकी ताजा मिसाल है।

हालांकि, भारत में ऐसे असाधारण अमीर हैं, जिनके घरों में बच्चों को अच्छी तरह से सिखाया जाता है कि वे अच्छा व्यवहार करें और लोगों को न कुचलें। हालांकि, साधारण अमीर बहुत अलग किस्म के होते हैं। वे अपने बच्चों को अपनी किस्मत पर इतराना सिखाते हैं और दूसरों के प्रति दया की सीख को जरूरी नहीं मानते हैं।

आप भारत के कुछ अमीरों के साथ बैठकर देखिए, सिर्फ यही सुनेंगे कि पैसे ने क्या खरीदा है और आगे क्या खरीदने वाला है। एक पीढ़ी ऐसे ही संवाद सुनकर बड़ी हुई है और यही मानती है कि अमीरों को अपनी किस्मत का ऐसे ही आनंद लेना चाहिए। वैसे, मेरा अनुमान है, धन से खरीदी जा सकने वाली सबसे अच्छी चीज बुद्धि ही है। बुद्धि की उत्पत्ति धन से होती है और यह अभी भी अमीरों की सर्वोत्तम सेवा करती है। बुद्धि या किसी बौद्धिक खोज के बिना अमीर लोग भौतिक चीजों में मनोरंजन तलाशने लगते हैं, जो दूसरों को सुलभ नहीं हैं। इस मांग के जवाब में, पूंजीवाद ने अति-अमीरों के लिए अनेक नकली उत्पादों का आविष्कार कर रखा है, पर जब उसमें भी मजा नहीं आता है, तब कुछ अमीर अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं और अंततः निराश हो जाते हैं। ऐसे में, उन्हें अधिक से अधिक खरीदना होगा और ध्यान खींचने के लिए जोखिम भरा काम करना होगा, जैसे 200 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी दौड़ाना? अफसोस, हम अपने आस-पास जिन अमीरों को देखते हैं, उनमें से अधिकांश पूंजीवाद के विजेता, पिछली पीढ़ियों से प्राप्त प्रगति के लाभार्थी हैं।

अपने देश में नए अमीर समस्या नहीं हैं, उनका नया व्यवहार समस्या है। ध्यान दीजिए, दुर्घटना के बाद लोगों ने किशोर और पोर्श कार पर हमला बोल दिया। हम मान सकते हैं कि यह पीड़ितों की ओर से गुस्से का इजहार नहीं था, बल्कि यह महंगी पोर्श कार के प्रति गुस्सा था। अक्सर सवाल उठता है, अमीरों को गरीब मार क्यों नहीं देते? शायद, गरीब हिंसक नहीं होना चाहते। जेल नहीं जाना चाहते। और गरीब शायद अमीरों की तुलना में गरीबों के प्रति ज्यादा मतलबी होते हैं। अतः व्यापक समाज और व्यवस्था के हित में गरीबों के साथ ही अमीरों को भी संतुलन साधकर चलना होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

यथार्थ का सामना कीजिए

हमारे संघर्ष और श्रम का यह संसार एक भयानक, खतरनाक, विनाशकारी और हड़पने वाला संसार है, जिसमें जीवन का अस्तित्व संदिग्ध रहता है और मनुष्य की आत्मा और शरीर घोर संकटों में विचरते हैं। यह संसार ऐसा है, जिसमें आगे बढ़ाए गए हरेक कदम से, हम चाहें या न चाहें, कुछ न कुछ कुचल या टूट जाता है। इसमें जीवन की प्रत्येक सांस मृत्यु की सांस भी है।

इस दुनिया में हमें जो कुछ बुरा या भयानक लगता है, उसकी जिम्मेदारी एक अर्द्ध-सर्वशक्तिमान शैतान पर डालना अथवा प्रकृति का एक हिस्सा मानकर अलग रख देना, विश्व प्रकृति और ईश्वर प्रकृति के बीच असंयोजनीय विरोध बनाकर, मानो प्रकृति ईश्वर से स्वतंत्र हो अथवा मनुष्य और उसके पापों पर पूरी जिम्मेदारी लाद देना, मानो इस संसार को बनाने में उसकी प्रधान आवाज हो या वह ईश्वर की इच्छा के विपरीत कुछ भी सृजित कर सकता है, यह सब भद्देपन से भरी सुखकर युक्तियां हैं, जिनमें भारत के धार्मिक विचार ने कभी आश्रय नहीं लिया है। हमें यथार्थ का साहस के साथ सामना करना होगा और समझना होगा कि इस संसार को और किसी ने नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर ने अपनी इच्छा से बनाया है और जैसा यह है, वैसा ही बनाया है। हमें समझना होगा कि अपने ही बच्चों को निगलने वाली प्रकृति, प्राणियों के जीवन-भक्षण करने वाला काल, सार्वभौम व अपरिहार्य मृत्यु तथा मनुष्य व प्रकृति की रौद्र शक्तियों की हिंसा अपने किसी सृष्टयात्मक स्वरूप में परमब्रह्म परमात्मा ही है।...

इस दुनिया में कोई वास्तविक शांति तब तक नहीं आ सकती, जब तक कि मनुष्य का हृदय शांति का पात्र नहीं बनता; विष्णु का विधान तब तक नहीं चल सकता, जब तक कि रुद्र का ऋण चुकाया नहीं जाता। तब फिर किनारे मुड़कर अभी भी अविकसित मानव जाति को प्रेम और एकता के विधान का उपदेश देना कैसा? प्रेम और एकता के विधान का शिक्षक होना ही चाहिए, क्योंकि अंतिम उद्धार तो उसी रास्ते से मिलना है। पर तब तक बाह्य और तात्कालिक यथार्थ पर, आंतरिक और चरम, विजय नहीं पा सकता, जब तक कि मनुष्य में कालात्मा तैयार नहीं होती। महात्मा बुद्ध और ईसा मसीह आए और चले गए, पर वह रुद्र हैं, जो संसार को अपनी मुट्ठी में पकड़े हुए हैं। और मानव जाति का प्रचंड अग्रगामी श्रम, उन शक्तियों द्वारा सताए और कुचले जाने पर, जो अहंकारी बल के मुनाफाखोर और उन्हीं के नौकर हैं, संघर्ष के नायक की तलवार की पुकार कर रहा है।

इस दुनिया में वास्तविक शांति तब तक नहीं आ सकती, जब तक कि मनुष्य का हृदय शांति का पात्र नहीं बनता; विष्णु का विधान तब तक नहीं चल सकता, जब तक रुद्र का ऋण चुकाया नहीं जाता।

यह विश्व वास्तव में प्रकृति की अंध-शक्तियों द्वारा सृजित नहीं है, अचेतन में भी परम सत्य की उपस्थिति क्रियाशील रहती है, उसके पीछे एक द्रष्टा शक्ति होती है, जो अचूक रूप से कार्य करती है।

श्री अरविंद

इमैनुएल मैक्रों | फ्रांसीसी राष्ट्रपति

राफा में इजरायली हमलों में कई विस्थापित मारे गए हैं। फलस्तीनी नागरिकों के लिए वहां कोई सुरक्षित क्षेत्र नहीं बचा, इसलिए ऑपरेशन फौरन बंद होने चाहिए। अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान और तत्काल युद्ध-विराम होना चाहिए।

अनुलोम-विलोम

पहाड़ पर भीड़

अब पहाड़ स्मृतियों वाले नहीं रहे

केदारनाथ के रास्ते में हैलीपैड की संख्या बढ़ती जा रही है। शोर इतना है कि आवाज देने पर वह गुम हो जाए। न गूंजेगी और न वापस ही आएगी। खनन के लिए जगह-जगह जेसीबी काम पर लगी हैं। अनेक सुरंगों, पुलों, चौड़े रास्तों के निर्माण के लिए इतनी ऊंचाई पर भारी मशीनों को देखकर कभी-कभी तो दिल बैठ सा जाता है। यहां की कई स्थानीय नदियों में पानी उतना ही बचा है, जितना शहरों की आंखों में आंसू। कभी उन नदियों में आकार पाए गोल पत्थर आधे सूखे, आधे गीले और कहीं-कहीं अकेले पड़े हैं। उन तक पहुंचने के रास्ते जीप, एसयूवी व अन्य गाड़ियों ने तलाश लिए हैं। लोग बड़े पत्थरों पर बैठकर पत्थरों के नीचे बहने वाली जलधारा को अंजुली में भरकर खुश हैं। मैगी प्वॉइंट्स पर गाड़ी मुहाने तक खड़ी करने की होड़ भी बढ़ रही है। रील देखकर कार पार्क करना लोगों के लिए नया एडवेंचर है। यही उनका मनोरंजन भी। यहां ठंडक अब पहले की तरह नहीं रही। अब गाड़ी का शीशा खोलने पर हवा गरम आती है। तापमान साल-दर-साल बढ़ रहा है। दिल्ली से बैग में आई जैकेट बैग में ही है और शायद बैग में ही वापस चली जाएगी। लोग दिल्ली की ही तरह हाफ टी-शर्ट और शर्ट में घूम रहे हैं। सच कहूं, उत्तराखंड के पहाड़ अब वैसे नहीं रहे, जैसे मेरी स्मृतियों में रहते आए हैं।

अंजुम शर्मा, टिप्पणीकार

गरमी की छुट्टी बड़ी वजह

धार्मिक, पर्यटन स्थलों और पहाड़ों पर इतनी ज्यादा भीड़ होने की सबसे बड़ी वजह है, बच्चों और अभिभावकों पर स्कूलों का दबाव। अभी गरमियों की छुट्टियां चल रही हैं, अतः अभिभावक अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए फटाफट ऐसी जगहों पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जब स्कूल शुरू हो जाएंगे, तब बच्चों को अवकाश नहीं मिल पाएगा, पढ़ाई का इतना दबाव उन पर और उनके पालकों पर होता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग गरमियों की छुट्टियों को छोड़कर साल भर कहीं घूमने नहीं जाते। पहाड़ों पर अंधाधुंध बढ़ती भीड़ से बचने का एक व्यावहारिक उपाय यह हो सकता है कि बच्चों के अवकाश के समय में कुछ बदलाव किए जाएं। गरमियों की छुट्टियों में बेशक कुछ कटौती कर ली जाए, लेकिन बीच-बीच में हफ्ते-दस दिन का अवकाश मिले, ताकि वे कहीं घूमकर आ सकें। इससे बच्चे भी सुकून महसूस कर सकेंगे और देश के पर्यटन स्थल भी सांस ले सकेंगे। हमारे स्कूलों को इस दिशा में सोचना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में यह बदलाव दूरगामी असर डाल सकता है।

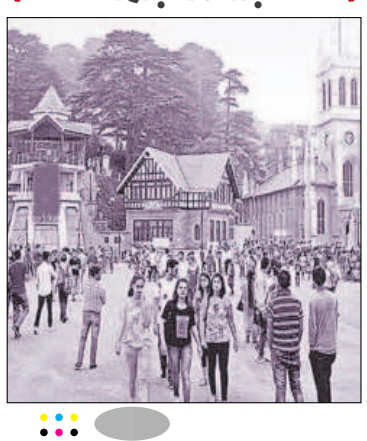

अवतार कुशवाहा, टिप्पणीकार

कारोबार होगा तो लोग जाएंगे ही

कुछ दिनों पहले केदारनाथ में ढोल बजाकर रील बनाने वाले कुछ लोगों को एक नौजवान ने रोका, जिसके बाद रील बनाने वालों को रोकने के लिए 50 मीटर का दायरा तय किया गया। मेरे एक मित्र हैं, जो कैंची धाम में लगातार बढ़ती भीड़ से चिंतित हैं। प्रश्न यह है कि पहाड़ों पर लागों के पहुंचने से चिंता क्यों हो रही है? क्या यह चिंता इसलिए है कि रील बनाने वाले जहां-तहां अमर्यादित आचरण करते हैं? अगर यह चिंता है, तो मंदिर के आसपास मर्यादित आचरण संबंधी कायदे लागू किए जा सकते हैं, मंदिर परिसर से 100 मीटर पहले मोबाइल रखवाया जा सकता है। अगर रील बनाना चिंता नहीं है और पर्यावरण के लिए कलेजा फट रहा है, तो दोहरी नीति नहीं चलेगी। अगर केदारनाथ क्षेत्र के संवेदनशील पर्यावरण को ढोल-करताल से दिक्कत है, तो हेलिकॉप्टर की आवाज से भी होनी चाहिए। मंदिर परिसर के आसपास जो दुकानें सजाई गई हैं, उनसे भी होनी चाहिए। मगर नहीं, यह तो आपके फायदे का सौदा है, इसलिए इनको कोई क्यों मना करेगा?

केदारनाथ के आसपास पक्का-निर्माण नहीं होना चाहिए था, पर आपने होने दिया। पहाड़ काटकर सड़कें नहीं बनाई जानी थीं, आपने बनने दिया। तो, अब पर्यावरण का रोना मत रोइए। अगर पर्यावरण की चिंता है, तो बताइए, गंगोत्री के ठीक नीचे से लेकर उत्तरकाशी तक (और आगे भी) भागीरथी के पेटे (बेसिन) में बने होटलों, मकानों के खिलाफ आपने क्या किया? उत्तराखंड को पर्यटन का हब बनाएंगे, तो लोग आएंगे ही। उत्तराखंड पर्यटन का प्रचार भी करेंगे और दूसरी तरफ ठोस कायदे-कानून भी नहीं बनाएंगे। चारधाम यात्रा से लेकर कैंची धाम तक, लाखों लोग पहुंच रहे हैं। सड़कें जाम हो रही हैं, तो इसका दोषी पर्यटक नहीं, आपकी व्यवस्था है। उत्तराखंड में सड़क का हर कोना होटल और ढाबे में बदल चुका है। आप माल काटेंगे, तो जाम कौन सहेगा? जब जाम लगता है, तो पानी की बोतल आप के ही लोग 50 रुपये की बेचते हैं।

पर्यटकों में से दस अगर तीर्थ के लिए पहुंचेंगे, तो 90 लोग पिकनिक समझकर जाएंगे। सरकार को माइक्रो स्तर पर इसकी योजना बनानी होगी। जैसे, कैंची धाम में मंदिर से सटाकर पार्किंग बना दी गई है। मंदिर के मुख्य द्वार के पास ही शिकंजी बेचने की बड़ी दुकानें हैं और लोगों से अधिक अफरातफरी दुकानदार मचाते हैं। क्या गाड़ियों की पार्किंग एक किलोमीटर दूर नहीं बनाई जा सकती थी, जहां से यात्रियों को पैदल या बैटरी रिक्शे से मंदिर परिसर तक पहुंचाया जाता? मगर नहीं, सारा ध्यान पैसा कूटने पर है। यदि आप पैसा कूटोगे, तो पब्लिक रील बनाएगी ही।

मंजीत ठाकुर, पत्रकार

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 29 मई, 2024

दैनिक जागरण

समृद्धि के लिए शांति का होना अनिवार्य है

अंतहीन सुनवाई

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मथुरा के श्रीकृष्ण जन्म स्थान एवं शाही ईदगाह मस्जिद मामले की सुनवाई के समय मंदिर पक्ष ने यह आरोप लगाया कि मस्जिद पक्ष पुरानी बातें दोहराकर बहस को लंबा खींच रहा है। पता नहीं इस आरोप में कितना सच है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुछ समय पहले उच्च न्यायालय की ओर से भी यह कहा जा चुका है कि मस्जिद पक्ष के वकील पहले कही गई बातें फिर से न दोहराएं। अब अगली सुनवाई इस माह के अंत में होगी। कहना कठिन है कि यह सुनवाई कितनी लंबी चलेगी? जो कहा जा सकता है, वह यह कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट पक्ष सर्वोच्च न्यायालय जाएगा और वहां भी इस मामले की लंबी सुनवाई चल सकती है।

यह तो अच्छा हुआ कि इस विवाद से जुड़े कई मामलों की जो सुनवाई मथुरा की स्थानीय अदालतों में हो रही थी, उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने यहां मंगवा लिया, ताकि सदियों पुराने इस प्रकरण का निस्तारण यथाशीघ्र किया जा सके, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिखता, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण पर रोक लगा रखी है। वैसे जब काशी के ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण हो चुका है, तब फिर न्याय और नीति यही कहती है कि मथुरा की ईदगाह मस्जिद का भी सर्वेक्षण हो, जिसके बारे में यह मान्यता है कि उसका निर्माण श्रीकृष्ण जन्म स्थान मंदिर पर किया गया। इसके वैसे ही दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हैं, जैसे ज्ञानवापी परिसर के हैं। काशी और मथुरा जैसे विवाद और भी हैं। इनमें से कुछ अदालतों में भी हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के धार जिले का भोजशाला परिसर। हिंदू पक्ष का यह मानना है कि यह देवी सरस्वती का मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह कमाल मौला के नाम से बनी मस्जिद है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक निर्णय के चलते पिछले दो माह से अधिक समय से भोजशाला परिसर का सर्वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से हो रहा है। इस तरह के कुछ और मामले भी उभर आए हैं। प्रश्न यह है कि आखिर ऐसे मामलों का निस्तारण कब और कैसे होगा? क्या यह उचित नहीं होगा कि इस तरह के जो भी प्रमुख मामले हैं, उनका निपटारा एक निश्चित समयसीमा में किया जाए। यह तभी संभव है, जब दोनों पक्षों के साथ-साथ न्यायपालिका भी इसके लिए तत्परता दिखाएगी। इसका कोई औचित्य नहीं कि इस तरह के मामलों की सुनवाई वर्षों तक होती रहे। उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई व्यवस्था करे, जिससे मंदिर-मस्जिद से जुड़े विवादों का पटाक्षेप हो और देश आगे बढ़े। यह भी समय की मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय पूजा स्थल अधिनियम की वैधानिकता की परख करे। इससे काशी, मथुरा के साथ इस जैसे अन्य विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी।

बीमारी वक्त नहीं देखती

कोरोना के दौरान आयुर्वेद के महत्व को सिर्फ देश ही नहीं विदेश ने भी समझा। इसके बावजूद भी आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति नहीं दिख रही है। बिहार के इकलौते राजकीय आयुर्वेदिक कालेज सह अस्पताल को देखकर तो ऐसा ही लगता है। यहां ओपीडी में हर रोज औसत पांच सौ मरीज पहुंचते हैं। ये वैसे मरीज हैं, जो उपचार की विभिन्न पद्धतियों के थक हारकर या सस्ते और कारगर चिकित्सा के ख्याल से यहां आते हैं। कोरोना के पहले की स्थिति पर गौर करें ओपीडी में इतनी संख्या में मरीज नहीं आते थे। जाहिर है, लोगों का भरोसा इस चिकित्सा पद्धति पर बढ़ा है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि अस्पताल के संसाधनों को लोगों की जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जाए। फिलहाल यहां दवा की कमी से मरीज जूझ रहे। महज 32 तरह की दवाएं ही वितरित की जा रही हैं। शेष दवा मरीजों को बाहर से खरीदनी पड़ रही है। यह उनकी जेब पर भारी पड़ रहा है। दवा की कमी के सवाल पर अधिकारी कहते हैं कि लोकसभा चुनाव की वजह से दवा खरीद की प्रक्रिया रुक गई है। इसका मतलब तो यही हुआ कि चुनाव के पूर्व इसकी तैयारी नहीं की गई थी। बीमारी न तो वक्त के दायरे में बंधी है और न ही दवा के लिए अनुकूल समय का इंतजार किया जा सकता है। यह पूरी तरह प्रबंधन की चूक कही जा सकती है। एक वक्त ऐसा भी था, जब मरीजों की न्यून संख्या की वजह से कालेज की मान्यता पर संकट के बादल घिरे रहते थे। अब 185 मरीज यहां भर्ती होकर उपचार कराते हैं। निश्चित रूप से लोगों का रुझान इस चिकित्सा पद्धति की ओर बढ़ा है। इस अवसर को हर तरह से सहेजने की जरूरत है।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज सह अस्पताल के ओपीडी में हर रोज औसत पांच सौ मरीज पहुंचते हैं। दवा की कमी यहां बड़ी समस्या बनी हुई है

ओबीसी आरक्षण से खिलवाड़

अवधेश कुमार

पिछड़े वर्ग का हक छीनकर मुस्लिम जातियों को आरक्षण देने का चलन बंगाल के साथ-साथ राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना में भी है

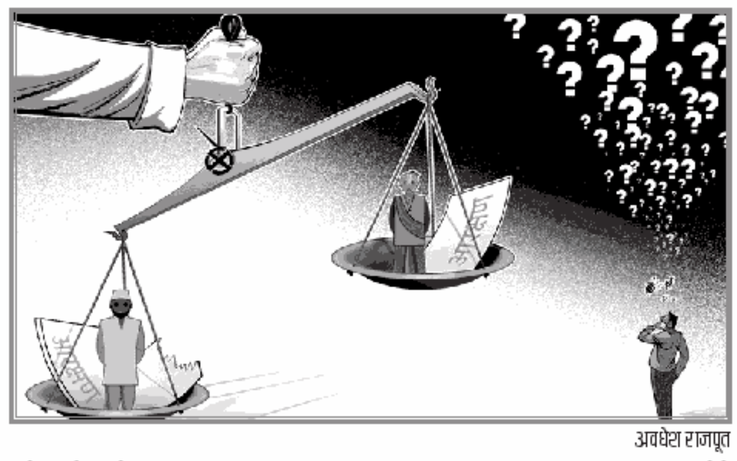

अवधेश राजपूत

लोकसभा चुनाव में पंथ या मजहब के आधार पर आरक्षण के मुद्दे को सांप्रदायिक करार देने वालों के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला एक आघात बनकर आया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रकट नाराजगी बताती है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम पर मुस्लिम समुदाय को ज्यादा से ज्यादा आरक्षण देने के असंवैधानिक, अनैतिक और समाज विरोधी फैसले पर वह केवल वोट के लिए यानी राजनीतिक कारणों से अड़ी रहना चाहती हैं। वह यहां तक बोल गईं कि जज को निर्देश देकर फैसला कराया गया है। बंगाल की सत्ता में आने के बाद ममता सरकार ने पांच लाख से ज्यादा ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए। उनमें से अधिकांश मुस्लिम समुदाय के लोगों को मिले। उच्च न्यायालय के अनुसार इन जातियों को ओबीसी घोषित करने के लिए वास्तव में रिलीजन ही एकमात्र मानदंड प्रतीत होता है और हमारा मानना है कि मुसलमानों की 77 श्रेणियों को पिछड़ों के रूप में चुना जाना पूरे मुस्लिम समुदाय का अपमान है। 77 श्रेणियों को ओबीसी में शामिल करने से स्पष्ट होता है कि इसे वोट बैंक के रूप में देखा गया है। न्यायालय की ये टिप्पणियां असाधारण हैं, लेकिन ये केवल तृणमूल और ममता बनर्जी ही नहीं, बल्कि देश के उन सभी राजनीतिक दलों, सरकारों और नेताओं के वास्तविक चेहरे को उजागर करतीं हैं, जो अन्य पिछड़ों के नाम पर केवल वोट के लिए मुसलमानों को असंवैधानिक रूप से आरक्षण का लाभ देने के लिए इसी तरह के कदम उठा रहे या उठाने की तैयारी में हैं।

वास्तव में, भारत के हर नागरिक को अवसर की समानता उपलब्ध कराने के लिए संवैधानिक तरीकों से व्यवस्था होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर समूहों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिया, जिसमें मजहब का बंधन नहीं है। उसमें हिंदुओं के साथ मुसलमान भी शामिल हैं। विरोध केवल पिछड़े, दलित और जनजातियों का हक मारकर असंवैधानिक तरीके से वोट बैंक के लिए मुसलमानों को आरक्षण देने का है। बंगाल में वाम मोर्चा सरकार ने 2010 में एक अंतरिम रिपोर्ट तैयार कराकर अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची बनाई और उसे ओबीसी-ए नाम दिया। सरकार ने बैकवर्ड मुस्लिम शब्द का प्रयोग करते हुए उनके लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की। इनमें ऐसे 42 समूह बनाए गए, जिनमें 41 केवल मुस्लिम समुदाय के थे। 2011 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में जब तृणमूल सत्ता में आई तो उसने कोई अंतिम रिपोर्ट प्राप्त किए बिना ही 11 मई, 2012 को 35 ऐसे वर्गों या श्रेणियों को शामिल किया, जो मुस्लिम थे। इनमें नौ ओबीसी-ए एवं 26 ओबीसी-बी में शामिल किए। इस तरह कुल 77 वर्ग या श्रेणियां हो गईं। बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग और सरकार ने इसके लिए द्रुत गति से काम किया। नियमानुसार न कोई अधिसूचना जारी हुई, न छानबीन की गई और न किसी तरह का आवेदन मांगा गया और न इस सामान्य नियम का पालन किया गया कि जिन्हें इस पर आपत्ति हो, वे उसे दर्ज करें। न्यायालय ने लिखा है कि ममता सरकार ने फैसला लेते समय ऐसा कोई आंकड़ा नहीं दिया, जिससे स्पष्ट हो सके कि बंगाल सरकार की सेवाओं में इस समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। अनारक्षित पूरे समुदाय को शामिल करने के लिए इस तरह की अपर्याप्तता का प्रमाण आवश्यक है। साफ है कि वोट के लिए मुसलमानों को आरक्षण देने के मामले में किसी तरह के नियम कानून के पालन की आवश्यकता ममता सरकार ने समझी ही नहीं।

इस फैसले से साबित हो गया है कि भाजपा तथा अन्य हिंदू संगठनों द्वारा ममता बनर्जी पर वोट के लिए पिछड़ों का हक मारकर मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने के असंवैधानिक तरीके उपयोग करने का आरोप सही था। वोट के लिए आपको एक समुदाय को खुश करना है तो वहां नियम, कानून, संविधान तथा आरक्षण की वास्तविक अवधारणा या सिद्धांत आड़े नहीं आते। यह जानकर आश्चर्य होगा कि बंगाल में 179 जातियां अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं। इनमें 118 मुस्लिम हैं। यानी हिंदू पिछड़ी जातियों की संख्या केवल 61 है। जरा सोचिए कि जिस राज्य में करीब 70 प्रतिशत आबादी हिंदू हो, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में उसकी भागीदारी 33 प्रतिशत के आसपास कैसे हो सकती है? क्या यह हिंदू समाज के पिछड़े वर्ग के साथ धोखा और अन्याय नहीं है? इसे मुस्लिम तुष्टीकरण का शर्मनाक नमूना न कहें तो क्या कहें? भारत का संविधान किसी भी तरह रिलीजन, पंथ या मजहब को आरक्षण का आधार नहीं मानता।

वर्ष 2018 में मोदी सरकार ने जब पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया तो राज्यों को राज्य स्तर पर पिछड़ा वर्ग की सूची में जातियों को शामिल करने की स्वतंत्रता मिली। कई राज्यों ने बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय को इनमें शामिल कर दिया। बंगाल में 71 जातियों को ममता सरकार ने पिछड़ा वर्ग में शामिल किया, जिनमें 65 मुस्लिम समुदाय से संबंधित हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बंगाल सरकार से इस संदर्भ में औपचारिक पत्र लिखकर पूछताछ की। इसका यथेष्ट उत्तर आयोग को नहीं मिला। आयोग ने यह भी पूछा था कि आखिर मुसलमानों के अंदर जो पिछड़ी जातियां शामिल हैं, वे जातियां हिंदुओं में कहां चली गईं? बताया यह गया कि इनमें से अधिकांश ने मतांतरण कर लिया है। उल्लेखनीय है कि बंगाल में 1971 के बाद मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़नी शुरू हुई जो आगे रुकनी चाहिए थी। इसमें गिरावट नहीं आई। तब क्या मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के कारण हिंदू जातियां वाकई मतांतरित होकर मुसलमान बन गईं? यदि यह सच है तो इससे भयावह स्थिति कुछ नहीं हो सकती। वोट बैंक के लिए पार्टियां तुष्टीकरण में किस सीमा तक जा सकती हैं, इसका इससे सटीक उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता। यह स्थिति केवल बंगाल तक नहीं है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने पाया कि राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण का बड़ा हिस्सा मुस्लिम समुदायों के पास जा रहा है। यह स्थिति कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना सहित कई राज्यों में है। इसके लिए अलग-अलग तरीके अपनाए गए हैं। कहीं-कहीं तो क्रीमी लेयर के नियम ऐसे बना दिए गए, जिनमें हिंदू पिछड़ी जातियां आरक्षण की अर्हता से बाहर चली जाएं और मुस्लिम जातियां उसके दायरे में आ जाएं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

विकसित देश के सपने को तोड़ते हादसे

राजीव सचान

अपने देश में हर तरह के नियम-कानून हैं, पर उनके उल्लंघन की जैसी सुविधा यहां है, वैसी शायद ही अन्य कहीं हो

आग से तबाह हुआ राजकोट का गेमिंग जोन। प्रेट्र

बीते सप्ताह गुजरात के राजकोट शहर में एक गेमिंग जोन में 35 लोग जलकर मर गए। इस भयावह घटना के कुछ दिन बाद दिल्ली के एक बेबी केयर सेंटर में सात बच्चे आग लगने के कारण काल के गाल में समा गए। इन दोनों घटनाओं में साझा केवल यही नहीं कि घटना का कारण आग लगना रहा। इसके अलावा भी बहुत कुछ साझा है, जैसे यह कि राजकोट के गेमिंग जोन ने अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल नहीं किया था। यही बात दिल्ली के बेबी केयर सेंटर के बारे में भी सामने आई। इसने भी न तो आग से बचाव के उपाय कर रखे थे और न ही अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले रखा रखा था। गेमिंग जोन के मामले में यह भी सामने आया कि राजकोट नगर निगम ने उसके संचालन के लिए न तो कोई लाइसेंस दे रखा था और ही संचालकों ने अन्य किसी नियामक संस्था से कोई अनुमोदन प्राप्त किया था। यही कहानी दिल्ली के बेबी केयर सेंटर की भी है। उसके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद वह अवैध रूप से चल रहा था। स्पष्ट है कि कोई भी यह देखने-जांचने वाला नहीं था कि उसके इलाके में कोई अवैध काम तो नहीं हो रहा है।

गेमिंग जोन या बेबी केयर सेंटर चलाना कोई ऐसा काम नहीं, जिसे गुपचुप रूप से किया जा सके। बेबी केयर सेंटर में पांच बच्चों की देखभाल की सुविधा थी, लेकिन उसमें 12 नवजात भर्ती थे। चूंकि किसी को परवाह नहीं थी, इसलिए इस सेंटर में न तो अग्निशमन यंत्र था और न ही कोई आपातकालीन निकास। इससे भी गंभीर बात यह थी कि यहां आक्सीजन के सिलेंडर रखे हुए थे। इसका मतलब है कि हादसे को निमंत्रण देने की तैयारी थी। ऐसी ही तैयारी राजकोट के गेमिंग जोन में भी दिखी। वहां लोगों का प्रवेश हो रहा था और वेल्डिंग का काम भी चल रहा था। चूंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं इसलिए राजकोट की घटना पर भी नेताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की और दिल्ली की घटना पर भी। दोनों जगह शासन-प्रशासन ने थोड़ी सख्ती का परिचय तो दिया, लेकिन इसके नतीजे में ऐसा कुछ विशेष नहीं हुआ, जो नजीर बन सके। राजकोट में गेमिंग जोन चलाने वाले संचालकों को गिरफ्तार कर लिया गया तो दिल्ली में बेबी केयर सेंटर चलने वाले डाक्टर को। प्रश्न है कि दोनों ही जगह अग्निशमन विभाग और नगर निकाय के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जैसे गुजरात सरकार से कोई यह नहीं पूछ रहा कि नगर निगम और अग्निशमन विभाग के किसी अधिकारी-कर्मचारी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, वैसे ही दिल्ली सरकार से कोई यह सवाल नहीं कर रहा कि अग्निशमन विभाग, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी-कर्मचारी की गिरफ्तारी की जरूरत क्यों नहीं समझी गई? कायदे से तो दोनों शहरों के संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलना चाहिए।

राजकोट और दिल्ली के मामले इकलौते ऐसे प्रकरण नहीं, जिनमें सरकारी तंत्र को जवाबदेही से दूर रखने की कोशिश की गई हो। इस तरह के मामले रह-रहकर होते ही रहते हैं और उनमें बड़ी संख्या में लोग जान गंवाते हैं अथवा घायल होते हैं, लेकिन नियामक तंत्र के उन लोगों को कभी भी कठघरे में नहीं खड़ा किया जाता, जिनकी अनदेखी और लापरवाही के चलते जानलेवा घटनाएं होती रहती हैं। इसका उदाहरण है मुंबई में एक विशालकाय होर्डिंग गिरने से कई लोगों की मौत। यह विशालकाय होर्डिंग अवैध रूप से लगा था, लेकिन किसी को 'नजर' नहीं आ रहा था। जब यह गिर गया और उसमें कई लोगों की जान चली गई तो सरकारी तंत्र ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया। होर्डिंग लगवाने वाला तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन नगर निकाय के किसी अधिकारी-कर्मचारी को गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं समझी गई। कोई नहीं जानता कि क्यों?

भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सरकारी तंत्र की लापरवाही से रह-रहकर हादसे होते रहें और उनमें बड़ी संख्या में लोग मरते रहें। दुर्भाग्य से अपने देश में यही हो रहा है। जब कोई बड़ी घटना घट जाती है और उसमें अधिक संख्या में लोग मारे जाते हैं तो शोक संवेदनाओं का तांता लग जाता है और फौरी कार्रवाई करने के साथ उच्चस्तरीय जांच के आदेश दे दिए जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हीं कारणों से वैसी ही घटना फिर सामने आती है, जैसी पहले हो चुकी होती है। यही कारण है कि न तो हादसे कम हो रहे हैं और न ही उनमें जान गंवाने वालों की संख्या में कमी आ रही है। हादसे दुनिया में हर कहीं होते हैं, लेकिन विकसित और विकासशील देश कम से कम उनसे सबक लेते हैं और ऐसी व्यवस्था करते हैं, जिससे बार-बार एक जैसे कारणों से हादसे न हों। भारत में कोई सबक सीखने से इन्कार किया जा रहा है और यही कारण है कि विकसित देश बनने के संकल्प को साकार करना कहीं अधिक कठिन दिख रहा है। अपने देश में हर तरह के नियम-कानून हैं, लेकिन उनके उल्लंघन की जैसी सुविधा यहां है, वैसी शायद ही किसी विकासशील और विकसित राष्ट्र का स्वप्न देखने वाले देश में हो। भारत में लोग किस कदर कदम-कदम पर नियम-कानूनों का ठसक के साथ उल्लंघन करते हैं और सरकारी तंत्र में बैठे लोग उनकी मदद करने या फिर उनके अपराध को ढकने के लिए तैयार रहते हैं, इसका शर्मनाक उदाहरण पुणे का कार हादसा भी है।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मन की रिक्तता

जीवन किसी के व्यक्तिगत नियम से नहीं चलता और अपने प्राकृतिक नियम से संचालित होता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम जिस वस्तु या उपलब्धि को बहुत तीव्र इच्छा के साथ चाहते हैं और वह हमें नहीं मिलती तो फिर हम बलपूर्वक उसे पाने की चेष्टा करने लगते हैं। यह मनुष्य की बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि इस प्रयास में हम अपने बहुमूल्य समय के साथ-साथ अपनी ऊर्जा भी व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। इस तरह व्यक्ति अपने मन को ढेर सारी नकारात्मकता से भर लेता है। इस बात को लेकर हमारी समझ जितनी स्पष्ट होगी, हमारा जीवन उतना ही बेहतर होगा कि प्रकृति के प्रत्येक पहलू पर हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता है। कभी-कभी प्रकृति यह चाहती है कि हमारे जीवन और मन में कुछ रिक्तता बनी रहे ताकि वह उपयुक्त समय आने पर उस रिक्तता में कोई उचित-उपयुक्त रचना कर उसे भरा जा सके। याद रहे कि किसी खाली कैनवास पर ही एक सुंदर चित्र की निर्मिति संभव है।

खाली दिमाग या मन शैतान का घर होता है, लेकिन यह तब होता है जब हम उस खालीपन को संभालना न जानते हों। उद्विग्न मन या बहुत सारी नकारात्मकता से भरे मन के साथ हम अपनी प्रगति में स्वयं ही बाधा बन जाते हैं। हमें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम अनंत की चाह में उलझ जाते हैं और फिर मन को शून्य करना भूल जाते हैं। जबकि अनंत का मार्ग भी शून्य से होकर ही गुजरता है। आध्यात्मिक मार्ग भी स्वयं को खाली करने पर ही जोर देता है ताकि ईश्वर की अनंत ऊर्जा से उस खालीपन को भरा जा सके। मन के खालीपन के संबंध में चाणक्य ने कहा था कि विवेकशील व्यक्ति अपने मन को खाली रखता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को व्यर्थ की चीजों से खाली रखता है ताकि उसमें ज्ञान और सच्चाई का निवास हो सके।

लवली आनंद

एवरेस्ट के प्रथम आरोहण की गाथा

सुधीर कुमार

29 मई, 1953 की सुबह साढ़े ग्यारह बजे न्यूजीलैंड के मधुमक्खी पालक एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेनजिंग नोर्गे ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। मानव सभ्यता के इतिहास में यह पहला अवसर था, जब 8848.86 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट को सफलतापूर्वक फतह किया गया था। इस ऐतिहासिक अभियान ने पर्वतारोहण की दुनिया में एक नई प्रेरणा का संचार किया। हिलेरी और तेनजिंग की इस महान उपलब्धि ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई और पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनके योगदान को अमर कर दिया। हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर वे लगभग 15 मिनट तक रुके थे। इस दौरान तेनजिंग ने ब्रिटेन, नेपाल, संयुक्त राष्ट्र और भारत के झंडे लहराए और इन ऐतिहासिक पलों को हिलेरी ने कैमरे में कैद किया था। उनकी इस सफलता ने पर्वतारोहियों के लिए असंभव प्रतीत होने वाले लक्ष्य को संभव कर दिखाया।

पर्वतारोहियों में पर्यावरणीय मूल्यों की कमी के कारण आज माउंट एवरेस्ट कचरे के पहाड़ में तब्दील होता जा रहा है

माउंट एवरेस्ट की उस प्रथम सफल चढ़ाई ने नेपाल के साथ-साथ दोनों सफल पर्वतारोहियों की तकदीर भी बदल गई थी। एक तरफ जहां एवरेस्ट की पहली चढ़ाई ने दुनियाभर में पर्वतारोहण में रुचि बढ़ाई और नेपाल उसका हब बन गया, वहीं इससे दोनों पर्वतारोहियों की जिंदगी भी बदल गई। इससे न सिर्फ दोनों की ख्याति दुनियाभर में फैली, बल्कि उन्हें कई उपलब्धियों से भी नवाजा गया। मधुमक्खी पालन कर साधारण जीवन व्यतीत करने वाले एडमंड हिलेरी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पर्वतारोहण का उनका शौक एक दिन लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा देगी। एवरेस्ट फतह के बाद ब्रिटिश सरकार ने एडमंड हिलेरी को नाइटहुड (सर) की उपाधि दी। वे भारत में न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त भी रहे थे। वहीं तेनजिंग नोर्गे के सम्मान में देश में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का जो सिलसिला आज से सात दशक पहले शुरू हुआ था, वह आज भी अनवरत जारी है। पर्वतारोहण आज नेपाल में पर्यटन उद्योग का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। हालांकि पर्वतारोहियों की भीड़ के कारण एवरेस्ट पर कार्बन पदचिह्न भी व्यापक हो रहे हैं। परमिटों की संख्या सीमित करने के लिए नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय की ओर से भी आदेश दिए जाते रहे हैं। दूसरी तरफ पर्वतारोहियों में 'सिविक सेंस' और पर्यावरणीय मूल्यों की कमी के कारण आज माउंट एवरेस्ट कचरे के पहाड़ में तब्दील होता जा रहा है। इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस ऐतिहासिक पर्वत चोटी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और यह सशक्त पर्यटन केंद्र के रूप में अपनी लोकप्रियता यथावत बरकरार रख सके।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

मेलबाक्स

अहम सुधारों का हो सूत्रपात

'तीसरे कार्यकाल की प्राथमिकताएं' शीर्षक से प्रकाशित अपने आलेख में संदीप घोष ने उन प्राथमिकताओं को चिह्नित किया है, जो प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में उनके एजेंडे में रहनी चाहिए। यह सही है कि अभी एक चरण का चुनाव और मतगणना के नतीजे आना शेष हैं, लेकिन व्यापक तौर पर यही अनुमान लगाया जा रहा है कि मोदी सहजता के साथ बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर सकते हैं। लेखक महोदय का यह कहना भी उचित है कि मोदी के पक्ष में जो जनादेश उभरता दिख रहा है वह देश को विकसित बनाए जाने की भावना के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में मोदी को इस कार्यकाल में कुछ कड़े सुधारों को लागू करना होगा। इन सुधारों को आकार देने में सभी अंशभागियों की चिंताओं का उचित निराकरण कर आगे बढ़ा जाए। देश में पिछले कुछ समय से सुधारों की बयार चली है, लेकिन अभी भी भूमि और श्रम जैसे महत्वपूर्ण सुधारों को मूर्त रूप दिया जाना शेष है। इनके अभाव में देश को विनिर्माण महाशक्ति और चीन का विकल्प बनाना मुश्किल होगा। इसके साथ ही सार्थक कृषि सुधारों को भी किसानों को भरोसे में लेकर आकार दिया जाए, क्योंकि खेती-बाड़ी की दशा सुधारे बिना देश की दिशा सुधार पाना मुश्किल होगा।

गुंजन शर्मा, कमला नगर-नई दिल्ली

राजनीतिक संस्कृति में बदलाव की अपेक्षा

'तीसरे कार्यकाल की प्राथमिकताएं' शीर्षक से लिखे आलेख में संदीप घोष ने भविष्य की चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। हमारे संविधान में वे सारे प्रविधान हैं जिसमें पर्यावरण की चुनौती सहित अन्य अनेक समस्याओं का समाधान निहित है। समान नागरिक संहिता को लागू करने की भी बात है। आरक्षण किस प्रकार किसे देना है। यह भी प्रबंध है। लोकतंत्र की यात्रा कैसे जारी रखनी है। सब कुछ है। वोट बैंक के फेर में संविधान की व्याख्या अपने तरीके से करने का जो चलन है वह खत्म होना जरूरी है। भारतीय विविधता को वोट बैंक के लालच में इस हद तक न निचोड़ें कि देश की एकता एवं अखंडता खतरे में पड़ जाए। ऐसे में जनसंख्या, भ्रष्टाचार नियंत्रण सहित पर्यावरण सुरक्षा कर हम देश को आगे ले जा सकते हैं। देश का लोकतंत्र परिपक्व जरूर है पर प्रचार अभियान में परिपक्वता नहीं दिखना खेदजनक है। लिहाजा राजनीतिक संस्कृति में बदलाव की अपेक्षा है। तभी बेरोजगारी, आय असमानता, गरीबी, अकुशल कार्य बल सहित खेती किसानी से संबंधित अन्य अनेक समस्याओं का समाधान संभव है।

मुकेश कुमार मनन, पटना

तीसरे कार्यकाल की चुनौती

'तीसरे कार्यकाल की प्राथमिकताएं' शीर्षक से युक्त लेख में संदीप घोष ने जनमत के अनुरूप 2024 में भाजपा की एनडीए सरकार बनने की प्रबल संभावना के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल की जिन प्राथमिकताओं का जिक्र किया है, उनसे असहमत नहीं हुआ जा सकता। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार की वह समस्या है जो देश को दीमक की तरह खाए जा रही है। दरअसल देश की अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, अपराध और भ्रष्टाचार इस देश के समक्ष चुनौती के रूप में खड़ी ऐसी व्याधियां हैं, जिनका निदान करने में कोई भी केंद्र सरकार सफल नहीं हो पाई। जनमानस की अवधारणा के अनुरूप सरकारी नौकरी ही स्थायी रोजगार और आर्थिक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। जबकि इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी का नजरिया थोड़ा अलग है। सरकारी नौकरी के व्यामोह में भटकने वाले शिक्षित बेरोजगारों के रोजगार हेतु मोदी सरकार ने उद्योग में निवेश को बढ़ावा देते हुए शिक्षित युवाओं को स्टार्टअप के जरिये खुद किसी काम की शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित किया है। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के अनुरूप सुई से तोप तक हर जरूरत की वस्तु का निर्माण देश में ही हो। ताकि भारत गेहूं का निर्यात करके ब्रेड का आयात करने से बच सके।

pandeyvp1960@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

संपादकीय जागरण

(10) बुधवार, 29 मई, 2024 : ज्येष्ठ कृष्ण - 6 वि. 2081

समृद्धि के लिए शांति का होना अनिवार्य है

अंतहीन सुनवाई

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मथुरा के श्रीकृष्ण जन्म स्थान एवं शाही ईदगाह मस्जिद मामले की सुनवाई के समय मंदिर पक्ष ने यह आरोप लगाया कि मस्जिद पक्ष पुरानी बातें दोहराकर बहस को लंबा खींच रहा है। पता नहीं इस आरोप में कितना सच है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुछ समय पहले उच्च न्यायालय की ओर से भी यह कहा जा चुका है कि मस्जिद पक्ष के वकील पहले कही गई बातें फिर से न दोहराएं। अब अगली सुनवाई इस माह के अंत में होगी। कहना कठिन है कि यह सुनवाई कितनी लंबी चलेगी? जो कहा जा सकता है, वह यह कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट पक्ष सर्वोच्च न्यायालय जाएगा और वहां भी इस मामले की लंबी सुनवाई चल सकती है। यह तो अच्छा हुआ कि इस विवाद से जुड़े कई मामलों की जो सुनवाई मथुरा की स्थानीय अदालतों में हो रही थी, उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने यहां मंगवा लिया, ताकि सदियों पुराने इस प्रकरण का निस्तारण यथाशीघ्र किया जा सके, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिखता, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण पर रोक लगा रखी है। वैसे जब काशी के ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण हो चुका है, तब फिर न्याय और नीति यही कहती है कि मथुरा की ईदगाह मस्जिद का भी सर्वेक्षण हो, जिसके बारे में यह मान्यता है कि उसका निर्माण श्रीकृष्ण जन्म स्थान मंदिर पर किया गया। इसके वैसे ही दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हैं, जैसे ज्ञानवापी परिसर के हैं। काशी और मथुरा जैसे विवाद और भी हैं। इनमें से कुछ अदालतों में भी हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के धार जिले का भोजशाला परिसर। हिंदू पक्ष का यह मानना है कि यह देवी सरस्वती का मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह कमाल मौला के नाम से बनी मस्जिद है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक निर्णय के चलते पिछले दो माह से अधिक समय से भोजशाला परिसर का सर्वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से हो रहा है। इस तरह के कुछ और मामले भी उभर आए हैं। प्रश्न यह है कि आखिर ऐसे मामलों का निस्तारण कब और कैसे होगा? क्या यह उचित नहीं होगा कि इस तरह के जो भी प्रमुख मामले हैं, उनका निपटारा एक निश्चित समयसीमा में किया जाए। यह तभी संभव है, जब दोनों पक्षों के साथ-साथ न्यायपालिका भी इसके लिए तत्परता दिखाएगी। इसका कोई औचित्य नहीं कि इस तरह के मामलों की सुनवाई वर्षों तक होती रहे। उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई व्यवस्था करे, जिससे मंदिर-मस्जिद से जुड़े विवादों का पटाक्षेप हो और देश आगे बढ़े। यह भी समय की मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय पूजा स्थल अधिनियम की वैधानिकता की परख करे। इससे काशी, मथुरा के साथ इस जैसे अन्य विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी।

दूर हों कमियां

पोलियो की तरह टीबी मुक्त भारत की लड़ाई पूरे देश में लड़ी जा रही है, लेकिन राज्य में स्वास्थ्य विभाग के कुछ अफसरों की लापरवाही इसमें रोड़ा बन रही। पूर्वी भारत के सबसे बड़े मेडिकल कालेज और अस्पताल जेएलएनएमसीएच में टीबी की जांच को आए तीन हजार सैंपल खराब हो गए। नौ जिलों के ये सैंपल लंबे समय से जांच के लिए पड़े थे। 15 दिन पूर्व लैब में लगे एसी खराब हुए तो राज्य यक्ष्मा पदाधिकारी को इसकी जानकारी दी गई। एक-दो नहीं, पांच बार पत्राचार किया गया, लेकिन यक्ष्मा पदाधिकारी एसी ठीक करवा पाने में नाकाम रहे। नतीजा, सैंपल खराब हो गए। अब उन लोगों की जान पर बन आई है, जिनको इस बीमारी की आशंका है और उन्होंने अपना सैंपल यहां भेजकर उपचार की सोची थी। यक्ष्मा पदाधिकारी भी धन की कमी का रोना रो रहे, लेकिन विचारणीय पहलू यह है कि क्या यह वास्तव में राशि की दिक्कत का मामला है या इच्छाशक्ति का अभाव। टीबी उन्मूलन पर मुफ्त दवाई, प्रचार-प्रसार पर करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं। ऐसे में चंद सौ रुपयों के लिए इस कदर बीमारी को पसरने का मौका देना क्या उचित है। स्वास्थ्य विभाग का हर कर्मचारी और अधिकारी सेवा भाव के संकल्प के साथ ही इस क्षेत्र को चुनता है, लेकिन इस मामले में इसकी कमी दिखती है। इससे इतर, अभी कुछ दिन पूर्व टीबी की दवाई उपलब्ध नहीं होने की भी खबर आई थी। चूंकि, इसकी दवाई मुफ्त मिलती है तो यह दवा दुकानों में भी उपलब्ध नहीं होती। मरीज दवाई के लिए दर-दर भटकते हैं। लैब टेक्नीशियन की घोर कमी को भी दूर करना होगा। इनकी कमी से ही यहां लंबे समय से सैंपल लंबित थे। टीबी के खिलाफ लड़ाई में इन कमियों को चिह्नित कर तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है, तभी टीबी मुक्त भारत का सपना साकार हो पाएगा।

टीबी उन्मूलन में संसाधनों की कमी न हो और अफसर सतर्क होकर काम करें, यह सुनिश्चित कराना होगा।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

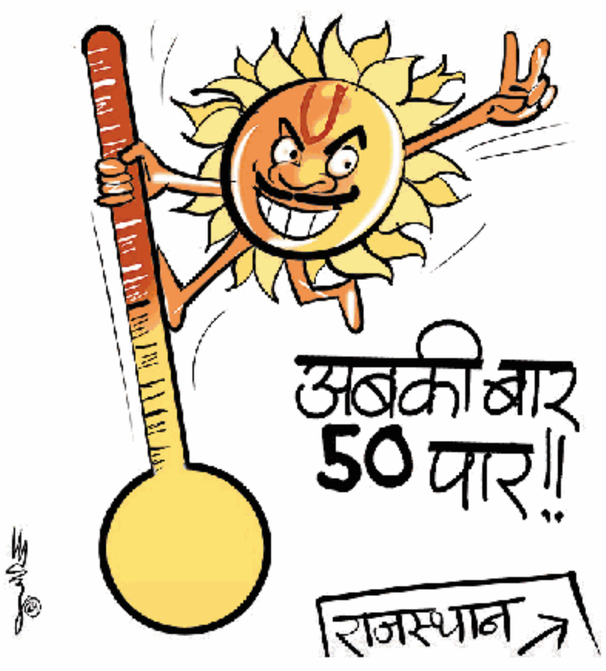

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या सेनाध्यक्ष को एक माह के सेवा विस्तार का फैसला सही है?

आज का सवाल
क्या आइएनडीआइए की बैठक से तृणमूल कांग्रेस का किनारा विपक्षी एकता के लिए झटका है?

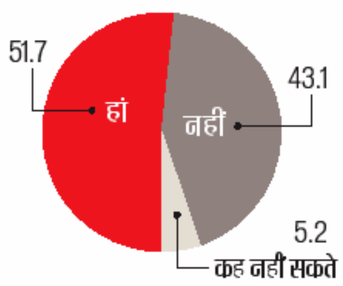

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

ओबीसी आरक्षण से खिलवाड़

अवधेश कुमार

पिछड़े वर्ग का हक छीनकर मुस्लिम जातियों को आरक्षण देने का चलन बंगाल के साथ-साथ राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना में भी है

लोकसभा चुनाव में पंथ या मजहब के आधार पर आरक्षण के मुद्दे को सांप्रदायिक करार देने वालों के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला एक आघात बनकर आया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रकट नाराजगी बताती है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम पर मुस्लिम समुदाय को ज्यादा से ज्यादा आरक्षण देने के असंवैधानिक, अनैतिक और समाज विरोधी फैसले पर वह केवल वोट के लिए यानी राजनीतिक कारणों से अड़ी रहना चाहती हैं। वह यहां तक बोल गईं कि जज को निर्देश देकर फैसला कराया गया है। बंगाल की सत्ता में आने के बाद ममता सरकार ने पांच लाख से ज्यादा ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए। उनमें से अधिकांश मुस्लिम समुदाय के लोगों को मिले। उच्च न्यायालय के अनुसार इन जातियों को ओबीसी घोषित करने के लिए वास्तव में रिलीजन ही एकमात्र मानदंड प्रतीत होता है और हमारा मानना है कि मुसलमानों की 77 श्रेणियों को पिछड़ों के रूप में चुना जाना पूरे मुस्लिम समुदाय का अपमान है। 77 श्रेणियों को ओबीसी में शामिल करने से स्पष्ट होता है कि इसे वोट बैंक के रूप में देखा गया है। न्यायालय की ये टिप्पणियां असाधारण हैं, लेकिन ये केवल तृणमूल और ममता बनर्जी ही नहीं, बल्कि देश के उन सभी राजनीतिक दलों, सरकारों और नेताओं के वास्तविक चेहरे को उजागर करतीं हैं, जो अन्य पिछड़ों के नाम पर केवल वोट के लिए मुसलमानों को असंवैधानिक रूप से आरक्षण का लाभ देने के लिए इसी तरह के कदम उठा रहे या उठाने की तैयारी में हैं।

वास्तव में, भारत के हर नागरिक को अवसर की समानता उपलब्ध कराने के लिए संवैधानिक तरीकों से व्यवस्था होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर समूहों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिया, जिसमें मजहब का बंधन नहीं है। उसमें हिंदुओं के साथ मुसलमान भी शामिल हैं। विरोध केवल पिछड़े, दलित और जनजातियों का हक मारकर असंवैधानिक तरीके से वोट बैंक के लिए मुसलमानों को आरक्षण देने का है। बंगाल में वाम मोर्चा सरकार ने 2010 में एक अंतरिम रिपोर्ट तैयार कराकर अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची बनाई और उसे ओबीसी-ए नाम दिया। सरकार ने बैकवर्ड मुस्लिम शब्द का प्रयोग करते हुए उनके लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की। इनमें ऐसे 42 समूह बनाए गए, जिनमें 41 केवल मुस्लिम समुदाय के थे। 2011 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में जब तृणमूल सत्ता में आई तो उसने कोई अंतिम रिपोर्ट प्राप्त किए बिना ही 11 मई, 2012 को 35 ऐसे वर्गों या श्रेणियों को शामिल किया, जो मुस्लिम थे। इनमें नौ ओबीसी-ए एवं 26 ओबीसी-बी में शामिल किए। इस तरह

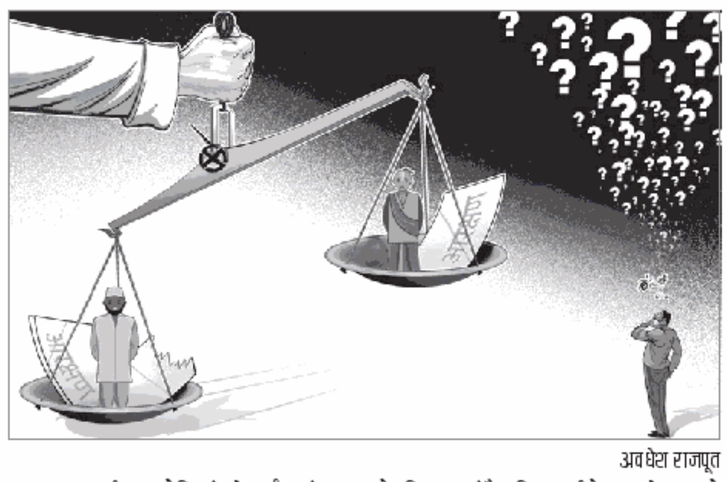

अवधेश राजपूत

कुल 77 वर्ग या श्रेणियां हो गईं। बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग और सरकार ने इसके लिए द्रुत गति से काम किया। नियमानुसार न कोई अधिसूचना जारी हुई, न छानबीन की गई, न आंकड़े जुटाए गए और न किसी तरह का आवेदन मांगा गया और न इस सामान्य नियम का पालन किया गया कि जिन्हें इस पर आपत्ति हो, वे उसे दर्ज करें। न्यायालय ने लिखा है कि ममता सरकार ने फैसला लेते समय ऐसा कोई आंकड़ा नहीं दिया, जिससे स्पष्ट हो सके कि बंगाल सरकार की सेवाओं में इस समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। अनारक्षित पूरे समुदाय को शामिल करने के लिए इस तरह की अपर्याप्तता का प्रमाण आवश्यक है। साफ है कि वोट के लिए मुसलमानों को आरक्षण देने के मामले में किसी तरह के नियम कानून के पालन की आवश्यकता ममता सरकार ने समझी ही नहीं।

इस फैसले से साबित हो गया है कि भाजपा तथा अन्य हिंदू संगठनों द्वारा ममता बनर्जी पर वोट के लिए पिछड़ों का हक मारकर मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने के लिए असंवैधानिक तरीके उपयोग करने का आरोप सही था। वोट के लिए आपको एक समुदाय को खुश करना है तो वहां नियम, कानून, संविधान तथा आरक्षण की वास्तविक अवधारणा या सिद्धांत आड़े नहीं आते। यह जानकर आश्चर्य होगा कि बंगाल में 179 जातियां अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं। इनमें 118 मुस्लिम हैं। यानी हिंदू पिछड़ी जातियों की संख्या केवल 61 है। जरा सोचिए कि जिस राज्य में करीब 70 प्रतिशत आबादी हिंदू हो, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में उसकी भागीदारी 33 प्रतिशत के आसपास कैसे हो सकती है? क्या यह हिंदू समाज के पिछड़े वर्ग के साथ धोखा और अन्याय नहीं है? इसे मुस्लिम तुष्टीकरण का शर्मनाक नमूना न कहें तो क्या कहें? भारत का संविधान किसी भी तरह रिलीजन, पंथ या मजहब को आरक्षण का आधार नहीं मानता।

वर्ष 2018 में मोदी सरकार ने जब पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया तो राज्यों को राज्य स्तर पर पिछड़ा वर्ग की सूची में जातियों को शामिल करने की स्वतंत्रता मिली। कई राज्यों ने बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय को इनमें शामिल कर दिया। बंगाल में 71 जातियों को ममता सरकार ने पिछड़ा वर्ग में शामिल किया, जिनमें 65 मुस्लिम समुदाय से संबंधित हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बंगाल सरकार से इस संदर्भ में औपचारिक पत्र लिखकर पूछताछ की। इसका यथेष्ट उत्तर आयोग को नहीं मिला। आयोग ने यह भी पूछा था कि आखिर मुसलमानों के अंदर जो पिछड़ी जातियां शामिल हैं, वे जातियां हिंदुओं में कहां चली गईं? बताया यह गया कि इनमें से अधिकांश ने मतांतरण कर लिया है। उल्लेखनीय है कि बंगाल में 1971 के बाद मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़नी शुरू हुई जो आगे रुकनी चाहिए थी। इसमें गिरावट नहीं आई। तब क्या मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के कारण हिंदू जातियां वाकई मतांतरित होकर मुसलमान बन गईं? यदि यह सच है तो इससे भयावह स्थिति कुछ नहीं हो सकती। वोट बैंक के लिए पार्टियां तुष्टीकरण में किस सीमा तक जा सकती हैं, इसका इससे सटीक उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता। यह स्थिति केवल बंगाल तक नहीं है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने पाया कि राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण का बड़ा हिस्सा मुस्लिम समुदायों के पास जा रहा है। यह स्थिति कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना सहित कई राज्यों में है। इसके लिए अलग-अलग तरीके अपनाए गए हैं। कहीं-कहीं तो क्रीमी लेयर के नियम ऐसे बना दिए गए, जिनमें हिंदू पिछड़ी जातियां आरक्षण की अर्हता से बाहर चली जाएं और मुस्लिम जातियां उसके दायरे में आ जाएं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

विकसित देश के सपने को तोड़ते हादसे

बीते सप्ताह गुजरात के राजकोट शहर में एक गेमिंग जोन में 35 लोग जलकर मर गए। इस भयावह घटना के कुछ दिन बाद दिल्ली के एक बेबी केयर सेंटर में सात बच्चे आग लगने के कारण काल के गाल में समा गए। इन दोनों घटनाओं में साझा केवल यही नहीं कि घटना का कारण आग लगना रहा। इसके अलावा भी बहुत कुछ साझा है, जैसे यह कि राजकोट के गेमिंग जोन ने अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल नहीं किया था। यही बात दिल्ली के बेबी केयर सेंटर के बारे में भी सामने आई। इसने भी न तो आग से बचाव के उपाय कर रखे थे और न ही अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले रखा रखा था। गेमिंग जोन के मामले में यह भी सामने आया कि राजकोट नगर निगम ने उसके संचालन के लिए न तो कोई लाइसेंस दे रखा था और ही संचालकों ने अन्य किसी नियामक संस्था से कोई अनुमोदन प्राप्त किया था। यही कहानी दिल्ली के बेबी केयर सेंटर की भी है। उसके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद वह अवैध रूप से चल रहा था। स्पष्ट है कि कोई भी यह देखने-जांचने वाला नहीं था कि उसके इलाके में कोई अवैध काम तो नहीं हो रहा है।

गेमिंग जोन या बेबी केयर सेंटर चलाना कोई ऐसा काम नहीं, जिसे गुपचुप रूप से किया जा सके। बेबी केयर सेंटर में पांच बच्चों की देखभाल की सुविधा थी, लेकिन उसमें 12 नवजात भर्ती थे। चूंकि किसी को परवाह नहीं थी, इसलिए इस सेंटर में न तो अग्निशमन यंत्र था और न ही कोई आपातकालीन निकास। इससे भी गंभीर बात यह थी कि यहां आक्सीजन के सिलेंडर रखे हुए थे। इसका मतलब है कि हादसे को निमंत्रण देने की तैयारी थी। ऐसी ही तैयारी राजकोट के गेमिंग जोन में भी दिखी। वहां लोगों का प्रवेश हो रहा था और वेल्डिंग का काम भी चल रहा था। चूंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं इसलिए राजकोट की घटना पर भी नेताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की और दिल्ली की घटना पर भी। दोनों जगह शासन-प्रशासन ने थोड़ी सख्ती का परिचय तो दिया, लेकिन इसके नतीजे में ऐसा कुछ विशेष नहीं हुआ, जो नजीर बन सके। राजकोट में गेमिंग जोन चलाने वाले संचालकों को गिरफ्तार कर लिया गया तो दिल्ली में बेबी केयर सेंटर

राजीव सचान

अपने देश में हर तरह के नियम-कानून हैं, पर उनके उल्लंघन की जैसी सुविधा यहां है, वैसी शायद ही अन्य कहीं हो

आग से तबाह हुआ राजकोट का गेमिंग जोन ● पीटीआइ

चलने वाले डाक्टर को। प्रश्न है कि दोनों ही जगह अग्निशमन विभाग और नगर निकाय के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जैसे गुजरात सरकार से कोई यह नहीं पूछ रहा कि नगर निगम और अग्निशमन विभाग के किसी अधिकारी-कर्मचारी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, वैसे ही दिल्ली सरकार से कोई यह सवाल नहीं कर रहा कि अग्निशमन विभाग, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी-कर्मचारी की गिरफ्तारी की जरूरत क्यों नहीं समझी गई? कायदे से तो दोनों शहरों के संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलना चाहिए।

राजकोट और दिल्ली के मामले इकलौते ऐसे प्रकरण नहीं, जिनमें सरकारी तंत्र को जवाबदेही से दूर रखने की कोशिश की गई हो। इस तरह के मामले रह-रहकर होते ही रहते हैं और उनमें बड़ी संख्या में लोग जान गंवाते हैं अथवा घायल होते हैं, लेकिन नियामक तंत्र के उन लोगों को कभी भी कठघरे में नहीं खड़ा किया जाता, जिनकी अनदेखी और लापरवाही के चलते जानलेवा घटनाएं होती रहती हैं। इसका उदाहरण है मुंबई में एक विशालकाय होर्डिंग गिरने से कई लोगों की मौत। यह विशालकाय होर्डिंग अवैध रूप से लगा था, लेकिन किसी को 'नजर' नहीं आ रहा था। जब यह गिर गया और उसमें कई लोगों की जान चली गई तो सरकारी तंत्र ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया। होर्डिंग लगवाने वाला तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन नगर निकाय के किसी अधिकारी-कर्मचारी को गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं समझी गई। कोई नहीं जानता कि क्यों?

भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सरकारी तंत्र की लापरवाही से रह-रहकर हादसे होते रहें और उनमें बड़ी संख्या में लोग मरते रहें। दुर्भाग्य से अपने देश में यही हो रहा है। जब कोई बड़ी घटना घट जाती है और उसमें अधिक संख्या में लोग मारे जाते हैं तो शोक संवेदनाओं का तांता लग जाता है और फौरी कार्रवाई करने के साथ उच्चस्तरीय जांच के आदेश दे दिए जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हीं कारणों से वैसी ही घटना फिर सामने आती है, जैसी पहले हो चुकी होती है। यही कारण है कि न तो हादसे कम हो रहे हैं और न ही उनमें जान गंवाने वालों की संख्या में कमी आ रही है। हादसे दुनिया में हर कहीं होते हैं, लेकिन विकसित और विकासशील देश कम से कम उनसे सबक लेते हैं और ऐसी व्यवस्था करते हैं, जिससे बार-बार एक जैसे कारणों से हादसे न हों। भारत में कोई सबक सीखने से इन्कार किया जा रहा है और यही कारण है कि विकसित देश बनने के संकल्प को साकार करना कहीं अधिक कठिन दिख रहा है। अपने देश में हर तरह के नियम-कानून हैं, लेकिन उनके उल्लंघन की जैसी सुविधा यहां है, वैसी शायद ही किसी विकासशील और विकसित राष्ट्र का स्वप्न देखने वाले देश में हो। भारत में लोग किस कदर कदम-कदम पर नियम-कानूनों का ठसक के साथ उल्लंघन करते हैं और सरकारी तंत्र में बैठे लोग उनकी मदद करने या फिर उनके अपराध को ढकने के लिए तैयार रहते हैं, इसका शर्मनाक उदाहरण पुणे का कार हादसा भी है।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मन की रिक्तता

जीवन किसी के व्यक्तिगत नियम से नहीं चलता और अपने प्राकृतिक नियम से संचालित होता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम जिस वस्तु या उपलब्धि को बहुत तीव्र इच्छा के साथ चाहते हैं और वह हमें नहीं मिलती तो फिर हम बलपूर्वक उसे पाने की चेष्टा करने लगते हैं। यह मनुष्य की बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि इस प्रयास में हम अपने बहुमूल्य समय के साथ-साथ अपनी ऊर्जा भी व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। इस तरह व्यक्ति अपने मन को ढेर सारी नकारात्मकता से भर लेता है। इस बात को लेकर हमारी समझ जितनी स्पष्ट होगी, हमारा जीवन उतना ही बेहतर होगा कि प्रकृति के प्रत्येक पहलू पर हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता है। कभी-कभी प्रकृति यह चाहती है कि हमारे जीवन और मन में कुछ रिक्तता बनी रहे ताकि वह उपयुक्त समय आने पर उस रिक्तता में कोई उचित-उपयुक्त रचना कर उसे भरा जा सके। याद रहे कि किसी खाली कैनवास पर ही एक सुंदर चित्र की निर्मिति संभव है।

वैसे तो एक धारणा यह है कि खाली दिमाग या मन शैतान का घर होता है, लेकिन यह तब होता है जब हम उस खालीपन को संभालना न जानते हों। उद्विग्न मन या बहुत सारी नकारात्मकता से भरे मन के साथ हम अपनी प्रगति में स्वयं ही बाधा बन जाते हैं। हमें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम अनंत की चाह में उलझ जाते हैं और फिर मन को शून्य करना भूल जाते हैं। जबकि अनंत का मार्ग भी शून्य से होकर ही गुजरता है। आध्यात्मिक मार्ग भी स्वयं को खाली करने पर ही जोर देता है ताकि ईश्वर की अनंत ऊर्जा से उस खालीपन को भरा जा सके। मन के खालीपन के संबंध में चाणक्य ने कहा था कि विवेकशील व्यक्ति अपने मन को खाली रखता है। उनके शब्दों में एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को व्यर्थ की चीजों से खाली रखता है ताकि उसमें ज्ञान और सच्चाई का निवास हो सके।

लवली आनंद

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

अहम सुधारों का हो सूत्रपात

'तीसरे कार्यकाल की प्राथमिकताएं' शीर्षक से प्रकाशित अपने आलेख में संदीप घोष ने उन प्राथमिकताओं को चिह्नित किया है, जो प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में उनके एजेंडे में रहनी चाहिए। यह सही है कि अभी एक चरण का चुनाव और मतगणना के नतीजे आना शेष हैं, लेकिन व्यापक तौर पर यही अनुमान लगाया जा रहा है कि मोदी सहजता के साथ बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर सकते हैं। लेखक महोदय का यह कहना भी उचित है कि मोदी के पक्ष में जो जनादेश उभरता दिख रहा है वह देश को विकसित बनाए जाने की भावना के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में मोदी को इस कार्यकाल में कुछ कड़े सुधारों को लागू करना होगा। इन सुधारों को आकार देने में सभी अंशभागियों की चिंताओं का उचित निराकरण कर आगे बढ़ा जाए। देश में पिछले कुछ समय से सुधारों की बयार चली है, लेकिन अभी भी भूमि और श्रम जैसे महत्वपूर्ण सुधारों को मूर्त रूप दिया जाना शेष है। इनके अभाव में देश को विनिर्माण महाशक्ति और चीन का विकल्प बनाना मुश्किल होगा। इसके साथ ही सार्थक कृषि सुधारों को भी किसानों को भरोसे में लेकर आकार दिया जाए, क्योंकि खेती-बाड़ी की दशा सुधारे बिना देश की दिशा सुधार पाना मुश्किल होगा।

गुंजन शर्मा, कमला नगर-नई दिल्ली

त्रासदी के बाद खुलती आंख

यह बड़ी विडंबना है कि जब कोई बड़ी त्रासदी हो जाती है, तब व्यवस्था की आंख खुलती है। गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट टीआरपी गेम जोन त्रासदी मामले में राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और सिस्टम पर कोई भरोसा नहीं होने जैसी बातें भी कही है। घटना के बाद गेम जोन को अनुमति देने वाले अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, परंतु इतनी बड़ी त्रासदी के बाद क्या यह कदम राज्य की मशीनरी पर सवाल पैदा नहीं करता? कई ऐसी संस्थाएं, जो बिना एनओसी की चल रही हैं और सुरक्षा के उपाय की अनदेखी करती हैं, अगर उन पर पहले कार्रवाई होती तो इस तरह की घटना नहीं होती। व्यवस्था को इतना सुदृढ़ करना होगा कि बिना समुचित सुरक्षा प्रबंधों के इस तरह के मनोरंजन के स्थल या मैरेज हाल, कांफ्रेंस हाल आदि की अनुमति ही नहीं दी जाए।

आनंद पांडेय, रोसड़ा

खत्म हुई भाषा की शालीनता

जगमोहन सिंह राजपूत द्वारा लिखित आलेख 'दलगत राजनीति से बचे नई लोकसभा' पढ़ा। लोकतंत्र शासन व्यवस्था की सर्वोत्तम प्रणाली मानी जाती है। आजादी के बाद कई वर्षों तक चुनाव के दौरान सभी दलों के नेताओं के बीच स्नेह देखा जाता था। प्रचार के दौरान नेता एक दूसरे पर अपमानजनक टिप्पणी नहीं किया करते थे, लेकिन आज की राजनीति में नैतिकता का पतन हो चुका है, भाषा की शालीनता समाप्त हो चुकी है, चुनाव के दौरान अनर्गल टिप्पणियों की बाढ़ आ गई है। परिवारवाद, वंशवाद बढ़ चुका है। लोकतंत्र में कुछ खामियां प्रवेश कर चुकी हैं। इन्हें नई लोकसभा के गठन के बाद दूर करने का प्रयास करना चाहिए। नए चुन कर आए सांसदों को दलगत भावनाओं को छोड़कर अपने पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए व्यवहार करना होगा।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गया

हार का ठीकरा फोड़ने की कवायद

संपादकीय आलेख 'ईवीएम पर दोषारोपण' पढ़ा। लगता है, विभिन्न स्रोतों से आइएनडीआइए एवं इसके प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस को आभास हो चुका है कि मोदी सरकार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में अब हार का ठीकरा किसी पर फोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। इसका उदाहरण ईवीएम पर बार-बार अनावश्यक संदेह जताना है। मोदी सरकार से पहले भी वर्ष 2001 के बाद ईवीएम में संभावित छेड़छाड़ के मसले को देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में उठाया जा चुका है। 2001 में मद्रास उच्च न्यायालय, 2002 में केरल उच्च न्यायालय, 2004 में दिल्ली उच्च न्यायालय और वर्ष 2004 में कर्नाटक उच्च न्यायालयों ने भारत में हुए चुनावों में ईवीएम के उपयोग में निहित तकनीकी सुदृढ़ता और प्रशासनिक उपायों के समस्त पहलुओं पर गौर करने के बाद यह पाया है कि भारत में ईवीएम विश्वसनीय, भरोसेमंद एवं पूरी तरह से छेड़छाड़ मुक्त है। इनमें से कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं की अपीलों को उच्चतम न्यायालय ने सिरे से खारिज कर दिया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय एवं मद्रास उच्च न्यायालय दोनों ने ही यह अवलोकन किया कि मतपत्र/मतपेटी वाली चुनाव प्रणाली की तुलना में चुनाव में ईवीएम के उपयोग के कई लाभ हैं। कोई बायरस या बग डालने का सवाल भी नहीं पैदा होता है क्योंकि ईवीएम की तुलना पर्सनल कम्प्यूटर से नहीं की जा सकती। चुनाव आयोग ने भी आश्वस्त किया है।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

X पोस्ट

प्रणब मुखर्जी ने कभी यह कहा था कि किसी भी चुनाव को नतीजे आने के बाद ही समझा जा सकता है। उससे पहले नहीं। शोभना के. नायर@SobhanaNair

ईवीएम को लेकर चलाया जा रहा शर्मनाक विमर्श विपक्षी दलों को ही सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाएगा। लगता नहीं कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा भी है।

शेहला राशिद@Shehla_Rashid

पाकिस्तानी नेता अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के प्रति इतने दीवाने क्यों हैं? क्या वे भारत में भी पाकिस्तान जैसे हालात देखना चाहते हैं? कम से कम भारत में लोग सही तरह से चुनाव तो कर रहे हैं।

दानिश कनेरिया@DanishKaneria61

राहुल गांधी ने एक लाइन पकड़ ली है और मीडिया पर जमकर हमला बोल रहे हैं। मानो उनकी लड़ाई भाजपा से न होकर पत्रकारों से है। पत्रकारों को हर जगह अपशब्द बोल रहे हैं। विवेक मौर्या@thevivekmaurya

राहुल गांधी खुद इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे हैं? चुनाव के समय तो कई पत्रकार उनका इंटरव्यू लेना चाह रहे होंगे। फिर उन्होंने इंटरव्यू क्यों नहीं दिए? कितने पत्रकार तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए लालायित हैं। कम से कम उनको तो इंटरव्यू दे ही देना चाहिए था। ऋचा अनिरुद्ध@richaanirudh

जनपथ

हिंसा में है डूबता उतराता बंगाल,
खून खराबे के लिए कौन रच रहा चाल।
कौन रच रहा चाल हाल दिखता है बदतर,
सिर्फ यही इक राज्य खून से दिखता है तर।
जब होता मतदान लोग बैठें दिल थामे,
कौन गँवाए जान न जाने इस हिंसा में।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्र, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 47

****

अमर उजाला

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ बुधवार, 29 मई 2024

यदि अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, तो उसके लिए गुंजाइश बनाइए। -मिल्टन बर्ले

पापुआ न्यू गिनी का भू-स्खलन हो या अमेरिका में आया तूफान, वनाग्नि से जूझते उत्तराखंड के जंगल हों या रिकॉर्ड गर्मी से झुलसती दिल्ली का मुंगेशपुर- ये सभी प्रमाण हैं कि जलवायु में आ रहे बदलावों को लेकर संकट की जिन चेतावनियों को हम वर्षों से सुनकर भी अनसुना करते रहे, वे चौखट तक आ पहुंची हैं।

पापुआ से मुंगेशपुर

पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी से छह सौ किलोमीटर दूर उत्तर-पश्चिम में स्थित एंगा प्रांत में हुए भारी भू-स्खलन में दो हजार से ज्यादा लोगों का जिंदा दफन होना हो या मध्य अमेरिका के कुछ राज्यों में आया शक्तिशाली तूफान हो या चक्रवाती तूफान रेमल से उबरते बांग्लादेश व भारत में बंगाल, ओडिशा व पूर्वोत्तर के राज्य हों, वनाग्नि से जूझते उत्तराखंड के जंगल हों या फिर भीषण गर्मी की चपेट में आया पूरा उत्तर भारत हो, ये सभी घटनाएं चिंतित करने वाली हैं, लेकिन अब ऐसी घटनाओं की आवृत्ति जिस तरह से पूरी दुनिया में बढ़ी है, वह और भी परेशान करने वाली है। जलवायु में आ रहे बदलावों को लेकर जिन चेतावनियों को हम वर्षों से सुनकर भी अनसुना करते रहे हैं, वे आज अगर चौखट तक आ पहुंची हैं, तो इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। राजधानी के मुंगेशपुर में अगर तापमान उन्चास डिग्री सेल्सियस को छूने को तैयार है, तो हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि धरती पर गर्मी को रोककर रखने वाली ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कोई और नहीं, बल्कि हम ही कर रहे हैं और इसके नतीजे अब स्वाभाविक ही खुलकर सामने आ रहे हैं। मौसम में आ रहे असमय बदलाव, ग्लेशियर और बर्फ की सिकुड़ती चादरें, सूखती नदियां और झीलें, भौगोलिक सीमाएं बदलती वनस्पतियां व पशु-पक्षी और समय से पहले खिलते पेड़-पौधे, ये सब जलवायु के साथ दशकों से हो रहे खिलवाड़ का ही तो नतीजा हैं। पापुआ न्यू गिनी के एंगा प्रांत में हुए भारी भूस्खलन में दो हजार से ज्यादा लोगों की मौत की खबर बेहद दुखद इसलिए भी है कि इस देश की अस्सी फीसदी आबादी पहले ही अभावों में जिंदगी बसर कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में यहां भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और समुद्री तूफान की घटनाएं जिस तरह से बढ़ी हैं, वे जलवायु के प्रति गंभीर होने की जरूरत को ही रेखांकित करती हैं। अमेरिका के टेक्सास, ओक्लाहोमा, कैंटुकी और अर्कांसस राज्यों में आए शक्तिशाली तूफान से आई

तबाही एक और प्रमाण है, जो बताता है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की समस्या नहीं रह गई। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) ने भी स्वीकारा है कि मनुष्य ने अपने इतिहास में इस तेजी से हादसों को होते नहीं देखा है। मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न ग्रीनहाउस गैसों की वजह से आने वाले कई दशकों तक वैश्विक तापमान में वृद्धि जारी रहने की आशंकाएं डराती हैं। हमारा भविष्य हमारे द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्रा पर ही निर्भर है, इसलिए अगर हम उत्सर्जन कम कर सकें, तभी इसके कुछ सबसे बुरे प्रभावों से बच सकते हैं।

वर्तमान पर ध्यान देने का वक्त आ गया है

चार जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सत्ता में आने वाली नई सरकार के सामने शिक्षा और रोजगार के मुद्दों से निपटने की चुनौती होगी। हालांकि समग्र रूप से शिक्षा प्राप्ति में बढ़ोतरी हुई है, इसके बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दरकार अब भी बनी हुई है।

पत्रलेखा चटर्जी
वरिष्ठ पत्रकार

चार जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद चाहे जो भी सत्ता में आए, कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उम्मीद है कि नई सरकार कुछ कटु सच्चाइयों पर अधिक ध्यान देगी। भारत तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। हम अक्सर जनसांख्यिकीय लाभांश के बारे में बातें करते हैं। देश के युवा कार्यबल में आर्थिक विकास, नवाचार और उत्पादकता को बढ़ाने की क्षमता है। लेकिन अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ते उन उच्च शिक्षित युवाओं के लिए पर्याप्त संख्या में उचित रोजगार सृजित नहीं कर पा रही है, जो सुरक्षित, ऊंचे वेतन वाली व्हाइट कॉलर जॉब की उम्मीद रखते हैं। रोजगार पाने का मतलब अक्सर कम वेतन वाला, अनिश्चित काम करना होता है।

पिछले हफ्ते एक खबर पर मेरा ध्यान गया, जिससे पता चलता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। एक राष्ट्रीय अखबार की खबर के अनुसार, आईआईटी कानपुर के एक पूर्व छात्र धीरज सिंह द्वारा दाखिल आरटीआई आवेदन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, देश के 23 आईआईटी के करीब 38 प्रतिशत छात्र अब तक बेरोजगार हैं। समाचार में सिंह के हवाले से बताया गया है कि इस वर्ष सभी 23 में 7,000 छात्रों को आईआईटी कैंपस के माध्यम से नियुक्ति नहीं मिलि है। सिर्फ दो साल पहले यह आंकड़ा इसके लगभग आधा (3,400) था। सिंह ने बताया कि जहां अधिक छात्र रोजगार के लिए आवेदन कर रहे हैं, वहीं दो साल में बेरोजगार छात्रों की संख्या 2.3 गुना बढ़ गई है।

यदि यह कोई अकेला मामला होता, तो इसे नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन भारत में शिक्षित युवाओं के बीच बेरोजगारी पिछले कुछ समय से बड़ी चिंता का विषय रही है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन एवं दिल्ली स्थित थिंक टैंक मानव विकास संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित इंडिया एंप्लॉयमेंट रिपोर्ट, 2024 के अनुसार, भारत के

बेरोजगार कार्यबल में 83 फीसदी युवा हैं और कुल बेरोजगार आबादी में माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं की हिस्सेदारी वर्ष 2000 में 35.2 फीसदी थी, जो 2022 में बढ़कर 65.7 फीसदी हो गई।

वर्ष 2023 के लिए परिशिष्ट के साथ मुख्यतः 2000 और 2022 के बीच के आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण और नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधरित यह रिपोर्ट बताती है कि शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी का स्तर काफी ऊंचा है। शिक्षा के स्तर के साथ युवा बेरोजगारी दर बढ़ी है। स्नातक या उससे ज्यादा शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है और शिक्षित पुरुषों के मुकाबले शिक्षित महिलाओं में बेरोजगारी दर ज्यादा है। क्या भारत के श्रम बाजार में उनके लिए अवसर हैं, लेकिन शिक्षित युवाओं के लिए बेहतर गुणवत्ता वाली पर्याप्त नौकरी नहीं है? आंकड़े इसी तरफ इशारा करते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात यह है कि गरीब परिवारों के शिक्षित युवा विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों में हैं।

रिपोर्ट बताती है कि 'सबसे कम मासिक प्रति व्यक्ति व्यय क्वाइंटाइल (29.4 प्रतिशत) में माध्यमिक या उच्च-माध्यमिक शिक्षा वाले युवाओं के बीच बेरोजगारी दर उच्चतम क्वाइंटाइल (25.8 प्रतिशत) वाले युवाओं की तुलना में अधिक थी। यहां बता दें कि क्वाइंटाइल किसी आंकड़े को पांच बराबर भागों में विभाजित करती है। नतीजतन युवाओं के बीच उच्च बेरोजगारी दर आंशिक रूप से व्हाइट कॉलर जॉब की आकांक्षाओं के कारण हो सकती है, जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। सबसे गरीब युवा, जिनके पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संसाधनों और सामाजिक पूंजी का अभाव है, वे अधिक पीड़ित हैं।'

चिंता की बात है कि हाशिये पर पड़े अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उच्च शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर अन्य पिछड़ा वर्ग या सामान्य श्रेणी के युवाओं की तुलना में ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सामाजिक रूप से हाशिये के युवाओं में उच्च बेरोजगारी उन चुनौतियों का संकेत देती है, जिनका सामना उन्हें बेहतर रोजगार की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए करना पड़ता है। यह प्रवृत्ति सामाजिक विषमताओं को कायम रखती है और सामाजिक रूप से ऊपर उठने में बाधा उत्पन्न करती है।

क्या उच्च शिक्षित युवाओं के लिए शिक्षा के स्तर और नौकरियों के बीच विसंगति समय के साथ बढ़ी है? इंडिया एंप्लॉयमेंट रिपोर्ट, 2024 इस बारे में कुछ संकेत देती है। यह बताती है कि उच्च शिक्षित युवाओं (पुरुष एवं महिला) का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवा भी शामिल हैं, अपनी नौकरी से ज्यादा योग्यता रखते हैं। तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं में से भी 0.4 फीसदी ऐसे व्यवसायों में लगे हुए थे, जो उनकी योग्यता के अनुरूप नहीं थे। हालांकि समग्र रूप से शिक्षा प्राप्ति में बढ़ोतरी हुई है, जिससे नौकरी की मांग रही है, जो (उच्च शिक्षित और कम शिक्षित युवाओं) में रोजगार दर को कम कर रही है और बेरोजगारी दर बढ़ा रही है। इसके चलते उच्च शिक्षित युवा भी कम कौशल वाले ब्ल्यू-कॉलर जॉब अपनाने लगते हैं।'

एक और चिंतनीय विषय है कि तमाम उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्ति का स्तर अब भी निम्न बना हुआ है और गुणवत्ता चिंता का विषय है। गरीब राज्यों एवं हाशिये के समूहों में मध्य एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा के बाद ड्रॉप-आउट (स्कूल छोड़ने) की दर उच्च है। शिक्षा की गुणवत्ता लगातार चिंता का विषय है। स्कूली स्तर पर और सामान्य रूप से भी सीखने के स्तर में कमी आई है और उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता खराब है। हम ऐसी स्थिति को जारी नहीं रहने दे सकते। रिपोर्ट बताती है कि योग्यताओं, आकांक्षाओं और नौकरियों के बीच विस्फोटक अंतर असंतोष बढ़ा रहा है। हालांकि ऐसे मामले अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों में आम रहे हैं, लेकिन अब आर्थिक रूप से ज्यादा गतिशील राज्यों में भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इसलिए अब सुदूर अतीत और सुदूर भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वर्तमान पर ध्यान देने का समय आ गया है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

चौधरी चरण सिंह
23-12-1902 से 29-05-1987

पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा रहे भारतरत्न चौधरी चरण सिंह की आज पुण्यतिथि है। वे लोगों से हमेशा कहा करते थे कि हमें अपनी बात सोच-समझकर और उचित अवसर पर ही बोलनी चाहिए।

बाते हाथी पाइए बाते हाथी पांव

अनकही बात अपनी चेरी है, पर कही हुई बात स्वामिनी हो जाती है। अतएव जीभ को सदैव अपने वश में रखना और समय पर विचार कर ही खोलना चाहिए अर्थात आपको जो कुछ कहना है, उसके हर पहलू पर विचार किए बिना और उसका जो परिणाम होगा, उस पर सूक्ष्म निरीक्षण किए बिना कुछ नहीं कहना चाहिए। ऐसा करने से अपकीर्ति का भय न रहेगा, किसी के सामने लज्जित न होना पड़ेगा और पश्चाताप से मुक्ति भी मिल जाएगी। कहावत है- बाते हाथी पाइए-बाते हाथी पांव। अर्थात बात अच्छी होने पर हाथी मिल सकता है और मुंह से बुरी बात निकलने पर हाथी के पांव तले रौंदा भी जा सकता है। समाज में बैठकर न अधिक बोलना चाहिए और न बिल्कुल चुप ही रहना ठीक है। शेखसादी का कथन है कि दो बातें मूर्खता की हैं, एक तो बात करने के अवसर पर चुप रहना, दूसरे-चुप रहने के स्थान पर बोलना। हिंदी में भी एक उक्ति है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। अर्थात मनुष्य को मितभाषी होना चाहिए।

शेक्सपियर ने अच्छी बात का लक्षण इसी प्रकार बताया है-बातचीत प्रिय हो, पर ओछी न हो, चुहल की हो पर बनावट लिए न हो, स्वच्छंद हो पर अश्लील न हो, विद्वतापूर्ण हो पर दंभयुक्त न हो, अनोखी हो, पर असत्य न हो। हमारी वाणी में ही अमृत है, और इसी में विष है। जहां मीठी बातें बोली जाती हैं, वहां की हवा मधुमय हो जाती है और चारों ओर सुख ही सुख दिख पड़ता है और जहां कटु अथवा अशिष्ट भाषण होता है, वह स्थान नरक हो जाता है। चाणक्य कहते हैं-प्रिय वाक्य बोलने से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए प्रिय बोलना चाहिए। ऐसा बोलने में कंजूसी कैसी? इसी संबंध में कबीर की दो साखियां हैं-बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। हिये तराजू तोल के, तब मुख बाहर खोल।। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोय। औरन को सीतल करै, आपहु सीतल होय।। गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है-तुलसी मीठे वचन से, सुख उपजत चहुं ओर। वशीकरण इक मंत्र है, तजि दे वचन कठोर।।

मधुर भाषण का उद्देश्य यह है कि परस्पर बातें करने में एक-दूसरे के मान व आदर और आनंद व प्रेम का ध्यान रखा जाए, जिससे मनुष्य एक-दूसरे के निकट आ सके। अभिवादन करना, धन्यवाद देना, समाचार पूछना, आशीर्वाद देना, अच्छी बातें करना, अच्छी बातें समझाना, इसी एक गुण के भिन्न-भिन्न अंश हैं। इसलिए भले आदमी का कर्तव्य है कि न ताना दे, न लानत भेजे और न कटु या अशिष्ट वाक्य कहे। अच्छी, मीठी बातें कहे, वरना चुप रहे। मधुर भाषण की इससे बड़ी कसौटी नहीं कि यदि विद्या, धन, बल अर्थात सत्ता या आयु में छोटा कोई व्यक्ति आपके पास किसी काम से आए, तो उससे बात करने के अनंतर उसके मन में आपके विद्या, धन आदि में बड़े होने की अनुभूति न हो और वह मन ही मन आपकी प्रशंसा करता जाए।

बोलने का वक्त

सूत्र

बिना पूछे, बिना कहे अपनी सम्मति देना या किसी की बातचीत में दखल देना असभ्यता है। जब कोई आपसे बातचीत करे या पूछे-ताछे, तभी बोलना ठीक है, वरना चुपचाप सुनते रहना चाहिए। यदि बीच में बोलना जरूरी हो, तो पहले नम्रतापूर्वक बोलने की अनुमति ले लेनी चाहिए। जायसी ने कहा है-बिन पूछे जो बोलहि बोला, होइ बोल माटी के मोला।

दूसरा पहलू

पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय बने गोपीचंद ने यात्रा से लौटकर कहा-वहां हर इन्सान को जाना चाहिए।

उस विराटता की कल्पना भी मुश्किल

काश मैं सभी 140 करोड़ भारतीयों को अपने साथ अंतरिक्ष यात्रा पर ले जा पाता। मैं तो कहूंगा कि सिर्फ भारतीय ही नहीं, हर इन्सान को अंतरिक्ष में जाकर देखना चाहिए कि दूसरी तरफ से हमारी पृथ्वी कैसी लगती है। ये शब्द हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जन्मे भारतीय मूल के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने 30 वर्षीय गोपीचंद थोटाकुरा के। उद्यमी और पायलट गोपीचंद ने पहले भारतीय पर्यटक और अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले दूसरे भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। गोपीचंद ने 19 मई को ब्लू ओरिजिन के पर्यटन रॉकेट से छह लोगों के साथ यात्रा शुरू की थी। यान ने यात्रियों को अंतरिक्ष के किनारे तक पहुंचाया। कैप्टन गोपीचंद चालक दल का हिस्सा थे। उनकी इस अंतरिक्ष यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया।

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जन्मे 30 वर्षीय गोपीचंद थोटाकुरा अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले राकेश शर्मा (1984 में) के बाद दूसरे भारतीय बन गए हैं।

गोपीचंद ने 19 मई को ब्लू ओरिजिन के पर्यटन रॉकेट से छह लोगों के साथ यात्रा शुरू की थी। यान ने यात्रियों को अंतरिक्ष के किनारे तक पहुंचाया। कैप्टन गोपीचंद चालक दल का हिस्सा थे।

गोपीचंद के अनुसार, उनकी अंतरिक्ष यात्रा अद्भुत रही, जिसका अनुभव शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे अपनी आंखों से देखना होगा। उन्होंने कहा कि ऊपर से जब हम आलीशान नीली गेंद (पृथ्वी) को देखते हैं, तो वाह! क्या सुदंर दृश्य दिखता है। यह वैसी नहीं है, जैसी फिल्मों में दिखाई जाती है। यह मेज पर रखी ग्लोब की तरह भी नहीं है और न ही उस चार्ट की तरह है, जिसे आपने बचपन में देखा होगा। वह कहते हैं कि आप जब पहली बार कहीं जाते हैं, जैसे- केरल, हिमालय, स्विस आल्प्स, तो वहां भी आप कुछ ऐसा देखते हैं, जिन्हें पहले कभी न देखा हो और वे खूबसूरत भी हो सकते हैं, लेकिन अंतरिक्ष की यात्रा के बाद मेरा मकसद बदल गया। अब मेरे जीवन का उद्देश्य इस धरती को बेहतर जगह बनाना है।

उन्होंने कहा कि खिड़की से बाहर झांकते हुए मैंने जो कुछ देखा, उसे समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने अमेरिका महाद्वीप, यूरोप के कुछ हिस्से और अटलांटिक महासागर को एक साथ देखा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं वास्तव में किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। आप बस इसकी विराटता की कल्पना कर सकते हैं, वास्तविक अनुभव स्वयं वहां जाने पर ही होगा।

जैसे ही शून्य गुरुत्वाकर्षण में मैंने अपनी बेल्ट खोली, मैं तैरने लगा था। शुरू में समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। जब मैंने खुद को संभाला, और खड़ा हुआ, तो चीजें स्पष्ट हो गईं। यह अनुभव बिल्कुल अलग था। इससे मुझे एहसास हुआ कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम कितने तुच्छ (छोटे) हैं। जब आप वहां जाते हैं और इस नीली पृथ्वी को देखते हैं, तो आपको ब्रह्मांड की विराट शक्ति का एहसास होता है और तभी इस पृथ्वी को बेहतर जगह बनाने की प्रेरणा जगती है। **(विभिन्न स्रोतों से)**

आंकड़े

बासमती चावल का निर्यात

भारत ने वित्त वर्ष 2024 में 48,389.29 करोड़ रुपये के बासमती चावल का निर्यात किया है। इनमें सबसे ज्यादा सऊदी अरब भेजा गया।

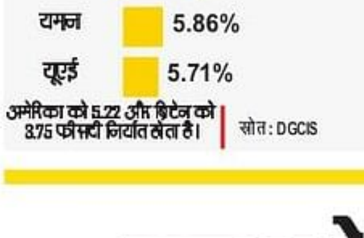

अमेरिका को 5.22 और ब्रिटेन को 3.75 फीसदी निर्यात लेता है। | स्रोत: DGCIS

जब अग्निदेव का तेज कम रह गया, तो उन्होंने महर्षि अंगिरा के समक्ष प्रार्थना की। इसके बाद महर्षि ने उन्हें पुत्र के रूप में वरण किया।

अग्निदेव बने बृहस्पति

अंतर्यात्रा
संकलित

पौराणिक कथाओं के अनुसार, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अंगिरा के तप से अग्नि का तेज कम रह गया। एक बार जल में तपस्या कर रहे अग्निदेव ने देखा कि अंगिरा के तपोबल के सामने उनकी तपस्या व प्रतिष्ठा छोटी पड़ रही है। इससे अग्निदेव निराश हो गए।

अग्निदेव महर्षि अंगिरा के पास गए और कहा-आप प्रथम अग्नि हैं, आपके तेज के सामने मेरा तेज कुछ भी नहीं, अब मुझे कोई अग्नि नहीं कहेगा। अग्निदेव की बात सुनकर महर्षि ने उन्हें देवताओं को हवि पहुंचाने का कार्य सौंपा। साथ ही पुत्र के रूप में अग्नि का वरण किया, जिसके बाद अग्निदेव ही बृहस्पति नाम से अंगिरा के घर पुत्र रूप में जन्मे। महर्षि अंगिरा की विशेष महिमा है।

मान्यता है कि महर्षि अंगिरा ने ही सबसे पहले अग्नि उत्पन्न की थी। अंगिरा ने धर्म व राज्य की व्यवस्था पर बहुत काम किया। वेदों की रचना में महर्षि अंगिरा का बड़ा योगदान रहा है। अंगिरा ने सृष्टि के आदि काल में वेद ज्ञान को सुनने, समझने व आदिपुरुष ब्रह्मा को समझाने का कार्य किया।

भृगु, अत्रि सहित अन्य ऋषियों ने महर्षि अंगिरा से ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने वेदों की रचना के साथ अपने नाम से *अंगिरा स्मृति* की भी रचना की। महर्षि अंगिरा की पत्नी दक्ष प्रजापति की पुत्री स्मृति थीं, जिनसे इनका वंश आगे बढ़ा। बताया जाता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने महर्षि अंगिरा से पाशुपत योग की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की थी।

अमर उजाला
पुराने पन्नों से — 11, दिसंबर 1949

यरुशलम नहीं देंगे, इस्राइल के प्रधानमंत्री की चेतावनी

यरूसलम नहीं देंगे
इसरायल के प्रधानमंत्री की चेतावनी

इस्राइल के प्रधानमंत्री मुशिये बेन गुरियन ने कहा कि यरुशलम शहर को हम किसी भी सूरत में अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। यदि उस पर अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण करने की कोशिश की गई तो उससे पश्चिम एशिया में अशांति भड़क जाएगी।

सहारा रेगिस्तान जैसा तपता एशिया

रिकॉर्ड तोड़ गर्म महीनों का सिलसिला जारी रहा, तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले एशियाई लोगों के लिए जीवनयापन मुश्किल हो जाएगा।

सीमा जावेद

ग्लोबल वार्मिंग

इन दिनों झुलसा देने वाली गर्मी से जन-जीवन अस्त-व्यस्त है। देश के कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच रहा है। अमेरिकी गैर-लाभकारी संस्था बर्कले अर्थ के डाटा से पता चलता है कि मई, 2024 दुनिया के अब तक के इतिहास में सबसे गर्म मई है। इन दिनों पूरे उत्तर-पश्चिमी भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। दिल्ली, गुरुग्राम, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान इस सच्चाई को साफ बयान कर रहे हैं। लू लगने और गर्मी जनित बीमारियों की वजह से अस्पतालों के बाह्य रोगी विभाग में पहुंचने वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है।

पूरे एशिया में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। वर्ल्ड वेदर एट्रिब्यूशन ग्रुप के एक नए अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन ने अप्रैल-मई में पूरे एशिया में हीटवेव्स को बढ़ा दिया था, जिससे अरबों लोग प्रभावित हुए। अप्रैल-मई में, एशिया के कई क्षेत्रों में अब तक के

सबसे गर्म दिन दर्ज किए गए। म्यांमार, लाओस, वियतनाम और फिलीपीन में अभूतपूर्व उच्च तापमान देखा गया। भारत के कई हिस्सों में दोपहर का तापमान 46-48 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जबकि युद्धरत फलस्तीन और इस्राइल को भी 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गर्मी का सामना करना पड़ा है। जाहिर है, जलवायु परिवर्तन ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। रिकॉर्ड तोड़ गर्म महीनों का सिलसिला जारी रहा, तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले एशियाई लोगों के लिए जीवनयापन मुश्किल हो जाएगा। क्लाइमेट सेंट्रल ने कहा है कि भारत में 54.3 करोड़ लोगों को अप्रैल-मई के दौरान कम से कम एक दिन भीषण गर्मी का अनुभव होगा। साथ ही दिल्ली में तो गर्मी और लू कहर बरपा रही है। जर्मन वॉच द्वारा जारी 'ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स' यानी वैश्विक जलवायु संकट सूचकांक के अनुसार, भारत अत्यधिक गर्मी की मार झेल रहा है।

ग्लोबल क्लाइमेट शिफ्ट इंडेक्स (सीएसआई) के अनुसार, मई के दौरान जो गर्मी पड़ रही है, वह क्लाइमेट चेंज की वजह से सामान्य से तीन से छह डिग्री सेल्सियस अधिक है। यदि जलवायु परिवर्तन नहीं होता, तो तापमान तीन से छह डिग्री कम रहता।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) अपनी रिपोर्ट में बार-बार बता रहा है कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी नहीं आई, तो 50 साल के अंदर एक तिहाई इन्सानों पर 'लगभग असहनीय' गर्मी की मार पड़ेगी। *प्रोसिडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऐंड साइंसेज* जर्नल में कुछ साल पहले की गई यह भविष्यवाणी अब साफ तौर पर हकीकत में बदलती नजर आ रही है कि 'लगातार बढ़ते तापमान के कारण 3.5 अरब लोगों को उस आबोहवा से वंचित होना पड़ेगा, जिसका इन्सान पिछले 6,000 साल से आदी रहा है।' दुनिया की लगभग एक तिहाई आबादी को आशियाना देने वाला भूभाग (एशिया) ग्लोबल वार्मिंग के चलते सहारा क्षेत्र के सबसे गर्म हिस्सों जितना गर्म हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, अब अगर दुनिया के सभी देश अपनी वर्तमान उत्सर्जन-कटौती प्रतिज्ञाओं (एनडीसी) को पूरा कर भी लें, तो दुनिया इस शताब्दी में किसी न किसी समय ग्लोबल वार्मिंग के 2.5 और 2.9 डिग्री स्तर के बीच के तापमान तक पहुंच जाएगी। इन्सानी गतिविधियों ने जलवायु को इतना गर्म कर दिया है, जो कम से कम पिछले 2,000 वर्षों में सबसे अधिक है और पिछला दशक 125,000 वर्षों में से सबसे गर्म दशक था। धरती की गर्मी अपने में सोख कर समुद्र भी गर्म होकर उबल रहे हैं, विशेषकर हिंद महासागर। हिंद महासागर का तापमान अब तक की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। लगातार बढ़ने से इसकी सतह का तापमान साल भर 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहने का अनुमान है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि पहले हिंद महासागर में अत्यधिक गर्मी के हर साल 20 दिन होते थे, लेकिन बहुत जल्द ये दस गुना बढ़ जाएंगे। अब हर वर्ष अत्यधिक गर्मी के दिन 220 से 250 हो जाएंगे।

जाहिर है, धरती से लेकर समुद्र तक अत्यधिक गर्मी की मार झेल रहे हैं। भीषण गर्मी समाज के हर वर्ग को, हर जीव-जंतुओं के जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। हालांकि अलग-अलग लोगों और जीवों पर इसका असर अलग-अलग पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित समाज के गरीब और वंचित तबके के लोग होते हैं।

चिंतन

अत्यधिक गर्मी से बढ़ रहा स्वास्थ्य जोखिम

गर्मी नित नया रिकार्ड बना रही है। सामान्य से अधिक गर्मी धरती पर तापमान बढ़ने का संकेत दे रही है। गर्मी से केवल भारत ही पीड़ित नहीं है, बल्कि विश्व के अधिकांश क्षेत्र प्रभावित है। सुदूर उत्तर में जापान से लेकर सुदूर दक्षिण में फिलीपींस तक, गर्मी ने रोजमर्रा की जिंदगी पर कहर बरपाया है। कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिण-पश्चिमी अमेरिका, यूरोप में गर्मी बढ़ रही है। अंटार्कटिका में ग्लेशियरों के पिघलने की घटनाएं हो रही हैं। अत्यधिक गर्मी व लू के चलते लोगों की मौतें हो रही हैं। 1880 में वैश्विक रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से 2015 और 2023 की नौ साल की अवधि में औसत तापमान सबसे अधिक था। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे वैश्विक दक्षिण में अत्यधिक गर्मी के चलते वृद्धों पर स्वास्थ्य जोखिम अधिक रहेगा। गर्मी की लहरें वृद्धों के लिए घातक हैं। बढ़ती आबादी के साथ बढ़ते तापमान के चलते करोड़ों लोगों का जीवन जोखिम में है। ताजा अध्ययन के मुताबिक, अगर पृथ्वी बीमार हुई, तो उस पर रहने वाले जीव भी बीमार होंगे। पृथ्वी पर बढ़ते तापमान का मानव स्वास्थ्य पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। मच्छर जनित संक्रमण मलेरिया ने पिछले दशक के दौरान हर साल पांच लाख से अधिक लोगों की जान ली है। वैश्विक तापमान डेढ़ डिग्री तक कम करने को लेकर दुनिया संकल्पित है, इसके बावजूद भूराजनीति के चलते तापमान में कटौती की ओर सार्थक प्रयास बहुत धीमी है। अफ्रीका में मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं, फ्रांस में डेंगू के केस बढ़ रहे हैं, इटली नए किस्म के मलेरिया का नया ठिकाना बन रहा है, भारत में मलेरिया, डेंग व चिकुनगुनिया के मामले बढ़ रहे हैं। ताजा शोध से पता चलता है कि गर्म हो रही दुनिया में 20 से अधिक उष्णकटिबंधीय रोगों का खतरा बढ़ा है। शोध बताता है कि गर्मीजनित कुछेक बीमारियाँ इन्सानों के लिए अतिरिक्त पीड़ा लेकर आएंगी। इतना ही नहीं, जलवायु परिवर्तन कुछ मस्तिष्क स्थितियों के लक्षणों को बढ़ा रहा है। हमारे मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स में से प्रत्येक एक सीखने, अनुकूलन करने वाले कंप्यूटर की तरह है, जिसमें कई विद्युत सक्रिय घटक होते हैं। हमारा मस्तिष्क पहले से ही तापमान सीमा की हद के करीब काम कर रहा है, इसलिए तापमान में थोड़ी सी भी वृद्धि ब्रेन में केमिकल लोचा बढ़ा सकता है। आज पृथ्वी जिस तेजी से बीमार हो रही है, उसमें केवल अच्छा खानपान व व्यायाम अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी नहीं हैं, ऐसा बहुत कुछ है जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं हैं। तीन साल से भी कम समय के भीतर, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अंतरराष्ट्रीय चिंता की दो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित की हैंः फरवरी 2020 में कोविड-19 और जुलाई 2022 में मंकीपॉक्स। अत्यधिक गर्मी के चलते पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से बर्फ के नीचे छिपे रोगाणु मुक्त हो रहे हैं। मानव पर नए नए रोगों के प्रहार हो रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य की एक नई विश्वव्यापी अवधारणा की तत्काल आवश्यकता है। जीवन को आश्रय देने वाले एकमात्र ग्रह पृथ्वी पर बढ़ रहे तापमान में कमी लाने के संकल्प के साथ 'एक विश्व एक स्वास्थ्य' की अवधारणा पर दुनिया को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। सभी देशों के नीति निर्माता वाहनों, बिजली संयंत्रों और कारखानों में जीवाश्म ईंधन से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए काम करें और हरित ऊर्जा बपनाएं। ग्लोबल वार्मिंग को तत्काल नियंत्रित करना जरूरी है।

सारा संसार

जयपुर के करीब आभानेरी गांव में चांद बावड़ी बेहद सुंदर पर्यटक स्थल है। यहां आपको राजस्थानी वास्तुकला के 10 वीं शताब्दी के स्मारक देखने को मिल जाएंगे। चांद बावड़ी भारत के सबसे अनोखे कुओं में शामिल है।

आम चुनाव

बाल मुकुन्द ओझा

विश्लेषकों के दावों का दौर

देश के जाने माने चुनाव विश्लेषकों ने एक मत से यह स्वीकार किया है की आएगा तो मोदी ही। यह जरूर है कि इनके जीत के आंकड़े मोदी से मेल नहीं खाते। मोदी ने भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का नारा बुलंद किया था। चुनाव विश्लेषकों ने 370 या 400 पार को तो नहीं माना है मगर जीत मोदी की पक्की मान रहे हैं। इन चुनाव विश्लेषकों में मोदी विरोधी माने जाने वाले योगेंद्र यादव और प्रशांत किशोर भी शामिल है। योगेन्द्र यादव ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए लगभग 305 सीटें जीतेगा। प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की कि भाजपा लगभग 300 सीटें जीतेगी। स्वतंत्र चुनाव विश्लेषक प्रो संजय कुमार सरीखे भी मोदी की हैट्रिक को स्वीकार कर रहे है। लोकसभा चुनाव के छह चरण पूरे हो चुके है। सभी दल बचे हुए एक चरण के मतदान की तैयारियों में लग गए। हर दल अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। एनडीए और इंडिया के बीच नंबर युद्ध छिड़ गया है। दोनों और से जीत के बढ़ चढ़ कर दावे प्रतिदावे किये जा रहे है। एक तरफ राजग और भाजपा 400 पार का दावा कर रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन अपनी जीत का दावा कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा की एक रैली में बताया कि अब तक हुए चुनाव में ही पीएम मोदी 310 सीटों के आंकड़े को पार कर चुके हैं। आने वाले फेज में ये आकड़ा 400 के पार पहुंच जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे ने 300 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत का विश्वास व्यक्त किया है। इस समय समूची दुनिया की निगाह भारत के लोकसभा चुनाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैट्रिक पर केंद्रित हो रही है। चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की कमान संभाल रखी है। चुनाव की विधिवत घोषणा से पूर्व ही उन्होंने देशभर का दौरा शुरू कर दिया था। वे देश के विभिन्न भागों में एक दिन में तीन से चार रैलियां और रोड शो में शामिल हो रहे है। उनका चुनावी जज्बा एक नौजवान की तरह कायम है। 74 साल की उम्र में भी मोदी थके से नहीं लग रहे है और सम्पूर्ण ऊर्जा और उत्साह के साथ लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे है। आज यह कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं है कि अकेला मोदी सब पर भारी साबित हो रहा है। राजनीतिक समीक्षकों का कहना है मोदी ने अपनी ही पार्टी के सर्वाधिक मजबूत और कद्दावर नेता वाजपेयी और आडवाणी को लोकप्रियता के पैमाने पर पीछे छोड़ दिया है। 2014 में भाजपा को देश की सत्ता शक्ति के शिखर पर पहुंचाने के बाद मोदी का जादू अनवरत रूप से लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है और लोकप्रियता में पक्ष या विपक्ष का कोई भी नेता उनके आसपास भी नहीं है। मोदी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भारतीय राजनीति के लिहाज से 2024 का लोकसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस चुनाव पर दुनियाभर की निगाहें टिकी है। देश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद होने के साथ ही चुनाव प्रचार में तेजी देखने को मिल रही है। पक्ष और विपक्ष में घमासान छिड़ गया है। यह कहा जा रहा है वर्तमान चुनाव में अकेला मोदी सब पर भारी हो रहा है। जून 2013 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया। जहां कई लोगों ने पहले ही उन्हें प्रधानमंत्री मान लिया था। नरेंद्र मोदी ने 2014 में और फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली जीत का नेतृत्व किया।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

मंडेला की एएनसी पर संकट

द.अफ्रीका में आज चुनाव

विवेक शुक्ला

दक्षिण अफ्रीका और भारत सिर्फ गांधी जी और नेल्सन मंडेला के कारण ही आपस में भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ते। इन्हें करीब 15 लाख भारतवंशी भी जोड़ते हैं, जो वहां सौ से भी अधिक सालों से बसे हुए हैं। उसी दक्षिण अफ्रीका में 29 मई को होने वाले आम चुनावों को लेकर भारतवंशी भी गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। उनका आरोप है कि दक्षिण अफ्रीका में उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया है। भारतवंशियों की एक बड़ी आबादी एएनसी की समर्थक रही है। सबको पता है कि मंडेला का भारत से आत्मीय संबंध था। वे लंबी जेल यात्रा से रिहा होने के बाद 1990 में दिल्ली आए थे। वह उनकी जेल से रिहा होने के बाद पहली विदेश यात्रा थी।

दक्षिण अफ्रीका और भारत सिर्फ गांधी जी और नेल्सन मंडेला के कारण ही आपस में भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ते। इन्हें करीब 15 लाख भारतवंशी भी जोड़ते हैं, जो वहां सौ से भी अधिक सालों से बसे हुए हैं। उसी दक्षिण अफ्रीका में 29 मई को होने वाले आम चुनावों को लेकर भारतवंशी भी गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। उनका आरोप है कि दक्षिण अफ्रीका में उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया है। भारतीय मूल के कुछ राजनेता दक्षिण अफ्रीका में आम चुनाव लड़ भी रहे हैं। इनमें पैट्रिक पिल्ले शामिल हैं, जिन्होंने डेमोक्रेटिक लिबरल कांग्रेस (डीएलसी) नाम से पार्टी बनाई है। एस. सिंह विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक एलायंस के उम्मीदवार हैं। इनके अलावा भी कुछ निर्दलीय के रूप में क्वाजुलु-नटाल प्रांत से चुनाव लड़ रहे हैं। क्वाजुलु-नटाल प्रांत के प्रमुख शहर डरबन में भारतीयों की आबादी खासी है। इसे मिनी दिल्ली या मुंबई भी कहा जाता है। यह डरबन शहर ही है जहां महात्मा गांधी 1893 में भारत से आए थे। बाद में गांधी जी ने पास के शहर फ़ीनिक्स में अपना आश्रम बनाया था, उसे कुछ साल पहले हुई हिंसा में बुरी तरह से तबाह कर दिया गया था। डीएलसी ने चुनावों में भारतीय मूल के 10 उम्मीदवार उतारे हैं। वहां के भारतवंशी भी बेरोजगारी के शिकार हैं। माइनॉरिटी फ्रंट पार्टी की शमीन ठाकुर-राजबंसी दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुलु-नटाल प्रांत की विधानसभा की सदस्य हैं। वह भी अपने देश के भारतवंशियों के हक में सक्रिय रहती हैं। भारतीय मूल के तीन व्यक्ति, फसीहा हसन, मागेशवरी गोवेन्दर और शाएक इमरान सुब्रथी नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकन कांग्रेस पार्टी (एएनसी) के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।

दरअसल भारतवंशियों की एक बड़ी आबादी एएनसी की समर्थक रही है। सबको पता है कि मंडेला का भारत से आत्मीय संबंध था। वे लंबी जेल यात्रा से रिहा होने के बाद 1990 में दिल्ली आए थे। वह उनकी जेल से रिहा होने के बाद पहली विदेश यात्रा थी। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया। राजधानी दिल्ली में नेल्सन मंडेला मार्ग का होना इस बात की गवाही है कि सारा भारत मंडेला की कुर्बानियों से प्रेरित होता है। मंडेला 1995 में भी भारत आए थे। नेल्सन मंडेला के नाम पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में साल 2004 में नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की स्थापना की गई। इस सेंटर की स्थापना मुख्य रूप से इसलिए की गई थी ताकि दुनियाभर में शांति और सद्भाव के लिए भारत की तरफ से की जाने वाली कोशिशों का गहराई से अध्ययन हो सके। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी अफ्रीकन अध्ययन केन्द्र है।

दक्षिण अफ्रीका में होने वाले आम चुनाव को अमानवीय रंगभेद के अंत के खात्मे के बाद के सबसे महत्वपूर्ण आम चुनाव का दर्जा मिल सकता है। सत्तारूढ़ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (एएनसी) 1994 में सत्तासीन होने के बाद पहली बार बहुमत खो सकती है। अमेरिका के जार्जिया यूनिवर्सिटी में अफ्रीकी मामलों के प्रोफेसर डॉ. उत्सव कुमार सिंह को लगता है कि इस चुनाव के बाद वहां एएनसी का एकछत्र राज खत्म होगा। वहां मिली-जुली सरकार बनेगी। दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार के

शासन के अंत के बाद देश में सातवां आम चुनाव है। इस चुनाव में करीब पौने तीन करोड़ मतदाता देश की नई सरकार को चुनेंगे। अगर एएनसी को चुनावों में 50 फीसद से कम वोट मिले, तो पार्टी को गठबंधन सरकार बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उस हालत में एएनसी के नेता और राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को मिली-जुली सरकार बनाने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। बताते चलें कि वे 2019 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। एएनसी ने 2018 में राष्ट्रपति जैकब जुमा को हटाकर रामाफोसा को देश का राष्ट्रपति बनाया था। जैकब जुमा पर 2009 और 2018 के बीच राष्ट्रपति पद पर रहते हुए करप्शन के अनगिनत केस लगे थे। जुमा पर यह भी आरोप था कि उन्होंने भारत के उद्योगपति 'गुप्ता ब्रदर्स' (अनिल और अजय) को खूब लाभ पहुंचाया। उत्तराखंड पुलिस ने बीते दिनों एक बड़े बिल्डर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गुप्ता ब्रदर्स को गिरफ्तार किया था। बेशक एएनसी से अवाम की नाराजगी की वजह जुमा के कुशासन के कारण ही हुई थी।

बेशक एक दौर में एएनसी के प्रति दक्षिण अफ्रीका के अवाम के मन में गहरा प्रेम था मंडेला के कारण। एएनसी को पिछले 2019 के आम चुनाव में पहली बार झटका लगा था। उस समय भी उसे देश की 60 फीसद जनता का भी समर्थन नहीं मिला था। तब पार्टी को 57.50 फीसद वोट मिले थे।

दक्षिण अफ्रीका हत्याओं के मामले बीते 20 साल के उच्च स्तर पर है; देश में लगभग हर 20 मिनट में एक व्यक्ति का कत्ल हो जाता है। जनता पुलिस की काहिली से बहुत नाराज है। बेरोजगारी, बिजली की बार-बार कटौती, पानी के संकट के स्थायी हल ना खोज पाने के कारण जनता एएनसी से दूर हो रही है। सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार से एएनसी को नुकसान ही हुआ है। दक्षिण अफ्रीका की जनता राष्ट्रपति रामाफोसा में मंडेला का अक्स देखती थी, पर वे भी जनता के मसलों को हल करने में नाकाम ही रहे। उन्होंने कुछ समय पहले एक भाषण में स्वीकार किया था, 'भ्रष्टाचार ने हमारे लोकतंत्र को घायल कर दिया है और लोगों का हमारे संस्थानों में विश्वास हिला दिया है। अगर भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगाई जाती है, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। सबसे बड़ा नुकसान स्वयं लोकतंत्र में विश्वास के लिए होगा।'

दक्षिण अफ्रीका की मुख्य विपक्षी पार्टी, सेंट्रिस्ट डेमोक्रेटिक एलायंस (डीए), का नेतृत्व जॉन स्टीनहुइसन करते हैं और इसे कई लोग गोरे दक्षिण अफ्रीकियों की पार्टी मानते हैं। इस चुनाव के लिए, डीए ने छोटी विपक्षी पार्टियों के साथ एक गठबंधन ब्लॉक बनाया है। कहने वाले कह रहे हैं कि डीए सत्ता पर काबिज हो सकती है। अगर सर्वेक्षणों पर विश्वास किया जाए, तो एएनसी को जरूरत पड़ने पर इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स (ईएफएफ) या डीए के साथ गठबंधन बनाने के बीच चुनाव करना पड़ सकता है। डीए के नेता स्टीनहुइसन ने अपनी ओर से, एएनसी के साथ गठबंधन में जाने से इनकार नहीं किया है। यानी एएनसी और डीए भी मिलकर सरकार बना सकते हैं। ईएफएफ एक वामपंथी पार्टी है जिसका नेतृत्व एएनसी के पूर्व युवा नेता जूलियस मालेमा करते हैं।

खैर, भारत में लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को और मित्र देश दक्षिण अफ्रीका में 2 जून को घोषित किए जाएंगे। इसके बाद दोनों देशों में नई सरकारें बनेंगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका में नई सरकार भारतवंशियों के हितों के हल तलाश करेगी। भारतीयों के बिना अधूरा है दक्षिण अफ्रीका। वहां के शिखर क्रिकेटर हाशिम आमला और केशव महाराज भारतीय मूल के ही हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

कैसे चेतना को विस्तृत करता है योग?

संकलित

दर्शन

योग के आठ अंग हैं और उनमें से मात्र एक अंग है शारीरिक मुद्राएं या आसन। योग मात्र व्यायाम नहीं है, इसमें मुख्य बात मन की समरसता को बनाए रखना है। जब आप कोई भी कार्य सजगता से करते हैं, तब आप इस बात के प्रति सजग होते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। यही आपको योगी बनाता है। योग के प्रतिपादक पतंजलि ने बताया है कि योग का उद्देश्य दुख को आने से पहले ही दूर कर देना है। लालच, क्रोध, जलन, घृणा, निराशा आदि नकारात्मक भावनाओं को योग से मिटाया जा सकता है। जब आप खुश होते हैं, तब आप अपने भीतर एक विस्तार की भावना का अनुभव करते हैं। विफलता या अपमान की स्थिति में लगता है कि हमारे भीतर कुछ सिकुड़ गया है। इस पर ध्यान देना ही योग है, जिसका हमारे खुश हो जाने पर विस्तार होता है और जो हमारे दुखी हो जाने पर सिकुड़ जाता है। मन की इस स्थिति को परिवर्तित करने का रहस्य योग में है। यह आपको स्वतंत्र बनाता है। अपनी ही भावनाओं के द्वारा पीड़ित होने के बजाय आप जिस समय जैसा महसूस करना चाहते हैं, योग उसके लिए आपको शक्ति प्रदान करता है। योग निश्चित रूप से आपको अधिक जिम्मेदार बनाता है, क्योंकि योग से आपके भीतर ऊर्जा एवं उत्साह उत्पन्न होता है। आप तब जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, जब आप थके हुए और तनावग्रस्त होते हैं। यदि आपने अपनी थकान और तनाव को संभाल लिया, तब आप निश्चित रूप से अधिक जिम्मेदारी उठाएंगे।

गलत काम पूरे जीवन की तपस्या कर देता है बर्बाद

संकलित

प्रेरणा

प्रसंग के अनुसार एक दिन महावीर स्वामी प्रवचन दे रहे थे और सभी शिष्य सुन रहे थे। प्रवचन के बीच-बीच में कुछ शिष्य प्रश्न भी पूछ रहे थे और महावीर जी उनके उत्तर दे रहे थे। एक शिष्य ने पूछा कि व्यक्ति कब अपने आचरण से गिर जाता है? कौन से काम हैं, जिनकी वजह से पतन होता है? क्या कोई एक काम है या कई ऐसे काम हैं? महावीर स्वामी ने कहा कि मैं उत्तर दूं, उससे पहले यहां बैठे अन्य शिष्य इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्वामी जी की बात सुनकर एक शिष्य ने कहा कि अहंकार पतन का सबसे बड़ा कारण है। एक ने कहा कि कामवासना से सबकुछ बर्बाद हो जाता है। किसी ने लालच को बड़ी बुराई बताया तो किसी ने गुस्से को पतन का कारण बताया। महावीर जी ने सभी की बात ध्यान से सुनी। फिर पूछा कि बताइए अगर आपके पास एक कमंडल है, उसमें पानी भर दें और उसे नदी में छोड़ दें तो क्या वह डूबा जाएगा? शिष्यों ने कहा कि अगर कमंडल का आकार सही है तो वह डूबेगा नहीं, तैरेगा। महावीर जी ने पूछा कि अगर उसमें छेद कर दिया जाए तो? शिष्यों ने कहा कि फिर तो वह डूब ही जाएगा। महावीर जी बोले कि क्या छेद के आकार से कोई फर्क पड़ेगा? शिष्य बोले कि अगर छेद छोटा होगा तो कमंडल थोड़ी देर से डूबेगा और छेद बड़ा होगा तो जल्दी डूब जाएगा। छेद की वजह से कमंडल जरूर डूब जाएगा। महावीर जी ने कहा कि बस यही बात मैं समझाना चाहता हूं। हमारा शरीर एक कमंडल की तरह ही है और बुराइयां छेद की तरह होती हैं।

अंतर्मन

आज की पाती

मुफ्त की रेवड़ियां बांटना बंद करें सियासी दल

राजनीतिक पार्टियां मुफ्त की रेवड़ियां बाटना बंद करें। जो भी राजनीतिक पार्टी चुनाव के समय मुफ्त लाभ देने की घोषणा करती है, यदि वह चुनाव के बाद सत्तारूढ़ होती है तो जो उन्होंने मुफ्त में देने की कोई घोषणा की होती है, उस मुफ्त का लाभ सरकारी खजाने से न देकर अपने पार्टी फंड से देने की कोशिश करे, सरकारी खजाने में जो फंड आता है, वह लोगों के खून-पसीने की कमाई टैक्स के रूप में सरकारी खजाने में जमा होता है। उस फंड का सदुपयोग देश के विकास में होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों की यह मुफ्त की घोषणा लोगों को अपाहिज बना रही है। आज शिक्षा व स्वास्थ्य का लाभ सभी वर्गों के लिए निशुल्क होना चाहिए।

– प्रदीप चंद्राकर, सरायपाली

करंट अफेयर

स्पेन फलस्तीन राष्ट्र को मान्यता देगा

यूरोपीय संघ के इजराइल के साथ बढ़ते मतभेद के बीच स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि उनके देश का मंत्रिमंडल मंगलवार को बैठक में फलस्तीन राष्ट्र को मान्यता देगा। आयरलैंड और नॉर्वे भी बाद में फलस्तीन राष्ट्र को आधिकारिक तौर पर मान्यता देंगे। दर्जनों देशों ने फलस्तीन राष्ट्र को मान्यता दी है लेकिन किसी बड़े पश्चिमी देश ने ऐसा नहीं किया है। सांचेज ने मैड्रिड में प्रधानमंत्री आवास के द्वार पर खड़े होकर कहा, 'यह एक ऐतिहासिक फैसला है जिसका एकमात्र लक्ष्य है और यह लक्ष्य इजराइल और फलस्तीन के लोगों को शांति स्थापित करने में मदद करना है।' सांचेज के इस भाषण का टेलीविजन पर प्रसारण किया गया। समाजवादी नेता सांचेज ने पिछले सप्ताह संसद के समक्ष अपने देश के फैसले की घोषणा की थी। उन्होंने गाजा में संघर्ष विराम और मान्यता के लिए समर्थन जुटाने के मकसद से यूरोपीय और पश्चिम एशियाई देशों का दौरा किया था। यूरोपीय संघ के सदस्य आयरलैंड और स्पेन द्वारा फलस्तीन राष्ट्र को राजनयिक मान्यता देने की पूर्व संध्या पर यूरोपीय संघ और इजराइल के आपसी संबंध सोमवार को रसातल में पहुंच गए।

ऑफ बीट

अगर पृथ्वी बीमार हुई, तो आप भी बीमार हो जाएंगे

एक अधिक गर्म दुनिया के अधिक बीमार दुनिया होने की संभावना है। पृथ्वी पर बढ़ते तापमान का मानव स्वास्थ्य पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है, जैसे लू की लहरें जो हमारे शरीर विज्ञान की सहनशीलता से अधिक गर्म होती हैं। हालाँकि, विरासत में मिली स्थिर जलवायु से हटने के प्रभाव भी अपने आप में आश्चर्यजनक होंगे। उनमें से कुछ मौजूदा बीमारियाँ हो सकती हैं जो नई जगहों पर दिखाई दे रही हैं या अधिक तीव्रता से फैल रही हैं। और कुछ, विशेषज्ञों को डर है, पूरी तरह से नई बीमारियाँ हो सकती हैं। मच्छर जनित संक्रमण मलेरिया ने पिछले दशक के दौरान हर साल पांच लाख से अधिक लोगों की जान ले ली। इनमें से अधिकतर पीड़ित बच्चे थे और लगभग सभी (2022 में 95 प्रतिशत) अफ्रीका में थे। बीमारी के स्रोत के रूप में, संक्रामक मच्छरों को कम से कम तीन चीजों की आवश्यकता होती हैः गर्म तापमान, आर्द्र हवा और प्रजनन के लिए पोखर। तो वैश्विक तापमान से क्या फर्क पड़ेगा? परजीवी दूसरी जगहों तक जा सकते हैं। जल और स्वास्थ्य विशेषज्ञ मार्क स्मिथ और क्रिस थॉमस (लिंकन विश्वविद्यालय) कहते हैं, 'जलवायु और मलेरिया संचरण के बीच संबंध जटिल है और लगभग तीन दशकों से गहन अध्ययन का विषय रहा है।'

ट्रेंड

जनादेश पारदर्शी सरकार के साथ

एक ओर 12 लाख करोड़ रुपये के घोटाले करने वाले इंडी गठबंधन के नेता हैं, दूसरी तरफ 23 साल के राजनीतिक जीवन में जिन पर एक पैसे का आरोप नहीं है, ऐसे मोदी जी हैं। उत्तर प्रदेश की जनता का जनादेश ईमानदार और पारदर्शी सरकार के साथ रहने वाला है।

-अमित शाह, गृह मंत्री

खेल की भी जरूरत

मेरे दोस्त राष्ट्रपति थॉमस बाख को ओलंपिक में आपकी साझेदारी के लिए और डब्ल्यूएचए 77 के उद्घाटन में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। आपने सही कहा- सभी को स्वस्थ रखने के लिए, हमें सभी के लिए खेल की भी आवश्यकता है।

-डॉ टेड्रोस, डब्ल्यूएचओ महानिदेशक

अफ़सरों का तबादला क्यों

अभी जब चुनाव चल रहा है तो मोदी जी अफ़सरों का तबादला कर रहें है, किसी को विस्तार दे रहें है। जब आदर्श आचार संहिता है तो मोदी जी अफ़सरों के आदेश क्यों निकाल रहें हैं? क्या मोदी जी जाने से पहले, चुनाव के दौरान अफ़सरों का तबादला कर, उन पर कृपादृष्टि कर रहें हैं?

-मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष

गंगाजल से घर धोया

यूपी के पांच साल सीएम रहे अखिलेश यादव ने घर ख़ाली किया तो भाजपा ने गंगाजल से घर धोया। पत्नी के साथ कन्नौज के मंदिर में पूजा किया तो भाजपाइयों ने मंदिर को गंगाजल से धोया। पीडीए से नफ़रत करती है बीजेपी।

-संजय सिंह, आप सांसद

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।